23.3.2015/1400/ag/av/1

हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 23 मार्च, 2015 को माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 2.00 बजे अपराह्न आरम्भ हुई।

शोकोद्गार

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री सागर चन्द नैय्यर, पूर्व शिक्षा मंत्री एवं सदस्य हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्गार प्रस्तुत करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत दुःख हो रहा है कि पूर्व विधायक श्री सागर चन्द नैय्यर का 22 मार्च, 2015 को चम्बा में निधन हो गया। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

स्वर्गीय श्री सागर चन्द नैय्यर का जन्म 22 फरवरी, 1928 को चम्बा जिला में मुहल्ला मगोटु में हुआ था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर से स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की थी। स्वर्गीय श्री सागर चन्द नैय्यर ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे तत्कालीन चम्बा स्टेट के प्रजा मण्डल के सदस्य रहे। 1946 में चम्बा स्टेट में प्रथम सार्वजनिक सभा आयोजित की गई। वे 1953 में चम्बा नगर समिति के लिए चुने गए तथा 1977 के अंत तक क्रमशः इसमें उपाध्यक्ष व अध्यक्ष रहे। 1950 से 1972 तक जिला कांग्रेस समिति के कोषाध्यक्ष रहे तथा 1973 में हिमाचल प्रदेश लघु उद्योग तथा निर्यात निगम लिमिटिड के तीन वर्ष के लिए अध्यक्ष नियुक्त किये गये। दिसम्बर, 1978 में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी गिरफ्तार हुई उस समय चम्बा में सत्याग्रह किया तथा अन्य कार्यकर्ताओं सहित कारावास में रहे।

समितियों की कार्य प्रणाली में सुधार सम्बंधी परामर्श देने के लिए वे नगर समितियों की अध्यक्ष समिति के सभापति रहे। वे प्रदेश कांग्रेस समिति कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी रहे।

स्वर्गीय श्री सागर चन्द नैय्यर वर्ष 1982 में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। वे 14 मार्च, 1984 को राज्य मंत्री (तत्कालीन शिक्षा) नियुक्त किये गये। मार्च, 1985 में वे पुनः विधान सभा के सदस्य चुने गए तथा प्रदेश मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बनाये गये। उनकी बागवानी तथा सामाजिक कार्यों में विशेष रूचि थी।

23.3.2015/1400/ag/av/3

यह माननीय सदन स्वर्गीय श्री सागर चन्द नैय्यर जी द्वारा प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए यह माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता है।

समाप्त

अगला वक्ता श्री बी.जे.द्वारा जारी

23.3.2015/1405/negi/ag/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, इस बार जब यह सत्र शुरू हुआ था तब कोई शोकोद्गार नहीं था और एक बहुत संतोष था कि कोई ऐसी दुर्घटना नही घटी । लेकिन दुर्भाग्य से कल यह दुखद समाचार मिला कि वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री रहे, विधायक रहे, श्री सागर चन्द नैयर जी का देहान्त हुआ है । उनकी जीवनी से लगता है कि वह जन समस्याओं से लोगों के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने नगर की सेवा की, जिला की सेवा की और फिर प्रदेश स्तर पर दो बार विधायक रह कर और दो बार मंत्री रह कर सेवा की है । इससे पहले वह स्वतन्त्रता आन्दोलन में प्रजामण्डल में थे। मैं अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस सदमें को सहने की शक्ति दे।

समाप्त

23.3.2015/1405/negi/ag/2

अध्यक्षः अब श्रीमती आशा कुमारी जी शोकोद्गार प्रकट करेंगी।

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, आज मुख्य मंत्री महोदय ने यह दुखद समाचार इस मान्य सदन को बताया है । कल सुबह लगभग 11.00 बजे, सागर चन्द नैयर जी का देहान्त हुआ। चम्बा के लिए तो it is a passing of an era for the

Congress Party. He was a very-very simple and kind hearted person. अपने लम्बे राजनीतिक जीवन में उन्होंने चम्बा के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए। हालांकि वह विधायक दो बार ही रहे मगर कांग्रेस पार्टी और राजनीति के साथ वह स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में जुड़े रहे। उसके बाद वह म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष रहे । उनको फाइन आर्ट्स से बहुत ज्यादा लगाव था , खुद भी बहुत अच्छा गाते भी थे और चम्बा की संस्कृति को बढ़ावा देने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। सागर चन्द नैयर जी के परिवार में आपकी पुत्री भी ब्याही हुई है। सागर चन्द नैयर जी बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे । वह कांग्रेस पार्टी की वजह से तो हमारे साथ जुड़े हुए ही थे मगर जैसा माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सदन को सूचित किया बंगोटू मोहल्ले में उनका निवास स्थान है जो कि हमारे घर के साथ ही उनका घर है इसलिए उनके साथ हमारे पारिवारिक संबंध भी थे। हमेशा उन्होंने बहुत ही उच्च मूल्यों की राजनीति की है । घटिया राजनीति या औछापन उनके राजनीति में नहीं था। चम्बा के कल्चर के लिए, चम्बा की जो हमारी जितनी संस्कृति थी उसको बढ़ावा देने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। चम्बा में शिक्षा का विस्तार करने में न केवल बतौर शिक्षा मंत्री, बतौर इंडिविजुअल उनके अपने तौर से भी भारतीय पब्लिक स्कूल जो चम्बा में एक प्राइवेट सोसाइटी के ज़रिये चलता है उसकी स्थापना भी सागर चन्द नैयर जी ने करवायी थी ताकि लोगों को अच्छी शिक्षा, अंग्रेज़ी माध्यम की शिक्षा चम्बा शहर में भी मिल सके। उनके बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको हम आज याद करते हैं। And it is a loss to the Congress Party. It is a loss to the State, particularly, to Chamba. मैं मुख्य मंत्री महोदय ने जो शोकोद्गार रखे हैं उसमें अपने आपको शामिल करती हूं।

23.3.2015/1405/negi/ag/3

अध्यक्षः अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, ठाकुर कौल सिंह जी शोकोद्गार प्रकट करेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा मुख्य मंत्री महोदय जी ने कहा, श्री सागर चन्द नैयर का हिमाचल की राजनीति में बहुत ही महत्व रहा है । उनका जो स्वर्गवास हुआ है उससे हिमाचल की राजीनति को बहुत ही नुकसान हुआ है । सागर चन्द नैयर जी का व्यक्तित्व एक साधारण राजनीतिज्ञ के रूप में रहा

है । मेरे तो वह व्यक्तिगत तौर पर वह बहुत अच्छे मित्र थे। 1982 में पहली बार वह विधान सभा में आए थे । जैसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, 1984 में वह राज्य के तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री बने और उन्होंने उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है । 1985 में...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

23.03.2015/1410/यूके /जेटी/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री---जारी ----

1985 में जब वे दोबारा जीत कर आए तो सरकार के शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया और, जैसे श्रीमती आशा कुमारी जी ने कहा उनका बहुत अच्छा योगदान रहा है । एक राजनीतिज्ञ के रूप में, एक साधारण व्यक्ति के रूप में और सिम्पलीसिटी के लिए और चम्बा के कल्चर के उभारने के लिए अध्यक्ष महोदय, उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता । जब भी हम कभी बैठते थे और कहते थे कि नैयर साहब, गाना हो जाए तो बहुत अच्छे गाने वे गाया करते थे और खास तौर से "सांय-सांय राविए " उनका गाना बहुत मशहूर था । वे सबका दिल लगाए रखते थे । मेरी मुलाकात उनसे सन् 1980 में हुई जब मैं चम्बा में पहली बार गया । वे मुझे अपने घर ले गए । He was known for his hospitality and courtesy, as you are known for that, Sir. इसलिए अध्यक्ष महोदय, उनका इस सत्र के बीच में चले जाना बहुत ही दुखदायी रहा है और जैसे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सारा सदन उनके परिवार के साथ है । जब-जब भी मैं चम्बा जाता था, वे हमेशा मुझे अपने घर जरूर बुलाते थे, कभी लंच पर, कभी डिनर पर और हम काफी देर तक बैठ कर बातें करते थे । अध्यक्ष महोदय, यह संसार ही ऐसा है कि जो इस दुनिया में आया है, उसे एक न एक दिन जाना पड़ता है । लेकिन उनके निधन से हिमाचल की राजनीति में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है ।

अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि श्री सागर चन्द नैयर जी की आत्मा को स्वर्ग में शांति मिले तथा उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे । ऐसे

23.03.2015/1410/यूके /जेटी/2

राजनैतिक नेता इस समाज में आते रहें । वे बहुत ही ईमानदार थे और अपने विभाग पर उनकी पूरी पकड़ होती थी । जब भी उनके पास कोई काम लेकर जाते थे, क्योंकि हम दोनों मंत्री इकट्ठे रहे हैं, तो कभी काम को इन्कार नहीं करते थे । कोई न कोई तरीका निकालते थे कि किस तरह उस काम को किया जाए । धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय ।

23.03.2015/1410/यूके /जेटी/3

अध्यक्षः अब श्री बी0के0 चौहान जी, अपने शोकोद्गार व्यक्त करेंगे ।

श्री बी0के0 चौहान : अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वर्गीय श्री सागर चन्द नैयर जी के दुखद निधन पर मैं अपने कुछ उद्गार व्यक्त करना चाहूंगा । सागर चन्द नैयर जी के निधन से केवल हिमाचल को ही नहीं विशेषकर के चम्बा के लिए एक अपूर्णीय क्षति हुई है । सागर चन्द नैयर जी का जन्म 22 फरवरी, 1928 में हुआ था । इन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी । उसके बाद ये प्रजामंडल के सदस्य बने और प्रजामंडल के माध्यम से इन्होंने स्वतन्त्रता संघर्ष में भी भाग लिया । इसके बाद ये सन् 1973 में स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपारेरेशन के अध्यक्ष के रूप में रहे । उसके बाद ये म्युनिसिपल कमेटी चम्बा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष भी रहे । कांग्रेस पार्टी में सक्रिय सदस्य एवं सक्रिय राजनीतिज्ञ होने के कारण इन्होंने वर्ष 1982 में पहला चुनाव जीता और 1984 से ये तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री रहे और 1985 से 90 तक हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने चम्बा के लिए

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

23.03.2015/1415/sls-jt-1

श्री बी0 के0 चौहान ...जारी

हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने चम्बा के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया क्योंकि चम्बा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ रहा है। उनके द्वारा स्कूलों का काफी विस्तार हुआ और चम्बा में शिक्षा का प्रचार-प्रसार बहुत ही सघन तरीके से हुआ। वे स्वभाव से बहुत ही मृदुभाषी और हंसमुख थे। जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने कहा,

वे जहां भी जाते थे वहां महफिल जमाते थे क्योंकि पठन-पाठन और संगीत में उनकी बहुत रुचि थी। विशेषकर पहाड़ी संगीत और चम्बा के गाने वे अक्सर गाया और गुनगुनाया करते थे। कल 22 मार्च, 2015 को उनका देहांत हुआ और चम्बा शहर में एक सनसनी फैल गई। मैं चम्बा से शिमला आ रहा था तो रास्ते में 11.00 बजे के समाचार में मैंने उनके देहांत के बारे में ख़बर सुनी। क्योंकि ये उस तरह के राजनीतिज्ञ नहीं थे जो दलगत राजनीति में विश्वास करते हों, इसलिए उनका सभी समुदायों और सभी राजनीतिक दलों से बड़ा मधुर संबंध था। वे अक्सर हमारे घर पहले से ही आया-जाया करते थे क्योंकि मेरे पिता जी से उनकी दोस्ती थी। उनके पीछे अब उनके दो पुत्र हैं जिनमें से एक अमेरिका में रहते हैं और एक चम्बा में हैं।

मैं परमात्मा से इस दुःख की घड़ी में उनकी पत्नी एवं परिवार के अन्य सदस्यों को इस दुःख को सहने की ताकत देने की प्रार्थना करता हूं। साथ ही दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हूं।

समाप्त

23.03.2015/1415/sls-jt-2

श्रीमती विद्या स्टोक्स : अध्यक्ष महोदय, मैं दिवंगत श्री सागर चंद नैय्यर, पूर्व विधान सभा सदस्य एवं पूर्व शिक्षा मंत्री, जिनका निधन 22 मार्च, 2015 को सुबह 10.30 बजे चम्बा में उनके पैतृक निवास पर हुआ, को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़ी हुई हूं।

आज सुबह जब मुझे यह पता चला तो मुझे बहुत सदमा पहुंचा। उनके इस तरह अकस्मात निधन के बारे में मैं सोच ही नहीं सकती थी। वह बड़े सुलझे हुए व्यक्ति थे और अपने साथियों का भी बड़ा ध्यान रखते थे। उनकी आदत थी कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, वह सबका ध्यान रखते थे। बहुत अर्से से मैं उनसे मिल नहीं सकी क्योंकि चम्बा नहीं जा सकी। उनकी आयु लगभग 88 वर्ष थी। मैं उनके प्रति प्रकट किए गए शोकोद्गार में अपने आपको सम्मिलित करती हूं।

अध्यक्ष महोदय, दिवंगत सागर चंद नैय्यर जी का जन्म 21 फरबरी, 1927 को मोहल्ला भंगोटू , जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। श्री नैयर जी ने पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर से स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की। उन्हें बागवानी का भी

बहुत शौक था। बागवानी पर उन्होंने बहुत काम किया और वे समाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखते थे। ऐसे सुलझे व्यक्ति के देहांत से आज मुझे बड़ा धक्का लगा है। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह बड़े सहनशील व्यक्ति थे जिन्हें देखकर हमेशा बड़ी खुशी होती थी। उन्हें हर तरह से हर बात में सहनशील रहने का अभ्यास था। स्वर्गीय श्री नैय्यर जी स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल रहे और उन्होंने इसमें सक्रिय भाग लिया। तत्कालीन चम्बा स्टेट के लिए उन्होंने प्रथम् सार्वजनिक सभा आयोजित की थी। वर्ष 1953 में वह चम्बा नगर समिति हेतु चुने गए तथा 1977 तक क्रमशः इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रहे।

जारी..श्री गर्ग

23/03/2015/1420/RG/AG/1

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री-----क्रमागत

क्रमशः इसमें उपाध्यक्ष व अध्यक्ष भी रहे। ऐसे अच्छे स्वभाव के व्यक्ति मैंने बहुत कम देखे हैं, जैसे वे थे। मैंने उन्हें कभी नाराज़ नहीं देखा, वे हमेशा मुसकराते ही रहते थे।

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री सागर चन्द नैयर वर्ष 1950 से 1972 तक जिला कांग्रेस समिति के कोषाध्यक्ष रहे तथा वर्ष 1973 में हिमाचल प्रदेश लघु उद्योग तथा निर्यात निगम लिमिटेड में तीन वर्ष के लिए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। वर्ष 1978 में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी जी गिरफ्तार हुईं, जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था, तो उस समय उन्होंने सत्याग्रह किया तथा अन्य कार्यकर्ताओं सहित कारावास में भी रहे। वे हमेशा हिम्मत रखते थे और सोचते थे कि हमें अपने-अपने कामों को पूरी तरह अन्ज़ाम देना है और अपनी पार्टी के लिए उनके दिल में बहुत भावना थी। आज नगर समिति की कार्य-प्रणाली में सुधार संबंधी परामर्श देने हेतु वे नगर समितियों के अध्यक्ष भी रहे और प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी रहे।

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री सागर चन्द नैयर वर्ष 1982 में विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए और 14 मार्च, 1984 को राज्य मंत्री (तकनीकी शिक्षा) नियुक्त किए गए। वे एक शिक्षित व्यक्ति थे और सभी के साथ बहुत मान-सम्मान रखते थे। वे मार्च, 1985 में चम्बा निर्वाचन क्षेत्र से पुनः विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए तथा मंत्रि-मण्डल में शिक्षा मंत्री के रूप में सम्मिलित हुए। मैं समझती हूं कि उन्होंने अपनी

जिन्दगी बहुत ही सुन्दर तरीके से गुज़ारी। उनका परिवार भी बहुत अच्छा है और उनका आपस में बहुत प्यार एवं सद्भावना है। उनके पुत्र एवं पत्नी को देखकर मुझे बहुत ही दुःख हुआ। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दिवंगत आत्मा को वे शांति प्रदान करे और उनके परिवारजन को इस असहनीय क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करे। जब ऐसी स्थिति होती है, तो हर परिवार को ऐसा समय देखना पड़ता है और परिवार के हर व्यक्ति को बहुत दुःख होता है। मैं इस बात के लिए क्षमा चाहती हूं कि हम उनके लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सके और वहां जा नहीं सके। आगे यदि समय हुआ, तो मैं चाहूंगी कि उनके परिवार के बीच अवश्य जाकर मिलूं। मेरे दिल में उनके प्रति बहुत मान-सम्मान है। आज हमारे बीच से एक ऐसा व्यक्ति चला गया है जो हम सोच ही नहीं सकते थे।

समाप्त

-/2

23/03/2015/1420/RG/AG/2

अध्यक्ष : अब श्री सुधीर शर्मा, माननीय शहरी विकास मंत्री अपने शोकोद्गार व्यक्त करेंगे।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज जो शोकोद्गार माननीय मुख्य मंत्री जी ने श्री सागर चन्द नैयर, पूर्व मंत्री के निधन पर व्यक्त किए हैं, मैं अपने आपको उसमें शामिल करना चाहूंगा। जैसाकि उससे पहले बहुत लोगों ने उनके जीवन के बारे में परिचय दिया है। जब वे दो बार वर्ष 1982 एवं वर्ष 1985 में विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए और मंत्री पद पर रहे, तो उन्हें एक नंबर मकान याट्स प्लेस पर आबंटित हुआ। उस समय मेरे स्वर्गीय पिता जी भी मंत्री होते थे और मैं बहुत छोटा था। इसलिए मुझे भी उनके पड़ोस में रहने का मौका मिला। उनके जो छोटे सुपुत्र नीरज नैयर हैं, उनके साथ बचपन में मेरी मित्रता रही है। मैंने बहुत करीब से उनको और उनके परिवार को देखा है और ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वे कोई राजनीतिज्ञ हैं। मैंने उन्हें कभी गुस्सा करते नहीं देखा। वे बहुत ही शांत स्वभाव के थे और जो भी उनसे मिलने आता था, बहुत प्यार से उससे वे मिला करते थे। जैसा कहा गया कि उनके अंदर मेहमान-नवाज़ी का जज़बा बहुत था। न केवल उनमें बल्कि उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चंचल नैयर में भी यह जज़बा था। परिवार में दोनों की जोड़ी ईश्वर ने ऐसी बनाई थी कि कभी उनके घर से मैंने किसी को निराश होकर जाते

नहीं देखा। जिस तरह से यहां कहा गया कि संगीत के प्रति उनका बहुत प्रेम था। जब भी उनके घर किसी भोज का आयोजन या कोई अन्य कार्यक्रम होता था, तो वे स्वयं हारमोनियम निकालकर बैठ जाते थे। वे हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते थे और गाते भी बहुत अच्छा थे। तो ये सारी यादें हैं--------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

23/03/2015/1425/MS/AG/1

शहरी विकास मंत्री जारी----------

तो ये सारी-की-सारी बातें उनके निधन पर आज जब यहां कही जा रहीं हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे कल की बात हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनका परिवार जो पीछे छूटा है, जिसमें उनके दो बेटे हैं, जिनमें से एक अमेरिका में है और एक यहीं पर मार्किटिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं तथा उनकी धर्मपत्नी है, उनको इस असहनीय दुःख व क्षति को सहने की क्षमता दे। धन्यवाद।

23/03/2015/1425/MS/AG/2

अध्यक्षः परिवहन मंत्री जी भी अपने शोकोद्गार व्यक्त करना चाहते हैं।

परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, श्री सागर चन्द नैय्यर, पूर्व शिक्षा मंत्री एवं सदस्य विधान सभा, जिनका निधन कल 22 मार्च, 2015 को तकरीबन 11.00 बजे चम्बा में हुआ, इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी जो शोकोद्गार प्रस्ताव लाए हैं, उसमें मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं।

अध्यक्ष जी, मुझे भी सागर चन्द जी को नजदीक से जानने का मौका मिला था। वह बड़े ही सरल और शांतिप्रिय स्वभाव के व्यक्ति थे। जब वह शिक्षा मंत्री बने तो मुझे कई बार उनसे मुलाकात करने का मौका मिला। वह आते-जाते कई बार मेरे पास रूकते भी थे। वह हर समस्या को हल करने का प्रयास करते थे और कोई-न-कोई समाधान निकालने का प्रयास करते थे। उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी थी। जैसे

आशा कुमारी जी ने भी कहा कि चम्बा में और हिमाचल की राजनीति में उनका अपना एक स्थान था। भले ही वह दो बार ही विधायक बने लेकिन राजनीति में लम्बे समय तक रहे। वर्ष 1978 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी गिरफ्तार हुई, उस समय वह चम्बा में सत्याग्रह में अग्रणी थे। जैसे सुधीर जी ने बताया कि उनके एक सुपुत्र अमेरिका में है और दूसरे यहां है। जो अमेरिका वाले उनके सुपुत्र हैं उनसे मिलने का मुझे दो-तीन बार अपने परिवार सहित मौका मिला है। अध्यक्ष जी, सागर चन्द जी सबसे बहुत स्नेह रखते थे। चम्बा में जब हम जाते थे तो सभी को किसी-न-किसी बहाने वह अपने घर लेकर जाना चाहते थे और लेकर जाते भी थे। उन्होंने इस प्रदेश के लिए जो योगदान दिए हैं, उसकी हम सब सराहना करते हैं। इस सदन ने दिवंगत आत्मा के प्रति जो अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, उनमें मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं।

अन्त में अध्यक्ष जी, मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके परिवारजनों को इस असहनीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इसी के साथ अध्यक्ष जी, आपने बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद।

23/03/2015/1425/MS/AG/3

अध्यक्षः स्वर्गीय श्री सागर चन्द नैय्यर, पूर्व सदस्य के निधन पर जो उल्लेख सदन में प्रस्तुत किए गए हैं, उसमें मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं तथा शोक-संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। इस माननीय सदन की भावनाओं को शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचा दिया जाएगा।

अब में सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे दिवंगत आत्मा को श्रद्धा-सुमन अर्पित करने के लिए अपने-अपने स्थान पर कुछ क्षण के लिए मौन खड़े हो जाएं।

(सभा मण्डप में उपस्थित सभी अपने-अपने स्थान पर कुछ क्षण के लिए मौन खड़े हुए)

प्रश्नकाल आरंभ श्री जे0के0 द्वारा------

23.3.2015/1430/जेके/जेटी/1

प्रश्नकाल आरम्भ

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्याः 1355

अध्यक्षः अब प्रश्नकाल के बचे हुए समय में प्रश्न पूछे जाएंगे। डॉ राजीव बिन्दल।

डॉ0 राजीव बिन्दलः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभा पटल पर रखी है उसके अनुसार 90 विभागों में 1616 लोगों को सेवा विस्तार या पुनर्नियुक्ति दी गई और जिस पर 6,93,53,197/-रूपये व्यय किये गए। अगर यह सेवा विस्तार न दे करके गवर्नमैंट की जो अनुबन्ध पॉलिसी है उसी के ऊपर इतने लोग भर्ती किये जाते तो शायद 2 करोड़ रूपये में इतना ही काम होता और इससे लगभग 5 करोड़ रूपये का नुकसान सरकार को हुआ। जिन सैंकड़ों लोगों ने प्रोमोशन प्राप्त करनी थी उनकी प्रोमोशन रुक गई। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या एक्सटैंक्शन और री-इम्प्लॉयमैंट के लिए सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है? क्या यह सेवा विस्तार उस पॉलिसी के अनुसार दिया गया? यदि कोई ऐसी पॉलिसी है तो कृपया उसको सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

दूसरे, सेवा विस्तार देने के लिए पिक एण्ड चूज़ पॉलिसी क्यों अडॉप्ट की गई? माननीय मुख्य मंत्री जी, पुलिस विभाग में 41 लोगों को सेवा विस्तार दिया। मेरा प्रश्न यह भी है कि जो कॉर्पोरेशन भारी घाटे में चल रही थी उनमें भी सेवा विस्तार दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभागीय उत्तर के 82वें नम्बर पर लिखा गया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य बोर्ड समिति। यह मालूम नहीं है कि कौन सा बोर्ड है, जिसमें 209 लोगों को सेवा विस्तार दिया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह पिक एण्ड चूज़ क्यों किया गया, कौन सी ऐसी मज़बूरी थी? इन लोगों के पास कौन सी ऐसी विशेषज्ञता थी कि इनके बिना सरकार चल नहीं सकती थी?

23.3.2015/1430/जेके/जेटी/2

तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि इस विभागीय उत्तर में अनेक कार्पोरेशन्ज, नगर पालिकाएं और विधान सभा भी शामिल हैं, जिनमें दिए गए सेवा विस्तार का जिक्र नहीं है। इन तीन प्रश्नों का कृपया उत्तर दें उसके बाद मैं सप्लीमेंटरी पूछता हूं।
मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जिन-जिन लोगों को जिन-जिन विभागों में सेवा विस्तार दिया गया है उनकी सूची यहां पर दी गई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार के मूल नियम फंडामैंटल रूल 56 में यह प्रावधान पहले से ही निहित है कि 58 वर्ष की आयु पूरा करने पर सक्षम अधिकारी यानि अप्वाइटिंग अथोरिटी सेवा विस्तार दे सकता है, बशर्ते वह सेवा विस्तार लोकहित में हो तथा तथ्य लिखित में दिए हों। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कर्मियों द्वारा 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवा विस्तार प्रदान किया जाए। जिसके लिए मूल नियम 56 में वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2014 द्वारा संशोधन किया गया। जिसके अनुसार कर्मचारियों को विकल्प देने का प्रावधान है। कर्मचारी 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर एक वर्ष की सेवा विस्तार हेतु सेवानिवृत्त की आयु 58 वर्ष पूर्ण करने के छः माह पहले अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। कर्मचारी द्वारा दिया गया विकल्प अन्तिम माना जाता है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी--------

23.03.2015/1435/SS-JT/1

प्रश्न संख्याः 1355 क्रमागत

मुख्य मंत्री क्रमागतः
कर्मचारी द्वारा दिया गया विकल्प अंतिम माना जाता है तथा उसको किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया जा सकता। हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने अपने पत्र दिनांक 2.2.1983 तथा 22.10.1998 द्वारा स्पष्ट किया है कि सेवा विस्तार बहुत विशेष परिस्थितियों व लोक हित में प्रदान किया जा सकता है। वे निम्न कारण दिए गए हैंः-

1. अन्य अधिकारी जोब हेतु उपलब्ध न हो।
2. सेवानिवृत्त अधिकारी उच्च मैरिट का हो।

3. जहां पर सेवानिवृत्त अधिकारी या कर्मचारी की सेवा दो से तीन माह तक कम हो। ऐसे एवं पैंशन प्राप्त करने के लिए 6 माह की अवधि पूर्ण कर सकें।

दिए गए सेवा-विस्तार व पुनर्नियुक्ति तथा प्रतिमास वेतन व भत्ते का विवरणः-

सेवा-विस्तार 1454, पुनर्नियुक्ति 162, कुल 1616.

वेतन पर प्रतिमास खर्च 3,86,37,418/- और भत्तों पर प्रतिमास खर्च - 3,47,15,779/-. कुल खर्च -6,95,53,197/-

मैंने विस्तार में अपने जवाब में ब्योरा दिया है उसका मैंने ये एक्सट्रैक्ट निकाल कर आपको दिया है। It is the prerogative of the Government to give extension where and when it is necessary. मगर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को इस बार सेवा में विस्तार दिया है आने वाले 31 मार्च को ये सारे खत्म कर दिए जायेंगे और अगर हम समझते हैं कि किसी को रखना प्रशासन के लिए ज़रूरी है उनको छोड़कर बाकी सब का एक्सटेंशन खत्म कर दिया जायेगा।

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने काफी विस्तार में उत्तर देने की कोशिश की है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि सेवा-विस्तार और पुनर्नियुक्ति, इन दो कैटेगिरीज़ को भरने की क्या आवश्यकता पड़ी?

नम्बर-2, जो आपने सूचना दी है कि 1616 लोगों को सेवा-विस्तार दिया है या पुनर्नियुक्ति दी हुई है उसमें हैरानी वाली बात यह है कि उनका जो वेतन है वह

3,44,37,418/- है। उनके जो मानदेय/भत्ते हैं वे 3 करोड़ 48 लाख के लगभग हैं। इन मानदेय, भत्तों के अलावा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि उनको मकान दिए गए हैं। मकान के अलावा उनको स्टाफ दिया गया। स्टाफ के अलावा उनको गाड़ियां दी गईं। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस पूरी सूचना को सदन के बीच में रखेंगे कि इनकी गाड़ियों के ऊपर, इनके स्टाफ के ऊपर, इनके घरों के ऊपर और उन घरों में जो बिजली जलती है उनके ऊपर आज तक कितना-कितना खर्च हुआ है?

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि जैसे मैंने कहा कि सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति की क्या आवश्यकता पड़ी, क्या उनके पीछे जो सैकिण्ड लाइन है क्या वे उतनी योग्यता नहीं रखते थे कि उनको प्रॅमोट कर दिया जाता ताकि प्रॅमोशन होने के उपरांत वे उसका फायदा भी उठाते? ऐसे कितने अधिकारी और कर्मचारी इस प्रदेश के अंदर विभिन्न विभागों, बोर्डों,

निगमों और अथोरिटीज़ में हैं जो अपनी प्रॅमोशन से वंचित हुए? क्या माननीय मुख्य मंत्री जी, इसका उत्तर दे पायेंगे?

तीसरा, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं ..

जारी श्रीमती के0एस0

23.03.2015/1440/केएस/एजी/1

श्री महेन्द्र सिंह जारी---

तीसरे अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 11 लाख बेरोज़गारों की एक बहुत लम्बी लाईन इस प्रदेश के अन्दर खड़ी है। वह इन्तज़ार में है कि अगर कोई रिटायर होगा तो शायद उनका नम्बर लग सके। एक सर्वेयर से ले कर, जे.ई. और एस.डी.ओ. से लेकर सभी एक स्टैप आगे बढ़ेंगें उसकी वजह से जो बेरोज़गारों को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कैसे और कौन करेगा?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, बहुत से लोग सेवानिवृत्त होते हैं। सभी को सेवा विस्तार नहीं दिया गया। जिनको आवश्यक समझा गया in the contingency of service and better running of the Government उनको रखा गया है और भविष्य में भी अगर किसी की आवश्यकता होगी तो उनको रखा जाएगा मगर जिनको अभी सेवा विस्तार दिया गया है, except for some people may be if it is necessary to continue them or so in the interest of the State तो उनको छोड़कर सभी का, जिनको सेवा-विस्तार दिया गया था, 31 मार्च, 2015 को उनका सेवा-विस्तार समाप्त कर दिया जाएगा।

श्री रविन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे माननीय सदस्यों का प्रश्न है और जो इन्होंने अनुपूरक प्रश्न किए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उनका जवाब नहीं दिया। आपने जो नोटिफिकेशन है, और जो रूल्ज़ आपने बनाए, जो अमैंडमैंट आपने की, वह आपने पढ़ कर सुना दिया। एक साल में जो 1616 की आपने पुनर्नियुक्ति की या सेवाविस्तार दिया, उनको सेवा विस्तार देने के बाद जो प्रोमोशन की लाइन में थे, जैसे कि ठाकुर

23.03.2015/1440/केएस/एजी/2

महेन्द्र सिंह जी ने पूछा, जो लाइन में थे, जिनकी प्रोमोशन होनी थी, वे उससे वंचित रह गए, वे कितने हैं? क्या जो एक साल पीछे रह गए उसके ऊपर सरकार विचार करेगी और पीछे से जबसे उनका हक बनता है, उस समय से उनको प्रोमोशन दी जाएगी?

दूसरे, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने विशेष परिस्थिति की बात की, मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं कि अभी क्योंकि आज आपने शायद केबिनैट में निर्णय लिया होगा लेकिन कई लोग जो जनवरी में रिटायर हो गए, 28 फरवरी को रिटायर हो गए वे 15-15 दिन यहां सचिवालय में बैठे रहे। यहां से चिट्ठियां ले कर गए । सभी विभागाध्यक्षों ने या जो आपके यहां पर अधिकारी हैं, इन्होनें लिखकर दे दिया कि जो सरकार का निर्णय होगा उसके अनुसार आपको बता दिया जाएगा, आप अपना काम करते रहिए। तो जो उनका गैप पड़ा, एक तो वे यहां आकर 10-15 दिन बैठे रहे और वहां उनकी अफ्सैंट लगी और बाद में यहां पर एच.ओ.डी. ने लिखकर दे दिया कि आप इसकी कंटिन्युटी में वहां पर इनको सैलरी भी दे दो। यहां से सभी को चिट्ठियां गई हैं। क्या मुख्य मंत्री जी, आप उनकी जो चिट्ठियां गई हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगें, उनकी जांच पड़ताल करेंगें? कितने लोग पूरे प्रदेश में पिछले तीन-चार महीने में ऐसे हैं और क्या उस गैप को पूरा करेंगें?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सेवा में विस्तार देना कोई नई बात नहीं है। जितनी भी सरकारें हिमाचल प्रदेश में या अन्य प्रदेशों में हुई हैं, सेवा विस्तार एक सम्मानित प्रक्रिया है और जहां-जहां सरकार समझती है कि किसी विभाग में मौजूदा ऑफिसर को सेवा विस्तार दिया जाना चाहिए,

23.03.2015/1440/केएस/एजी/3

किन्हीं कारणों से सरकार वहां पर यह कदम उठाती है। यह नहीं है कि सेवा विस्तार सिर्फ सचिवालय में ही हुआ है। It is in all branches of administration everywhere. तो यह कोई सचिवालय की ही बात नहीं है। मैं यह मानता हूं कि पीछे जो सेवा विस्तार हुआ है यह हमने सीमित समय के लिए किया था और उसको 31 मार्च, 2015 को खत्म कर दिया जाएगा except where Government feels that

extension should continue in public interest. और बाकी जो आपने बातें कही है it is suggestion for action.

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में अभी बताया कि कहीं पर अधिकारी उपलब्ध न हो या अधिकारी बहुत बड़ी मैरिट का हो तभी उसको सेवा-विस्तार दिया जाना चाहिए, ऐसा रूल्ज़ में प्रावधान है। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनके नीचे के सारे ही अधिकारी अक्षम थे और जिनको सेवा विस्तार दिया, केवल वे ही सक्षम थे? आपने पुलिस में 41 भर्ती किए तो इसका मतलब उनके पीछे कोई सक्षम नहीं था? उच्च शिक्षा में 73 दिए तो उनके पीछे क्या कोई सक्षम नहीं था? मैंने जानना चाहा था कि 209 इस कॉर्पोरेशन में आपने और दिए, यह कौन सा बोर्ड है?

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

23.3.2015/1445/ag/av/1

प्रश्न संख्या : 1355-----क्रमागत

डॉ.राजीव बिन्दल जारी--------
आपने और दिए। यह कौन सा बोर्ड है जिसमें आपने 209 लोगों को सेवा विस्तार दिया और जिसमें अभी कार्पोरेशन के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। उसके लिए सरकार से हर साल ग्रांट दी जाती है। ऐसी निगमों के अंदर भी ऐक्सटैनशन दी गई तो ऐसी क्या मजबूरी थी? हम यह कहना चाहते हैं कि सरकार ने योजनापूर्वक पिक एण्ड चूज करके लोगों को सेवा विस्तार दिया। हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या उनको कोई ऐसे काम करवाने के लिए सेवा विस्तार दिया गया कि जिसमें वे सरकार की मन्शा को पूरा कर सके?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनके समय में ऐसा होता होगा और शायद माननीय सदस्य यहां अपनी मनोवृति को जाहिर कर रहे हैं। हमारी ऐसी कोई इंटैन्शन नहीं है। हां, कई कारण होते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो प्रमोट होगा हम उसको विभाग को चलाने के लिए सक्षम नहीं समझते। We give extension to the person

and make for the next man to take over. It is a Government policy. दूसरी बात यह है कि सर्विस में ऐक्सटैनशन कोई नई चीज नहीं है। आपकी पार्टी की भी यहां पर दो बार सरकार बनी। यहां धूमल साहब के नेतृत्व में सरकार बनी और उससे पहले शांता कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी। If you ask me question, I can give you figures how many people were given extension. जैसे यहां कहा गया कि सचिवालय में लोग सेवा विस्तार के लिए आ रहे हैं। You are trying to dramatize their issue. मैं यह कहना चाहता हूं कि सेवा विस्तार के लिए 6 महीने पहले दरख्वास्त देने का प्रावधान है। अतः 15 दिन पहले लिखकर देने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। आपने यहां एच.पी.एस.ई.बी. की बात की तो यह ठीक है कि वहां पर 209 लोगों को सेवा विस्तार दिया गया। They were field workers. (---

23.3.2015/1445/ag/av/2

व्यवधान---) नहीं, यह एच.पी.एस.ई.बी.लि. ही है और अब यह कम्पनी बन गई है। मैं यह कह रहा हूं कि वहां पर फील्ड वर्कर्ज की कमी है। हमारे पास जो ट्रैनड फील्ड वर्कर्ज हैं जैसे लाइन मैन और दूसरे वर्कर्ज हैं; वे सेवानिवृत हो रहे थे। उनकी जगह जो नये भर्ती हो रहे थे उनको ट्रेनिंग हासिल करनी है, वे उस काम को अभी सम्भाल नहीं सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटिड ने 209 कर्मचारियों को ऐक्सटैनशन दी है।

समाप्त

23.3.2015/1445/ag/av/3

प्रश्न संख्या : 1665

श्री बलदेव सिंह तोमर : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसमें बताया गया है कि एक साल के अंदर अवैध खनन के 16 मामले पकड़े गए जिसमें 12 मामलों में कम्पाउंडिंग हुई है। शिलाई विधान सभा क्षेत्र में पिछले एक साल से लगातार अवैध खनन हो रहा है जिसमें कि रोज कम-से-कम 50 से लेकर 100 ट्रक अवैध खनन के जा रहे हैं। यह खनन लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर हो रहा है। सड़कों को 50-50, 100-100 मीटर पीछे तक काटा जा रहा है जिसमें कि कांटी मुश्वा सड़क, सकौली सड़क, पुड़वाह सड़क और नेशनल हाई वे 72-बी पर भी अवैध खनन हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो लोग अवैध खनन कर रहे हैं

या जिनकी वह जमीन है उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं हुई है? दूसरा, लोक निर्माण विभाग, फॉरैस्ट विभाग, खनन विभाग या पुलिस विभाग ने अवैध खनन करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? अभी तक उन्होंने एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं की है? मैं यह जानना चाहता हूं कि उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है/होनी है? क्या आने वाले दिनों में हो रहे अवैध खनन पर सरकार अंकुश लगायेगी क्योंकि पिछली रात भी वहां से सौ ट्रक अवैध खनन के आये हैं। ---

श्री बी.जे.द्वारा जारी

23.3.2015/1450/negi/jt/1

प्रश्न संख्याः 1665 जारी..

श्री बलदेव सिंह तोमर... जारी...

क्योंकि पिछली रात भी 100 ट्रक वहां से अवैध खनन के आए। वहां पर लगातार जे.सी.बीज. लगी हैं, लगातार अवैध खनन हो रहा है और सड़कों की हालत खराब हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में इन अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी?

शहरी विकास मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक आपने कहा है कि शिलाई और पांवटा में अवैध खनन हो रहा है। शिलाई और पांवटा में 39 मॉइन्ज़ हैं जिनमें 13 अभी काम कर रही हैं और एक सी.सी.आई. की, केन्द्र सरकार की माईन है। जो शिलाई विधान सभा क्षेत्र है वहां पर विशेष करके ढांग रोहाना के क्षेत्र से ज्यादातर शिकायतें आती हैं। वहां पर दो माइन्ज़ स्वीकृत हैं जिसमें से अभी एक माईन ही काम कर रही है, दूसरी बन्द पड़ी है। यहां क्योंकि सरकारी भूमि और वन भूमि में ज्यादातर लाईम स्टोन पाया जाता है इसलिए ज्यादातर अवैध रूप से इस क्षेत्र में इस तरह का मामला विभाग के ध्यान में आया था। विभाग ने उप-मण्डलाधिकारी पांवटा साहब के साथ मिल करके और रेवेन्यु आफिसर्ज़ के साथ मिल करके वहां पर यह पता लगाने का प्रयास किया कि जो स्थानीय लोग हैं जिनकी भूमि है जो लीगली माईन करने के लिए अधिकृत नहीं हैं लेकिन फिर भी उनकी भूमि से लाईम स्टोन उठाया जा रहा था। क्योंकि स्थानीय लोग एक दूसरे के खिलाफ ग्वाही देने के लिए तैयार नहीं थे, जब भूमि चिहिन्त हो गई तो उसके बाद ऐसे 5 मामले ध्यान में आए।

क्योंकि स्थानीय लोगों के खिलाफ कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली लेकिन विभाग ने इन 5 मामलों को पांवटा साहब कोर्ट में दिया है। जहां तक आपने कहा, जो अवैध खनन का मामला है यह कम्पाउंडेबल है। अभी हाल ही में विभाग ने जो अपने रूल्ज़ हैं उनको नए सिरे से ले करके आए और 43 साल के बाद दोबारा इनको बदले हैं, जिसमें 2 वर्ष की सजा का प्रावधान किया है और कम्पाउंडेबल फीस 25,000/- रूपये तक की गई है। जिस तरह से आपने कहा कि 100-100 ट्रक वहां से चला जाता

23.3.2015/1450/negi/jt/2

है। इसकी आप पूरी जानकारी लिखित रूप से देंगे तो निसिंदेह इसमें जो कोई अधिकारी संलिप्त होगा या अन्य विभागों के अधिकारी भी संलिप्त होंगे अवश्य कारवाई की जाएगी ।

श्री बलदेव सिंह तोमर: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नही हुई है? पिछले 6 महीने से जो पी.डब्ल्यू.डी. विभाग की सड़कें अवैध रूप से काटी जा रही है, पी.डब्ल्यू.डी. विभाग ने अभी तक क्यों कार्रवाई नही की है? वहां से दिन-रात अवैध खनन की सैंकड़ों गाड़ियां निकल रही हैं। विभाग का कोई अधिकारी वहां क्यों नहीं जाता है ? पुलिस वहां पर क्यों नहीं जा रही है, माइनिंग ऑफिसर क्यों नहीं जा रहा है, पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के अधिकारी क्यों नहीं जाते हैं और वन विभाग के अधिकारी क्यों नहीं जाते हैं? अगर आप वहां पर इन्क्वायरी करेंगे तो लाखों टन वहां से माल निकाला जा चुका है, अभी तक अधिकारी वहां क्यों नहीं गए और अभी तक कार्रवाई क्यों नही हुई है ?

Speaker: Give reason as to why action was not taken?

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने उत्तर में जानकारी दी है कि 16 मामलों में कार्रवाई हुई है। इसके अलावा जिला सिरमौर में अवैध खनन की रोकथाम हेतु विभाग समय-समय पर छापेमारी और दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई अमल में लाता रहा है । 1.4.2013 से 31.3.2014 के दौरान छापेमारी में चुना पत्थर के अवैध खनन के कुल 13 मामले पकड़े गए हैं जिनमें 7 मामलों में 67,000/- रूपये जुर्माना

वसूला गया है। जबकि 6 मामले न्यायालय में दायर किए गए। जबकि 1.4.2014 से 28.2.2015 तक छापेमारी के दौरान चुना पत्थर के अवैध खनन के कुल 35 मामले पकड़े गए हैं जिनमें 18 मामलों में कुल 1,84,000/- रूपये जुर्माना वसूला गया है । जबकि 3 मामले न्यायालय में दायर किए गए हैं और अन्य 14 मामलों में दोषियों को नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है ।

23.3.2015/1450/negi/jt/3

जहां तक आपने कहा है कि पी.डब्ल्यू.डी. विभाग की सड़क की साईट से माइनिंग हो रही है, यह सूचना मेरे पास अभी उपलब्ध नही है, आपने बताया है, इसको संबंधित विभाग से उठा करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वह की जाएगी ।

समाप्त

अगला प्रश्न श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

प्रश्न संख्या-1666

Shri Ravi Thakur: Hon. Speaker, Sir, I would like to ask from the Hon. Minister that is there any proposal of constructing extra rooms and accommodation at Kukumseri College to start polytechnic college till permanent arrangement is made for land and building as the college is being run at Sundernagar against the college sanctioned at Udaipur (Lahaul)? Secondly, by when the polytechnic college is due to start and how many years have passed since the polytechnic college was sanctioned?

Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Minister: Speaker, Sir, the building of the Government Polytechnic, Lahaul & Spiti is proposed to be built at Phatgarh (Udaipur) for which forest land measuring 25.01 bighas bearing khasra no.24/12/1, area 14.19 bighas and 8/1 and area 10.2 bighas has been identified and selected for the purpose. Principle

approval for the transfer of this land has been accorded by the Government of India and conveyed vide letter No. HPB109/2012 dated 11.07.2012. माननीय अध्यक्ष जी, इसके ऊपर तकरीबन एक करोड़ रुपया फॉरेस्ट डिपार्टमैंट के पास डिपोज़िट कर दिया है, और अगली कार्रवाई की जा रही है। अभी तक सुन्दरनगर में इसकी क्लासिज़ चलाई जा रही हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसमें संज्ञान लिया है। जल्दी से जल्दी इस काम को किया जायेगा।

23.03.2015/1455/यूके /जेटी/2

Shri Ravi Thakur: Speaker, Sir, I would like to ask the Hon. Minister that the land which he is mentioning about is where BRO buildings are constructed and are existing for the last few decades and all the roads of Lahaul-Spiti are under the BRO. So, how is it possible to knock down all the buildings, displace them and make a polytechnic college? The initial proposal was that the college will start at Kukumseri. So, how the Government is going to finalise the proposal?

Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Minister: Speaker, Sir, presently the classes of Government Polytechnic, Lahaul & Spiti with one discipline is running in Jawaharlal Nehru Govt. Engg. College, Sundernagar, as a Mentor Institute decided by the Govt. of India from the academic year 2013-14. अब माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कमेटी ने डिसाईड किया था कि यहां पर खुलेगा। सारी परमिशनों के लिए ऐप्लाई कर दिया है। फौरेस्ट डिपार्टमैंट ने लैंड हमारे नाम कर दी है। अब इसके ऊपर काम चल रहा है। अब इस साईट को बदलना है तो at this stage, I don't think it is appropriate. So, at the moment, we are going ahead with the site which is already selected.

Concluded.

(Question Hour is over)

23.03.2015/1455/यूके /जेटी/2

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी, सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएंगे ।

मुख्य मन्त्री, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जो कि इस प्रकार हैः-

सोमवार, 23 मार्च, 2015	1. शासकीय/ विधायी कार्य । 2. बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2015-16 सामान्य चर्चा ।
मंगलवार, 24 मार्च, 2015	1. शासकीय/ विधायी कार्य । 2. बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2015-16 सामान्य चर्चा ।
बुधवार, 25 मार्च, 2015	1. शासकीय/ विधायी कार्य । 2. बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2015-16 सामान्य चर्चा ।

23.03.2015/1455/यूके /जेटी/3

वीरवार, 26 मार्च, 2015	1. शासकीय/ विधायी कार्य । 2. बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2015-16 सामान्य चर्चा एवं चर्चा का समापन।
शुक्रवार, 27 मार्च, 2015	1. शासकीय/ विधायी कार्य । 2. बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2015-16 मांगों पर चर्चा एवं मतदान ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

23.03.2015/1500/sls-ag-1

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं -

(i) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिनियम, 1968 की धारा 15 की उपधारा (1) और (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का लेखा विवरण वर्ष 2013-14; और

(ii) हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग अधिनियम, 2010 की धारा 13(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 एवं 2012-13.

23.03.2015/1500/sls-ag-2

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे।

अब श्री राकेश कालिया, सभापति, जन प्रशासन समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री राकेश कालिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जन प्रशासन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर भी रखता हूं।

(i) समिति का 13वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 36वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सहकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का 14वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 36वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है ।

23.03.2015/1500/sls-ag-3

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों पर चर्चा

अध्यक्ष : आज से वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट अनुमानों व वित्तीय विवरण पर सामान्य चर्चा आरंभ हो रही है। इसका समापन 26 मार्च, 2015 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय के उत्तर के साथ होगा। समय की उपलब्धता अनुरूप विपक्ष के नेता को 45 मिनट तथा अन्य सदस्यों को 10 से 12 मिनट में ही अपनी-अपनी बात रखने का समय उपलब्ध रहेगा। मेरा सभी सदस्यों से निवदेन है कि वे अपने-अपने भाषण बजट तक ही सीमित रखें तथा अपनी चर्चा निर्धारित अवधि के भीतर ही समाप्त करें।

अब सर्वप्रथम् मैं प्रो० प्रेम कुमार धूमल जी, नेता विपक्ष को चर्चा आरंभ करने के लिए आमंत्रित करता हूं।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, 18 मार्च को माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना 18वां और इस कार्यकाल का तीसरा बजट इस सदन में प्रस्तुत किया। 18वां बजट पेश करना एक इतिहास बन गया, जिसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं।

आप चर्चा को समय सीमा में बांध रहे हैं जबकि बजट भाषण 3.10 घंटे का था। बहुत बड़ा भाषण था लेकिन बीच में कंटैंट बहुत कम था। मैं आपके माध्यम से कुछ बातें माननीय मुख्य मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं। आपके इकोनोमिक सर्वे का इंडिकेटर जो है, मैंने यह पहली बार देखा कि हिंदी और इंगलिश वर्शन में अंतर है। जो खाद्यान का उत्पादन है, उसका आंकड़ा जो चेंज का है वह हिंदी में कुछ और है और इंगलिश में कुछ और है। इकोनोमिक सर्वे बहुत महत्वपूर्ण डाकुमैंट होता है। पृष्ठ 3, सारणी-1.1 मुख्य सूचक में खाद्य उत्पादन का पिछले वर्ष से प्रतिशत्

परिवर्तन वर्ष 2012-13 में 2.3 है जबकि अंग्रेजी संस्करण में (-)0.2 तथा वर्ष 2013-14 में हिंदी में (-)0.2 और अंग्रेजी संस्करण 2.3 दिखाया गया है। आंकड़ों में भिन्नता

23.03.2015/1500/sls-ag-4

है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी रिपोर्ट क्या होगी? माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी फिसकल मैनेजमैंट बहुत ऐक्सेलैंट थी, इस कारण से प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। टेबल 1-3, Non Tax Revenue...

जारी ..गर्ग जी

23/03/2015/1505/RG/AG/1

प्रो. प्रेम कुमार धूमल-------क्रमागत

टेबल 1.3 पर देखिए, नॉन-टैक्स रैवेन्यु वर्ष 2011-12 में हमारे कार्यकाल में 1,915 करोड़ था, वर्ष 2012-13 में 1,377 करोड़ रह गया, वर्ष 2013-14 में 1,408 करोड़ और वर्ष 2014-15 में 1,399 करोड़ रहा। फिर माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि पिछली सरकार ने बहुत ही कठिन वित्तीय स्थिति में हमें छोड़ा। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2011-12 में जो कैपिटल रिसीट्स एवं बौरोइंग लायबिलिटीज़ थीं वे 1,984 करोड़ थी, ये इनके आंकड़ें हैं, वर्ष 2012-13 में 3,371 करोड़, वर्ष 2013-14 में 3,722 करोड़ और इस रिपोर्ट के छपने के बाद यदि आपने कोई और लोन नहीं लिया हो, तो 3,634 करोड़ है। तो लगभग डबल लायबिलिटीज़ एवं बौरोइंग आपके समय में हुई है।

अध्यक्ष महोदय, as percentage of GDP to revenue receipts हमारे समय में रैवेन्यु रिसीप्ट्स की परसेंटेज थी 21.89, वर्ष 2012-13 वह 20.45% रह गई, वर्ष 2013-14 में 10.41% और अब 17.28%, टैक्स रैवेन्यु कम हुआ है, नॉन-टैक्स रैवेन्यु कम हुआ है, ग्रांट इन एड कम हुई है और सबसे चिंताजनक बात जो है वह है टोटल ऐक्सपैन्डीचर, प्लान ऐक्सपैन्डीचर क्या है? प्लान ऐक्सपैन्डीचर जो हमारे समय 5.93 था वह वर्ष 2012-13 में 5.75 हुआ, वर्ष 2013-14 में 5.59 और अब वर्ष 2014-15 में वह 4.62 रह गया अर्थात 1.31, वह भी कम हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार ऐनुअल प्लान का ऐवरेज़ परसेंटेज Five year plan wise है, 8वीं योजना में कांग्रेस सरकार थी, तो हिमाचल प्रदेश का 6.3% था,

ऑल इण्डिया का 6.2% था, 0.1 प्रतिशत हिमाचल की अच्छी परफॉरमैंस थी। 9th Plan हमारे कार्यकाल में कार्यान्वित हुई, ऑल इण्डिया का 5.6% था, हमारा 6.4% था, इसमें 0.8% ज्यादा रहा। 10th Plan फिर इनके समय आया, तो नेशनल लेवल पर बढ़कर 7.8% पर पहुंच गया, लेकिन हिमाचल में 7.6% रह गया और 11th Plan का भारत सरकार का ग्रोथ रेट 8% था और हिमाचल प्रदेश सरकार का भी इतना ही था। वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 का इन्होंने इसमें नहीं दिया है, कंपैरिजन नहीं किया है, शायद इनके पास भारत सरकार के आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, इनका कितना बढ़िया प्रबन्धन है जिसका दावा ये करते हैं। प्रदेश में टूरिस्ट्स अराइवल क्या है? वर्ष 2007 में 3,39,000 विदेशी पर्यटक प्रदेश में आए, वर्ष 2008 में 3,77,000 विदेशी पर्यटक आए, वर्ष 2009 में 4,01,000 पर्यटक

23/03/2015/1505/RG/AG/2

आए, वर्ष 2010 में 4,54,000 पर्यटक आए, वर्ष 2011 में 4,84,000 और वर्ष 2012 में 5,00,000 विदेशी पर्यटक आए। अब इनके कार्यकाल में गिरकर ये 3,90,000 पर्यटक ही रह गए। वर्ष 2014 में हिमाचल प्रदेश में 1,10,000 विदेशी पर्यटक कम आए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में आज पर्यटन की क्या स्थिति हो रही है! हम इनकी इस बात का स्वागत करते हैं कि गुड गवर्नेन्स के लिए ये लोक मित्र केन्द्र स्थापित करेंगे----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

23/03/2015/1510/MS/JT/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जारी----------

हम आपकी इस बात का स्वागत करते हैं कि गुड गवर्नेंस के लिए लोकमित्र केन्द्र आप एस्टेब्लिश करेंगे, हिमाचल भवन नई दिल्ली और हिमाचल भवन चण्डीगढ़ में to facilitate Himachalis in 2014-15 which finds no mention in the Budget Speech now. आपने वर्ष 2014-15 में कहा था कि दिल्ली में भी और चण्डीगढ़ में भी हो जाएगा लेकिन वे एस्टेब्लिश हुए कि नहीं हुए, उसका इस बजट भाषण में कोई जिक्र नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकमित्र केन्द्र स्थापित किए गए हैं

उनकी वर्किंग क्या है? आज वे संतोषजनक नहीं है। लोगों को जो शिकायतें, जो सूचनाएं और जो जानकारी चाहिए, वह लोकमित्र केन्द्रों से नहीं मिल रही है। यह सही है कि पर केपिटा इन्कम एक लाख को क्रॉस कर गई और अब एक लाख चार हजार हो गई। यह सारे प्रदेशवासियों के लिए भी और सरकार को भी बधाई का विषय है। लेकिन हमारे समय में जो वृद्धि की परसेंटेज थी, वह इससे कहीं ज्यादा थी। हमारे समय में एवरेज 13 परसेंट पर केपिटा इन्कम इन्क्रीज होती थी।

इसी तरह से अध्यक्ष जी, इकानोमिक सर्वे के अनुसार भी और हम सब मानते हैं कि road line is the lifeline of the State. यहां सड़कें ही जीवन रेखा हैं। मैं देख रहा था पिछले दो वर्षों से आपकी डबल लेन 2416 किलोमीटर ही चल रही है अर्थात आपने एक किलोमीटर भी डबल लेन एक्सटैंड नही की। विकास के मामले में आप कहते हैं कि हमारा प्रदेश इण्डस्ट्रियल हब हो गया। आपने बहुत सारे इण्डस्ट्रियल मेले लगाए। इण्डस्ट्रियल आउटपुट आपके ही आंकड़ों के मुताबिक 18 प्रतिशत से कम होकर 16.5 प्रतिशत रह गया। तो इण्डस्ट्री में भी आप डाउन जा रहे हैं।

अध्यक्ष जी, एक चीज का सारे प्रदेश के लोग इंतजार कर रहे थे। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स मोबेलाइजेशन कमेटी प्रदेश की आर्थिक स्थिति को खराब देखते हुए बनाई थी। उसकी इस बार के बजट में बहुत आशा थी। उसकी रिकमेंडेशन्ज क्या हैं? प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसे सुधर सकती है क्योंकि रिर्सोस मोबेलाइज नहीं हो रहा है। प्रदेश को सबसे गम्भीर संकट यह है कि संसाधन नहीं

23/03/2015/1510/MS/JT/2

जुटाए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक खर्चे की वृद्धि अध्यक्ष जी, 31 प्रतिशत है । Debt burden has crossed Rs. 34,000/- crores mark. तो उस कमेटी ने कोई रिकमेंडेशन्ज की होंगी। उसको एक्टिवेट कीजिए। उसका चैयरमैन एक्टिव आदमी था लेकिन उसमें रिजाइन हो गया। अब या तो मैडम एक्टिवेट हो जाए।

मुख्य मंत्रीः उसने स्वेच्छा से रिजाइन किया, इसका मुझे अफसोस है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः वॉलेंटरी रिटायरमैंट हो गई। बाली जी कह रहे हैं कि मैडम उनसे ज्यादा एक्टिव है। तो परिणाम क्या आया? एक्टिव होने के बाद तो रिपोर्ट की कोई प्रोडक्शन होनी चाहिए।

टैक्स कलैक्शन की रेशो भी GSDP से कम हो गई है। अध्यक्ष जी, केवल उद्योग में ही उत्पादन कम नहीं हुआ Power generation has also decreased from 1950 million units to 1815 million units. 1950 मिलीयन युनिट जो पावर जनरेशन होता था, वह 1815 युनिट रह गया है। यह भी चिन्ता का विषय है। GSDP का अध्यक्ष जी मैंने जिक्र किया कि जो वर्ष 2011-12 में ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 14.8 प्रतिशत था, वह आपकी 2015-16 के सर्वे के मुताबिक 2013-14 में 12.6 प्रतिशत रह गया। यहां भी पिछड़ रहे हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

23.3.2015/1515/जेके/,एजी/1

श्री प्रेम कुमार धूमलः-------जारी-----

अध्यक्ष महोदय, 20 सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन बहुत महत्वपूर्ण होता है जिससे सरकार की परफोरमैंस राष्ट्रीय लैवल पर भी आंकी जाती है। हमें इस बात की खुशी है कि वर्ष 2009-10, 2010-11 और वर्ष 2011-12 तीनों सालों में हिमाचल प्रदेश देश में नम्बर-1 पर था। State of the States Award मिलता रहा। लेकिन वर्ष 2013-14 और 2014-15 और वर्ष 2012-13 की आपकी क्या परफोरमैंस रही है, क्या फंक्शनिंग रही है, इसका जिक्र नहीं है। भाषण आपका बहुत लम्बा था तभी मैंने कहा कि जो बातें आनी चाहिए थी, वह नहीं आई। आपको लिख करके जो दे दिया, आपका टैस्ट तो हो गया कि आप खूब पढ़ सकते हो और तीन घण्टे खड़े रह सकते हो। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी कि उस घोषणा का स्वागत करता हूं यदि इम्प्लिमैंट होगा तो देखेंगें, LED डिस्ट्रिब्युशन। सारा विश्व आज बिजली बचाना चाहता है। This scheme is being implemented by the Energy Efficiency Services Limited, Ministry of Power, Government of India. भारत सरकार की योजना है। हमें इस बात की प्रसन्नता होती है कि जो भारत सरकार ने भी आज सोचा , वह आज आप भी सोच रहे हैं। हमने 15 अप्रैल, 1998 को अटल बिजली बचत योजना चलाई थी। आप तो इसमें पैसे लेने की बात कर रहे हैं। हमने तो मुफ्त में 4-4 बल्ब दिये थे। उसका कितना विरोध हुआ था? हम राजनीतिक कारणों से विरोध नहीं करना चाहते हैं। डेफिनेटली सी.एफ.एल. पर एल.ई.डी. इम्प्रूवमैंट है। मुख्य मंत्री महोदय, पहाड़ में हर व्यक्ति के घर बड़े हैं और ये बल्ब कम है। बल्बों की संख्या

बढ़ाएं और पैसा रीकवर करने की बात छोड़ें। अगर सी.एफ.एल. उस वक्त मुफ्त दिए जा सकते हैं तो एल.ई.डी. के बल्ब भी मुफ्त दिए जाने चाहिए। एल.ई.डी. का बल्ब अगर गरीब मज़दूर लेगा तो उसकी दिहाड़ी आपने 10 रूपये बढ़ाई, जो कि बहुत कम है। आपके चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार भी 200 रूपये होनी चाहिए थी। वैसे भी मेरा आपसे अनुरोध है कि डेलिवेज़िज अगर आप बढ़ायेंगे नहीं तो मनरेगा में 5 हजार करोड़ रूपया अडिशनल एमाऊंट की बात कही गई है और जो प्रदेश में डेलिवेज़िज होगी वही मनरेगा वाले को मिलेगी। पंजाब में

23.3.2015/1515/जेके/,एजी/2

शायद 224 रूपये है यदि और न बढ़ाई हो। हरियाणा में इससे भी ज्यादा है। हमारे यहां पर यदि 170 रूपये से 180 रूपये हो गई तो यह मुकाबला बराबर का नहीं होगा और इसका लाभ उनको नहीं मिल पाएगा। मेरा सुझाव रहेगा कि मनरेगा में पहाड़ी राज्यों के लिए हमने पहले भी डिमाण्ड उठाई थी और आप फिर से भारत सरकार से मामला उठाएं कि मटिरियल के लिए ज्यादा पैसा अलाऊ करें। लेबर कम्पोनैंट उतना नहीं होता जितना कि मटिरियल की आवश्यकता होती है और यहां पर मटिरियल वैसे भी मंहगा होता है। आपने अपने भाषण में यह भी जिक्र किया कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 'Scaling the Heights' और आपने कहा कि कांग्रेस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह कौन से साल हुई थी 'Scaling the Heights'. 1993 से 2011 तक हुआ है और जिसका जिक्र आया था कि हिमाचल प्रदेश ने बहुत शानदार काम किया। उन 18 वर्षों में से 10 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी का शासन हिमाचल प्रदेश में रहा है।

अध्यक्ष महोदय, बजट में सब कोई आशा कर रहे थे कि जो पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जैसे वॉर्ड पंच, प्रधान, उप-प्रधान, बी.डी.सी. मैम्बर, चेयरमैन, वाईस चैयरमैन, जिला परिषद् के मैम्बर, चेयरमैन, वाईस चेयरमैन और अर्बन लोकल बॉडिज़ हैं, के ऑनरेरियम में कोई वृद्धि नहीं की गई है। जब आप ज़वाब देंगे तो मैं निश्चित तौर पर आशा करता हूं कि उनके लिए भी आप वृद्धि की घोषणा करेंगे। क्योकि तीसरा बजट है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----------

23.03.2015/1520/SS-JT/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल क्रमागतः

क्योंकि यह तीसरा बजट है। चौथे बजट में लोग विश्वास नहीं करते कि चुनाव आ रहे हैं सिर्फ घोषणा होती रहेगी।

स्किल डिवैल्पमैंट पर जोर दिया गया है लेकिन इसी सदन में मामला बार-बार उठा है और आपके कैबिनेट मंत्री भी कहते हैं कि जिन लोगों को स्किल डिवैल्पमैंट का काम दिया गया है वे इंस्टिट्यूशन्ज़ या तो फेक हैं या वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उनके द्वारा जो प्रमाण पत्र दिये जा रहे हैं, जो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, उनको गवर्नमैंट और प्राइवेट सैक्टर में कहीं मान्यता प्राप्त नहीं है। अन-इम्प्लॉयड यूथ को इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है।

योजना में भी आपने कैपिटल एक्सपेंडीचर को कम कर दिया है। जो 2011-12 में प्लान का 5.6 प्रतिशत कैपिटल पर खर्च होता था, वह 2014-15 में 4.01 प्रतिशत रह गया है। इसका मतलब है कि एग्जैक्ट डेढ़ परसैंट की कमी इसमें आ गई है। आपके भाषण में एक और भी ज़िक्र है कि प्लानिंग एरिया में मिक्सड लैंड यूज एलाऊ करेंगे। यह बहुत डाउटस क्रियेट करता है। इस स्कीम को एक्सप्लेन करिये। क्या कुछ लोगों ने जो गड़बड़ियां की हैं उसको रेगुलराइज़ करने के लिए किया जा रहा है या कोई नई स्कीम है जिससे सब को लाभ होगा? ये शंकाएं दूर होनी चाहिएं। ऐसी ही कंफ्यूजिंग स्टेटमैंट लेबर लॉज पर है कि कुछ लेबर लॉज को अमैंड किया जायेगा क्योंकि वे किसी को फायदा नहीं करते। ऐसा लॉ कौन-सा हो सकता है जो किसी को फायदा नहीं करता? या तो वह लेबर के हक में है, मालिक उसको बदलवाना चाहते हैं ताकि लेबर को उन्हें कुछ देना न पड़े। या वह मालिक के हक में इतना है कि वह लेबर को नुकसान कर रहा है।

एक चर्चा बार-बार उठी। पिछली बार डॉ0 राजीव बिंदल ने भी उठाई थी कि ठियोग से हाटकोटी रोड आपके इलैक्शन का बहुत बड़ा मुद्दा था। आपने केवल मात्र एक लाइन में कह दिया कि ठियोग-हाटकोटी रोड और घुमारवीं-सरकाघाट रोड की रिटैंडरिंग कर दी है। अगर ढाई साल में रिटैंडरिंग ही होनी है तो काम कब होगा? इस तरह से विकास की गति बिल्कुल ठप्प पड़ी है।

लॉ एण्ड ऑर्डर का जवाब बड़ा गोल-मोल सा दिया गया है। लेकिन आंकड़े सच बोलते हैं। आपका ही इकोनॉमिक सर्वे का पेज़-22, टेबल-33 है - Crime rate

23.03.2015/1520/SS-JT/2

as per your own figures has increased from 15937 in 2012 to 17122 in 2014. 2015 के आंकड़े तो अध्यक्ष महोदय आने हैं।

Chief Minister: It is due to better detection of the cases.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः इसका मतलब है कि आप डिटैक्ट कर लेंगे कि बलात्कार हो गया, बलात्कारी को पकड़ लिया तो संतोष होगा। बलात्कार हो ही क्यों। मुख्य मंत्री महोदय, अच्छा हुआ कि आपने इंटरवीन किया। शिमला में ही लोअर बाज़ार में एक बच्चा उठाया गया है। लोअर बाज़ार में शिमला में एक बच्चे को किडनैप किया गया है। मेरे चुनाव क्षेत्र में हमीरपुर शहर में आदित्य नाम का एक पांच साल का बच्चा उठाकर ले गए। महीने से ज्यादा हो गया लेकिन उसका पता नहीं लगा। पहले भी आपके ध्यान में लाया था कि आप कांगड़ा के प्रवास पर थे, वहां एक बच्ची से बलात्कार हुआ लेकिन आज तक वे बलात्कारी पकड़े नहीं गए। शिमला जो राजधानी है, आई0एस0बी0टी0, तारादेवी, मशोबरा, ठियोग, कुफरी में लावारिश लाशें पाई गईं। ये तो मैं शहर के नज़दीक की बातें बता रहा हूं। सारे प्रदेश में डिटैक्शन की जो बात आप कह रहे हैं लावारिश लाशें क्यों पाई जा रही हैं? कौन कत्ल करके भागा जा रहा है? रेप, मर्डर, डकैती, चोरी, चेन स्नैचिंग के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इसमें कोई प्वाइंट सिक्योर करने की बात नहीं है। कोई भी सरकार हो, ऐसा मामला अगर होगा..

जारी श्रीमती के0एस0

23.03.2015/1525/केएस/एजी/1

श्री प्रेम कुमार धूमल जारी---
कोई भी सरकार हो, ऐसा मामला अगर होगा तो यह नहीं होना चाहिए और दोषियों को अगर तुरन्त कड़ी सजा दी जाएगी तो निश्चित तौर पर डैटरैंट के तौर पर वह काम करेगा। मैंने पहले भी कहा था कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी ड्रग माफिया के बारे में कोई ज़िक्र नहीं किया गया है। ड्रग ट्रैफिकिंग आज देश की सबसे बड़ी समस्या बन गई है, यह केवल हमारे प्रदेश की ही समस्या नहीं है। लेकिन यह देव भूमि है यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आम चर्चा सुनिए, आपकी सी.आई.डी. आपको रिपोर्ट देती होगी, ऐजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्ज़ के पास दुकानें

खुली हुई हैं जहां से लोगों को नशे की दवाइयां मिल रही है, नशा मिल रहा है, नशा बिक रहा है। नई जनरेशन तबाह हो रही है, बच्चे उसको खरीद कर खा रहे हैं, पी रहे हैं। बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो रही है। यही भयंकर स्थिति हमारे पड़ौस के राज्यों में भी है और हमारे यहां भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मेरा आग्रह रहेगा कि इस बुराई को रोकने का बजट में भी प्रावधान किया जाए और केवल सरकार ही अकेले इस बुराई को समाप्त नहीं कर सकती, हमको और पूरे समाज को मिल कर इसमें सहयोग करना होगा । घर में मां-बाप को बच्चे का ध्यान रखना होगा, स्कूल में टीचर्ज़ को रखना होगा। आप सादे कपड़ों में वहां पर पुलिस वालों की डियूटी लगाएं जो कि चैक करें। इसका मुख्य कारण बेरोज़गारी भी है। प्रश्न संख्या 700 के जवाब में आप ही ने 16 मार्च को कहा था कि 46863 पद विभिन्न श्रेणियों के खाली पड़े हैं। उनमें से जो हज़ारों लोगों को आपने री-इम्प्लॉयमैंट दी थी, एक्सटैंशन दी थी अगर

उनको भी जोड़ दिया जाए तो लगभग 50 हजार के करीब पद खाली पड़े हैं और ग्यारह-साढ़े ग्यारह लाख लोग रजिस्टर के हिसाब से हमारे पास बेरोज़गार हैं। आपने पांच हजार फंक्शनल पोस्टें भरने की बात की है । साढ़े ग्यारह लाख में से अगर पांच हजार को नौकरी मिल गई तब भी ग्यारह लाख पैंतालीस हजार बेरोज़गार रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का यह तीसरा बजट आ गया। आप सब बेरोज़गारी भत्ते के नारे पर जीत कर आए हैं और इस बार मुख्य मंत्री महोदय ने अपने भाषण में बहुत सारे शेर बोले हैं। बजट प्रैज़ैंट करने का भी और शेरो-शायरी करने का भी रिकॉर्ड कायम किया है। तो बेरोज़गारों की तरफ से एक शेर आपके लिए आया है किः

निगाहें मुंतज़िर थी कि कब सहर टूटे, सुबह होगी
मगर यह रात तो और काली होती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, बेरोज़गारों के लिए इंतज़ार की घड़ियां लम्बी होती जा रही है। आपने अपने भाषण में यह भी कहा कि हमने बड़ी योग्यता से अपना पक्ष रखा इसलिए चौदहवें वित्तायोग ने बहुत बढ़िया ग्रांट हमें दी।

परन्तु आपने केन्द्र का धन्यवाद नहीं किया। आप पहले अपने भाषण में डॉ0 मनमोहन सिंह जी का, श्रीमती सोनिया गांधी का और दाव लगता था तो उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी का भी धन्यवाद पहले पैराग्राफ में कर देते थे लेकिन इस बार केन्द्र ने बहुत बढ़िया काम किया जो 14वें वित्तायोग की सिफारिश आई थी उसको डाइसैंटिंग नोट के बावजूद वैसे के वैसे ही स्वीकार किया। आप तो सबसे लम्बे समय तक मुख्य मंत्री रहे हैं। कितनी बार केन्द्र से कहते थे कि सैंट्रल टैक्सिज़ में हमारा शेयर बढ़ाओ? कभी

23.03.2015/1525/केएस/एजी/3

आधा परसेंट, कभी एक परसेंट बढ़ता था। 13वें वित्तायोग, जिसका दोष आप हमें देते हैं कि हमने पक्ष ठीक नहीं रखा, कोई प्रदेश सरकार ऐसी नहीं होती कि वह अपना पक्ष ठीक न रखे और हमने तो जब आपके समय में 12वां वित्तायोग आया था तब हमने भी--

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

23.3.2015/1530/jt/av/1

श्री प्रेम कुमार धूमल जारी--------
जब 12वां वित्तायोग आया था तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने अपोजिशन के तौर पर मैमोरैंडम दिया था और आपके साथ मिलकर बी.बी.एम.बी. प्रोजैक्ट में शेयर मांगा था। हमें इस बात का भी दुख है कि बी.बी.एम.बी.प्रोजैक्ट में जो हमें 4,250 करोड़ रुपये के करीब एरियर मिलना है उसका जिक्र ही नहीं है। हम बार-बार मांगते थे कि थोड़ी वृद्धि दो। पिछली बार भी साढ़े आठ प्रतिशत वृद्धि रिकमैंड हुई थी। 13वें वित्तायोग ने कहा था कि स्टेट को टैक्स का साढ़े 39 प्रतिशत मिलना चाहिए। यू.पी.ए. की सरकार ने एक प्रतिशत बढ़ाकर 31 से 32 प्रतिशत किया था। इस बार हम प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी के धन्यवादी हैं। इस बार जो 32 से 42 प्रतिशत करने की रिकमैंडेशन आई वह वैसे-की-वैसे स्वीकार कर ली। हालांकि जे.एन.एन.यू. के एक स्कॉलर ने कहा था कि पहले 38 करो, फिर 42 करना। उसके परिणामस्वरूप 12वें वित्तायोग में जो आपके समय में

14,450 करोड़ रुपये मिला था तथा 13वें वित्तायोग में हमारे समय में 21,691 करोड़ रुपये मिला था वह इस बार आपको 72,047 करोड़ रुपये मिलेगा।

मुख्य मंत्री महोदय, मैं आपकी ही स्पीच में से आंकड़े निकाल रहा था। केंद्र का कुछ शब्दों में धन्यवाद तो कर दो। आपने जो बजट बनाया है, मान लो सौ रुपये का बजट है तो उसमें 16.33 प्रतिशत सैंट्रल टैक्सिज का शेयर है। दूसरा उसका कम्पोनैंट सैंट्रल ग्रांट 50.32 प्रतिशत है। दोनों को जोड़कर 66.65 प्रतिशत बनता है। सौ रुपये का बजट बन रहा होगा तो उसमें 66.65 रुपये केंद्र सरकार से आ रहे हैं और 17 प्रतिशत आप कर्ज ले रहे हैं। यह 84 प्रतिशत बनताहै और इसमें स्टेट शेयर केवल 16 प्रतिशत है। आपने जिक्र किया कि अब उत्तराखंड का भी बुरा हाल होगा। उत्तराखंड को रैवन्यु डैफिसिट ग्रांट कभी भी नहीं मिली। मगर इस बार हमें फिर से भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि 13वें वित्तायोग ने रैवन्यु डैफिसिट ग्रांट केवल आठ राज्यों को दी थी जिसमें अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-

23.3.2015/1530/jt/av/2

कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। 14वें वित्तायोग ने 11 स्टेट्स को दी है जिसमें आन्ध्रप्रदेश, आसाम और पश्चिम बंगाल जोड़े गए हैं। इस बार इन राज्यों को भी ग्रांट मिली है। केरल को भी मिली है। अगर पैसा लेना हो तो रिसोर्स मोबलाइजेशन तो हमेशा एक कंडिशन रही है। यह तो होगा नहीं कि हम अपने रिसोर्स मोबलाइज करे नहीं और पैसे की अपेक्षा करें।

मैंने कहा था कि अगर भाषण लम्बा हो जाए तो कन्ट्राडिक्शन्ज ज्यादा आती है। हम आपके धन्यवादी है कि आपने विधायक क्षेत्र विकास निधि को बढ़ाने की घोषणा की है। मैंने आपका वित्तीय वर्ष 2015-16 का प्लान डॉक्युमैंट और बजट प्रावधान देखा। आपने बजट प्रावधान ही कम किया है। The allocation under Vidhayak Kshetra Vikas Nidhi Yojna has been increased from Rs. 50 lakhs to Rs. 70 lakhs for each M.L.A. The budget provision for this scheme has been done on the basis of Rs. 50 lakhs per constituency. The total budget of Rs. 34 crore i.e. Rs. 32.66 (General Plan) and Rs. 1.34 crore (Tribal Sub Plan) has been provided in the budget for 2015-16. Whereas the budget provision for this should have been Rs. 47.60 crore. जो 47.60 करोड़ रुपये होना चाहिए था--------

श्री बी.जे.द्वारा जारी

23.3.2015/1535/negi/jt/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल.. जारी...

वह 32 करोड़ 66 लाख रूपये है। इसलिए मैंने कहा था जगलरी ऑफ फिगर्ज़ एंड वर्डज़.

आपने एम.एल.एज. को भी खुश कर दिया। आपने मैडम, आई.पी.एच. मिनिस्टर को भी खुश कर दिया। उनके बजट में से आप 20 लाख डाइवर्ट करेंगे। आपने कंडिशन लगा दी जो आपको केन्द्र ने लगाई है कि रिसोर्स मोबिलाइज़ करेंगे तो आपको मिलेगा। आपने एम.एल.एज. पर यह कंडिशन लगा दी कि इरिगेशन की स्कीमें दो। सुरेश भारद्वाज़ जी शिमला में कौन सी इरिगेशन करवाएंगे? जिन चुनाव क्षेत्रों में इरिगेशन का स्कोप ही नही हैं, पानी पीने को नहीं मिलता है वहां सिंचाई की योजनाएं कहां से आएंगी? या तो आप इसको ड्रिंकिंग वाटर के साथ जोड़िए । वैसे तो हम सबकी डिमाण्ड यही है कि इसको आप खुला छोड़ें जो निर्माण कार्य पर इसका इस्तेमाल हो सके। मेरा आपसे यह निवेदन रहेगा, सारे विधायक इसको चाहेंगे। अन्यथा बजट में प्रावधान इसके लिए नहीं है।

Speaker, Sir, it has been mentioned that the allocation under RIDF has been increased from 500 crores to 750 crores. आपने 500 करोड़ रूपये से 750 करोड़ रूपये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डिवलपमैन्ट फंड में इंक्रीज करने की बात की है। इसके लिए वर्ष 2015-16 में, बजट प्रावधान केवल 459.22 करोड़ रूपये है। आप यहां से स्वॉयल कंज़र्वेशन एग्रीकल्चर के लिए 30 करोड़ रूपये देंगे। माइनर इरिगेशन के लिए देंगे 60 करोड़ रूपये। रोडज़ एण्ड ब्रिजिज़ के लिए देंगे 265.22 करोड़ रूपये। फूड एण्ड सप्लाई के लिए देंगे 4 करोड़ रूपये और रूरल वाटर सप्लाई के लिए देंगे 100 करोड़ रूपये और यह कुल 459.22 करोड़ रूपये बनता है। तो यह 750 करोड़ कैसे हुआ ? आपके एनॉउन्समैन्ट्स हो गई है लेकिन कागज़ में प्रोविजन्ज़ नहीं है। इसलिए इन्टरनल कंट्राडिक्शन्ज लगातार आपको तंग करेगी।

23.3.2015/1535/negi/jt/2

Further, on Page 70 of the Plan Document - Allocation under Sectoral Decentralised Planning, SDP जो बड़े पापुलरली लोग जानते हैं। वर्ष

2012 में वर्ष 2012-13 के लिए जब हमने बजट बनाया था तो इसमें बजट 47.37 करोड़ थी । It has been reduced to 18.86 crore in 2014-15. The budget provision for 2015-16 is 30.93 crore which is less than the provision for 2012-13. यही पैसा होता है जिससे जो अर्जेन्ट काम होते हैं, वे डी.सी. के माध्यम से होते हैं। यह 47.37 करोड़ रूपये से आपने कम करके 30.97 करोड़ रूपये कर दिया । इसमें लगभग 17 करोड़ रूपये की कमी आ गई है । स्माल डिवलपमैन्ट वर्कज़ जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, छोटे-छोटे विकास के कार्य, वे इससे प्रभावित होंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक और यहां कट लगाया गया है। एक योजना शांता कुमार की के समय चली थी -गांव भी अपना, काम भी अपना। आपने उसका नाम बदल कर विकास में जन सहयोग कर दिया। हमें भी लोगों ने कहा नाम बदलने के लिए लेकिन हमने कहा काम होना चाहिए नाम जो भी हो। स्कीम का नाम वही चल रहा है जो आपका है लेकिन आप इससे पीछे खिसक रहे हैं। हमने वर्ष 2012-13 में विकास में जन सहयोग में 17 करोड़ रूपये का प्रावधान किया था। आपने वर्ष 2014-15 में इसको कम करके 10 करोड़ कर दिया और वर्ष 2015-16 में भी 10 करोड़ रूपये कर दिया। यह भी आपके पेज-70 पर है। अब एक करोड़ बढ़ा करके 11 करोड़ रूपये की बात कही जा रही है। अध्यक्ष महोदय, उस समय इस योजना की सराहना हुई थी । यह सेल्फ टैक्सेशन है, लेाग 25 परसेन्ट, 30 परसेन्ट और कई जगह 50, शहरों में तो 50 परसेन्ट कन्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप 10 करोड़ देंगे तो जनता भी कंट्रीब्यूट करेगी, अगर वे 25 परसेन्ट देंगे तो 2.50 करोड़ रूपये उनकी कंट्रीब्यूशन होगी। तो विकास में जन सहयोग योजना में बजट प्रावधान कम करने की बजाय इसको बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि सरकारी खजाने से जो पैसा जाएगा उसमें एडिशनल लोगों की तरफ से कंट्रीब्यूशन भी आएगी।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

23.03.2015/1540/यूके /1

श्री प्रेम कुमार धूमल ---जारी ----

ऐडिशनल सैंट्रल अस्सिस्टैंस, ACA वर्ष 2014-15 में 514 करोड़ रुपए था और अब वर्ष 2015-16 के लिए 694.20 करोड़ रुपए प्रोपोज़्ड है । मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब उत्तर दें तो अधिकारी नोट कर लें कि वर्ष 2013-14 और 2014-15 में ऐक्चुअली आपको ACA मिला कितना? प्राजेक्ट करना और बात है, आप फिगर्स

बढ़ा देते हो। ऐक्चुअल में आपको वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 में कितनी रीसीट हुई है, ये बताएं ?

PDS में सब्सिडी आपने कहा वर्ष 2014-15 में 220 करोड़ रुपए थी जो कि 2015 में आपने कम कर दी, 210 करोड़ रुपए कर दी। यह 10 करोड़ रुपए की कमी है। बाली साहब, क्या इस बार भी ऐसे ही होगा कि कभी चीनी आई तो दालें नहीं, दालें आई तो अनाज नहीं,

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : हमने आपका कर्जा भी उतारा है, 108 करोड़ रुपए का।

श्री प्रेम कुमार धूमलः हमारा कर्जा तो उतारना ही पड़ेगा आपको क्योंकि हमने भी आपका उतारा था और आगे जो छोड़ कर जाओगे यह भी काफी भारी होगा। लेकिन मैं जो मुख्यतः कह रहा हूं। आपको सिस्टम को कम्प्यूटराईज़ करने के लिए भी ग्रांट मिली है। रेगुलरली यह होता है कि डिपुओं पर लोग रोज ही जा रहे हैं। आज दाल है, आज चावल है, आज आटा है, आज खांड है। उसके लिए एक डेट फिक्स हो जाए कि इस डेट को इकट्ठा सामाना मिलेगा। ताकि लोगों को भी सुविधा हो सकेगी।

23.03.2015/1540/यूके /2

ग्रामीण क्षेत्रों में इतना नहीं है लेकिन शहरी क्षेत्रों में मुख्य मंत्री महोदय, पार्किंग का बहुत महत्व है। वर्ष 2014-15 के आपके भाषण में जरा आपके पैरा 131 पर, अधिकारी भी मार्क कर लें, वर्ष 2014-15 का मुख्य मंत्री जी का भाषण। आपने कहा कि "मेरी सरकार प्रदेश के बड़े शहरों में यातायात के दबाव और पार्किंग की समस्या से परिचित है। छोटा शिमला, संजौली और शिमला स्थित लिफ्ट के समीप लगभग 1400 कारों की पार्किंग की सुविधा के लिए पार्किंग परिसर निर्माण के विभिन्न चरणों में विकास नगर में लगभग 175 वाहनों की पार्किंग के लिए एक और कार-पार्किंग निर्मित की जायेगी। इसका निर्माण कार्य वर्ष 2014-15 में आरम्भ होगा।" इसी प्रकार पालमपुर, अध्यक्ष महोदय का क्षेत्र, मंडी, अनिल शर्मा जी का क्षेत्र, में कार पार्किंग एवं व्यवसायिक परिसरों का निर्माण कार्य वर्ष 2014-15 से आरम्भ होगा। मैकलोडगंज, धर्मशाला, हमीरपुर, रोहड़ू और आई0जी0एम0सी0 तथा शिमला शहर के पुराने बैरियर के समीप कार पार्किंग एवं व्यवसायिक परिसरों का निर्माण

कार्य वर्ष 2014-15 में प्रारम्भ होगा । शिमला तथा धर्मशाला शहरों के निवासियों की सुविधा के लिए हम इन शहरों में सार्वजनिक-निजी सहभागिता के अन्तर्गत मास रैपिड ट्रांज़िट प्रणाली की संभावनाओं का पता लगाएंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा क्योंकि मेरे चुनाव क्षेत्र, हमीरपुर में तो शुरू हुआ नहीं है । कहां-कहां शुरू हुआ है वह पूरी जानकारी सदन को मिले । क्योंकि यह वर्ष 2014-15 में प्रारम्भ होना था ?

23.03.2015/1540/यूके /3

अध्यक्ष महोदय, स्किल डवेलपमैंट का जिक्र मैने पहले भी किया था, इस पर उंगलियां पहले भी उठ रही हैं । वर्ष 2014-15 में 100 करोड़ रुपए की बात थी, अब 500 करोड़ रुपए की बात है । लेकिन क्वालिटी स्किल प्रोवाईड का जब तक आप प्रबन्ध नहीं करेंगे तब तक इसका कोई लाभ नहीं होगा । आज तक कितने लोगों को स्किल प्रोवाईड किया गया और कितने स्किल प्रोवाईडर्स आपके पास एम्पैनल्ड हुए हैं, सूचीबद्ध हुए ? कितना खर्चा हुआ है? यह सारी जानकारी इसमें आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा ।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2012-13 में रोड्ज़ और टनल्ज़ का जिक्र हमने किया था और उसमें बंगाणा-धनेटा का तो फाऊंडेशन स्टोन भी हो गया था ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

23.03.2015/1545/sls-ag-1
प्रो० प्रेम कुमार धूमल...जारी

और उसमें बंगाणा व धनेटा का तो फाऊंडेशन स्टोन भी ले हो गया था और उसमें 10 करोड़ रुपये का प्रावधान भी था। होली उतराला करसर तेलंग जो कुल्लू में भुभुजोत के नाम से मशहूर है, इसका सर्वे हो गया था और डी.पी.आर. बन रही थीं। आपने कहा in addition the present Government in 2013-2014 and 2014-15 has also proposed to construct Chamunda-Holi, अब यह किशोरी लाल जी से नाराज़गी है कि उतराला वाली सुरंग छोड़कर आप चामुण्डा से शुरू कर रहे हैं या आप दो टनल बना रहे हैं, एक उतराला से होली और दूसरी चामुण्डा से होली? यह

भी स्पष्ट होना चाहिए। जब उतराला होली का सर्वे हो गया, डी.पी.आर. बन गईं तो उसके बाद उसको क्यों छोड़ा जा रहा है? क्या यह पोलिटिकल कारणों से हो रहा है? हमारे साथ तो करो लेकिन अपनी पार्टी में तो ऐसा मत करो। आपने प्रोपोज किया कि Chamunda-Holi Tunnel, Bhubujot, Tissa-Killar, Chaini Pass in Pangi Valley, Jalori Jot, Kullu and Chaini Pass. Speaker, Sir, there is no mention of these proposed tunnels in the Budget Speech of 2015-16. 2014-15 में पूरी लिस्ट थी लेकिन वर्ष 2015-16 में टनल्ज का आइडिया छोड़ दिया गया? क्या प्रोग्रैस है, कितना सर्वे हुआ है, कितनी डी.पी.आर्ज़ बनी हैं, इनका मैंशन क्यों नहीं है? हम जानना चाहेंगे कि आज इनकी वस्तुस्थिति क्या है? इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में आपने काफी लोगों को रि-इम्पलॉयमैंट दी और उसके टैक्निकल कारण बताए। आपके भाषण में घोषणा थी कि 2013-14 में 1918 मैघावाट, 2014-15 में 2000 मैघावाट और 2015-16 में 1050 मैघावाट प्रोपोज्ड हैं। How much target has been achieved in the previous year? क्या उपलब्धि है? 1918 मैघावाट, 2000 मैघावाट और 1050 मैघावाट के विरुद्ध आपने कितने-कितने मैघावाट के प्रोजैक्ट कमीशन किए? आपकी 2013-14 की बजट स्पीच में था जो पिछले से पिछले साल की थी Kasang Phase - I to be commissioned in the same year by HPPCL which has not been commissioned as yet. जो 2013-14 में ही कमीशन हो जाना था और अब 2015-16 शुरू होने वाला है। लेकिन वह अभी तक शुरू नहीं हुआ। आपने कहा था कि 2 मैघावाट का सोलर फोटो वोल्टिक पॉवर प्लांट काजा में सैट किया जाएगा। रवि जी, फोटो वोल्टिक आपके यहां लग गया होगा? क्या कारण हैं कि आज प्रोजैक्ट के लिए लोग अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं? आप एडवरटाईज कर रहे

23.03.2015/1545/sls-ag-2

हो। जंगी थोपन, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक लोग लड़े, उसके लिए कोई एप्लीकेशन नहीं आ रही। अध्यक्ष महोदय, 1997 तक ये 100 मैघावाट तक के प्रोजैक्ट भी वैसे ही अलॉट कर देते थे without any competition. हमने कहा कि 5 मैघावाट से ऊपर हर प्रोजैक्ट के लिए कंपीटिशन होगा, बोली लगेगी और रिसोर्स मोबिलाइजेशन होगी। खुली प्रतिस्पर्धा के बाद वर्ष 1998 से 2003 के बीच, अध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. सरकार ने 200 स्माल हाईड्रो प्रोजैक्ट अलॉट किए थे और हमें इस बात की खुशी है कि उनमें से 81 प्रोजैक्ट दिसम्बर 2012 तक कमीशन भी कर

दिए गए जो चालू हो गए थे और जिनमें उत्पादन शुरू हो गया था। बाकी के इंप्लीमैंटेशन एग्रीमैंट और पॉवर परचेज एग्रीमैंट साईन हो गए थे। अब सरकार को थोड़ा प्रो-एक्टिव होने की ज़रूरत है। अगर आप स्माल हाईड्रो को ज्यादा प्रोत्साहित करेंगे तो इससे आपको भी और प्रदेश को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। जो आज आपको फ्री पॉवर मिलती है, बोर्ड के पास जब पॉवर नहीं होती तो वह आपसे ड्रॉ करता है, उस फ्री पॉवर को आप बाहर बेच सकते हैं अगर स्मॉल हाईड्रो की पॉवर को हमारा बिजली बोर्ड खरीद ले,

जारी ..गर्ग जी

23/03/2015/1550/RG/AG/1

To be checked

प्रो. प्रेम कुमार धूमल-------क्रमागत

आपने यह भी कहा था कि वर्ष 2014-15 में City Museum and Entertainment Park for tourists and general public were proposed to be set up in Shimla. जो वर्ष 2014-15 में ही होने थे। मैं जानना चाहूंगा कि कितने सिटी म्युजियम बन गए हैं, कितने ऐन्टरटेनमेंट पार्क्स बन गए हैं? वर्ष 2015-16 के बजट में उनका कहीं जिक्र नहीं है। हवाई बातें कहीं हवा में ही तो नहीं उड़ गईं?

अध्यक्ष महोदय, मैंने टूरिज्म का जिक्र पहले ही कर दिया कि प्रदेश में विदेशी पर्यटक कम होते जा रहे हैं। धर्मशाला में टूरिज्म ऐक्शन प्लान का जिक्र वर्ष 2014-15 की बजट स्पीच में आया था। लेकिन इस बार उसका कोई जिक्र नहीं है। रोप-वेज़ का इस बार इसमें जिक्र आया है, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें काम क्या हुआ? पर्यटन विकास निगम घाटे में जा रही है। कितने होटल प्रौफिट कमा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय, हैल्थ और मैडिकल ऐजुकेशन के बारे में मैंने मंत्री महोदय, (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री) पहले भी आपसे यहां कहा था कि जब हमने 2-3 हास्पिटल में ऑऊटसोर्स किया था, तो उसका उस समय आपने विरोध भी किया, होमगाड्र्स को लगाने की बात भी की, होमगाड्र्स लगाए भी, प्राईवेट कम्पनियों के खिलाफ केस भी बनाए, लेकिन आज मैं फिर आपका (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री) बयान पढ़ रहा था कि 100 बैड से ज्यादा के जितने भी अस्पताल हैं, सबमें सिक्योरिटी ऑउटसोर्स कर दी जाएगी। जो ऑऊटसोर्सिंग वर्ष 1998 से वर्ष 2002 में गलत थी, इलीगल थी, जो प्रदेशहित में ठीक नहीं थी उसमें ऑर्ग्युमेंट दिया जाता

था कि होमगार्डस में अपने होमगार्डस में रोजगार मिलता है, तो आज क्या होमगार्डस वाले बेगाने हो गए? इसलिए इस पर पुनर्विचार करिए। यदि आज का बयान आप बदल दें, तो हमें अच्छा लगेगा कि होमगार्ड्स ही कॉन्टीन्यु करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014-15 के बजट में कहा गया था और मुझे लगता है कि शायद आइडिया तो यही होगा कि पानी की प्लास्टिक की बोतलें इस्तेमाल न हों, इसलिए वाटर ए.टी.एम्ज. लगाने की बात कही गई थी। ये कितनी जगह लगे? शिमला में तो सुना है कि एक लगा है, लेकिन बाकी कितनी जगह लगे, कितने हैं? शिमला वाला भी ऑऊट ऑफ ऑर्डर था, लेकिन आज मैंने पता किया कि वह चालू हो गया है। एक और बहुत बड़ा कनफ्युजन है "Establishment of War memorial", वर्ष 2014-15 के बजट में धर्मशाला में वार मैमोरियल के लिए दो

23/03/2015/1550/RG/AG/2

करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान है और दिनांक 18 मार्च, 2015 के बजट में कहा गया कि तीन करोड़ रुपये का प्रावधान है। हमें लगा कि पांच करोड़ रुपये से तो धर्मशाला में क्या और जगह भी बन सकता है। वहां तो पहले से ही है, लेकिन जब हमने बजट की किताब देखी, तो हैरानी हुई। पृष्ठ-84 पर मांग संख्या 4 पर देखें कि केवल एक करोड़ रुपये का प्रावधान है। What is the factual position? क्या आपने पांच करोड़ रुपये कर दिया है या अभी केवल एक करोड़ रुपये ही किया है और पिछले साल वाला दो करोड़ रुपये नहीं खर्चा, तो इस तरह तो सारा पैसा मत खर्च करो और अगले साल इतना ही बढ़ाकर और बोल दो कि इतना ज्यादा हो गया। सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और शहीदों के साथ तो ऐसा मजाक न करिए।

अध्यक्ष महोदय, हॉर्टिकल्चर के बारे में मैं कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदया भी बहुत बड़ी बागवान हैं, इनका बहुत बड़ा बगीचा है। मैडम, आपके (सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य) विभाग के बारे में कहा गया था कि one juice concentrate unit costing Rs. 15 Crore in District Shimla by HPMC will be established. 15 करोड़ रुपया लग गया, लेकिन वह कहां बना है? क्या वह रेडीमेड ही बाहर से आएगा? कोई नया यूनिट नहीं बना।

अध्यक्ष : धूमल साहब, आप कितना समय लेंगे?

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी की तीन घण्टे की बजट स्पीच थी। मैं सिर्फ पांच-सात मिनट और लूंगा, आप चिन्ता न करें। यह कहा गया कि कांगड़ा, मण्डी, ऊना, बिलासपुर----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

23/03/2015/1555/MS/JT/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जारी----------
मण्डी, ऊना, कांगड़ा और बिलासपुर में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमैंट के माध्यम से you will explore coffee cultivation. तो कहां-कहां कॉफी उत्पादन के लिए प्रयास किए गए? क्या परिणाम निकले? इसके अलावा Two Vegetable Pack Houses with an investment of Rs. 8 Crore at Ghumarwin and Nadaun in 2014-15. 2014-15 में घुमारवीं और नदौन में वेजिटेबल पैक हाउसिज बनने थे लेकिन इसकी कहीं कोई युनिट नहीं लगी है। वे कहां बनें? जबकि वे ईयरमार्क्ड थे कि वर्ष 2014-15 में बनने हैं और इस साल के बजट भाषण में इसका जिक्र ही नहीं है।

पुलिस की आप बहुत तारीफ करते हैं लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमें जो एक्स्ट्रा पे (pay)एक महीने की मिलती थी, वह 2014-15 के हिसाब से नहीं बल्कि 2012 के रेट पर दी जा रही है। होमगार्ड्ज का डैली अलाउंस भी बहुत कम बढ़ाया गया है।

शिक्षा का महकमा तो मुख्य मंत्री जी आपके पास ही है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव आया तो आपने कहा कि मैं दो बच्चों के लिए भी स्कूल खोलूंगा और बजट भाषण में आप कह रहे हैं कि अब कन्सोलिडेशन का समय आ गया है। अब कन्सोलिडेशन करो क्योंकि नये संस्थान खोलने की जरूरत नहीं है। 15 हजार से ज्यादा स्कूल हो गए हैं। आपकी कौन सी बात सच्ची है महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण वाली या बजट भाषण वाली?

मुख्य मंत्रीः दोनों सच्ची हैं।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः मुख्य मंत्री जी, आपने रेलवे लाइन्स का जिक्र किया। अच्छा होता यदि पहली बार जो ऐतिहासिक अलॉटमैंट फण्डज की हिमाचल रेलवे लाइन के लिए हुई, उसका भी जिक्र करते। आपने कहा कि भानुपल्ली-बरमाणा रेलवे लाइन के लिए 25 प्रतिशत आप देंगे। सबसे पुरानी रेलवे लाइन नंगल-तलवाड़ा-ऊना जो वर्ष 1973 से हिमाचल प्रदेश में बन रही है, उसका काम प्रारंभ किया गया था। उसके लिए पहली बार 100 करोड़ रूपया केन्द्र सरकार से स्वीकृत हुआ है। चण्डीगढ़-बद्दी के लिए 95 करोड़ रूपया स्वीकृत हुआ है। भानुपल्ली-बिलासपुर

23/03/2015/1555/MS/JT/2

रेलवे लाइन जिसके लिए आपने भी अपना शेयर देने का कमिट किया है, उसके लिए 160 करोड़ रूपये का केन्द्र ने प्रोविजन किया है। 40 करोड़ रूपये का क्योंकि आपने बजट बाद में बनाया तो आपके बजट में वह रिफ्लैक्ट होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है।

अध्यक्ष जी, मेरे बाकी साथी भी विस्तार से चर्चा करेंगे। मैंने केवल वही बातें कही जो बजट में मुझे लगा कि आपके ध्यान में नहीं आई और आपसे कहलवा दी गईं। आपने कहा कि हमने चुनाव घोषणा पत्र के अधिकांश वायदे पूरे कर दिए और मैंने बता दिया कि अधिकांश वायदे पूरे नहीं हुए हैं। मैंने फैक्ट्स और फिगर्स देकर साबित किया कि अधिकांश बातें नहीं हुई और जो घोषणाएं की गई थीं, वे भी पूरी नहीं हुई। तो आपकी ही शेरो-शायरी पर मैं फिर कह रहा हूं-

कि नज़र उनकी, जुबां उनकी,

मुख्य मंत्रीः यह तो सत महाजन जी का शेर है।

मुख्य मंत्रीः कड़सी सत महाजन जी। सत महाजन जी हमारे भी मित्र थे। उन्होंने भी किसी से इसे लिया होगा। आप लोग मेरी पूरी बात सुन लीजिए। इसका शायर कोई और है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

23.3.2015/1600/जेके/एजी/1

श्री प्रेम कुमार धूमलः-----जारी-----

नज़र उनकी ज़ुबां उनकी, मैं किसे मौन भर समझूं,
नज़र कुछ कहती है और ज़ुबां कुछ और कहती है,
वे कहते हैं, काफिला हमारा मंजिल पर पहुंचा है।

आप कहते हैं कि वायदे पूरे हो गए हैं।

वे कहते हैं कि काफिला हमारा मंजिल पर पहुंचा है,
मगर काफिले की दास्तां कुछ और कहती है।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका धन्यवाद। मैं समझता हूं कि बजट किसी सरकार का आने वाले वर्ष के लिए सबसे पवित्र डॉक्युमैंट होता है लेकिन पिछले वर्ष में जो वायदे किये गये हों, वे वायदे कितने पूरे हुए। पूरे हो जाए तो जिक्र आ जाए कि हमने यह वायदा किया था और पूरा कर दिया। अगर न हो तो यह कहा जाए कि यह काम चल रहा है। अगर किसी कारण से नहीं हो सकता है तो उस कारण की डिफिकल्टी बताई जाए कि इस वज़ह से यह काम नहीं हो सकता लेकिन कुल मिला कर इस बजट में भी पुराने वायदों को भुला कर नये वायदे करने का प्रयास किया गया। तो फिर कहा गया है किः

न अहम् है वो सियासत की नज़र में,
वायदा करके जिनको मुकरना नहीं आता।

आप मुकरने में महिर हैं, आपको यह मुबारिक। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय हिमाचल।

23.3.2015/1600/जेके/एजी/2

अध्यक्षः अब श्रीमती आशा कुमारी जी चर्चा में भाग लेंगी।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, 18 मार्च को सदन के नेता और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री, राजा वीरभद्र सिंह जी ने अपना 18वाँ बजट इस सदन में पेश किया उस चर्चा में भाग लेने के लिए आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय,मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगी कि हाल की स्थिति जो है उसके हिसाब से एक बहुत ही व्यावहारिक बजट, एक pragmatic budget है He has not tried to play to the galleries. और मुझे ऐसा लगता है कि जो बजट के बिन्दु जिसमें इन्होंने बहुत ज्यादा फोक्स किया है, वे एक अनुभवी मुख्य मंत्री को दर्शाते हैं। एक अच्छे मुख्य मंत्री का मार्क इस बजट में है और इसमें जो इनका अपना पर्सनल एजैंडा है क्योंकि ये एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वह भी इसमें दर्शाया गया है। जो स्कीम्ज इस साल इसमें इन्होंने लाई हैं और मुझे सबसे बड़ा संतोष इस बात का है कि शायद 8वीं बार मैं इस सदन में माननीय धूमल जी को बजट में बतौर नेता प्रतिपक्ष इनका भाषण सुन रही हूं। पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आज इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे थे। ये आलोचना भी नहीं कर पाए। ---(व्यवधान)--आप लोग मुझे बोलने दीजिए जब माननीय धूमल जी बोल रहे थे तो हम चुपचाप सुन रहे थे। मुझे बिल्कुल महसूस हुआ कि इनको आलोचना करने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ आंकड़ें पकड़ कर इन्होंने कुछ कहने का प्रयास किया। वे भी किसी पुराने सरकारी अधिकारी ने इनको पकड़ा दिये होंगे। जिसका ज़वाब माननीय मुख्यम मंत्री महोदय देंगें और इनको बिल्कुल संन्तुष्ट करेंगें आप लोगों को मानना पड़ेगा कि यह बेहतरीन बजट है under the circumstances. बजट के शुरू में जो यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने बात रखी और आपने भी कही कि 10 परसेंट सेन्ट्रल टैक्सिज़ में बढ़ौत्तरी हुई। आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए था। धूमल साहब आप भी 10 साल मुख्य मंत्री रहे हैं। Everything is to be taken in its full

23.3.2015/1600/जेके/एजी/3

perspective. मुख्य मंत्री महोदय ने उसके साथ-साथ आपको यह बात भी याद दिलाई कि प्लानिंग कमिशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग में मुख्य मंत्री भी सदस्य होंगे। जहां तक मैं समझती हूं कि हमारे मुख्य मंत्री भी सदस्य होंगे। लेकिन नीति आयोग के किसी भी सदस्य को यह पता नहीं है कि नीति आयोग क्या कर रहा है? इस परिप्रेक्ष्य में यह बजट पेश हुआ है, राष्ट्र का बजट

भी और उसके बाद प्रदेश का बजट भी पेश हुआ है। अगर आप राष्ट्रीय बजट की बात कर रहे थे और आप बड़े जोर-शोर से यह बात कर रहे थे कि हमें धन्यवाद करना चाहिए कि 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत हो गया। मुख्य मंत्री महोदय इस ओर से यह कहते हैं कि हमें इस बात का भी पूरा-पूरा विरोध करना चाहिए। मेरे पास पूरी सूची है। केन्द्र सरकार ने जो केन्द्र प्रायोजित स्कीम्ज थी जिनको डी-लिंक कर दिया, आप इसके बारे में क्यों चर्चा नहीं करते। ? आपने क्यों चर्चा नहीं की?

एस0एस0 द्वारा जारी---

23.03.2015/1605/SS-jt/1

श्रीमती आशा कुमारी क्रमागतः

आपने क्यों चर्चा नहीं की? ये 34 स्कीमें तो मुझे पता हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। I am just a small MLA. मैं तो सरकार का भी हिस्सा नहीं हूं। मैं अपनी सूचना के मुताबिक आपको बता रही हूं जो मुझे मालूम हैं। --(व्यवधान)-- धन्यवाद, आपकी दुआएं कभी काम आयेंगी। आपने ये ज़रूर कहा कि उनका धन्यवाद किया जाए। आपने इन चीज़ों का ज़िक्र क्यों नहीं किया? आपने ये क्यों नहीं कहा कि आप इसका धन्यवाद करो, हम दिल्ली में जो हमारी पार्टी की सरकार है --(व्यवधान)—

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि सैंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्ज़ डिलिंक कर दीं। वास्तव में ये काम मुख्य मंत्रियों की डिमांड पर हुआ है। पहले केन्द्र की सरकारें अपना कोई प्रोग्राम सोचती थीं और वह स्कीम सब स्टेटस पर थोप दी जाती थी। उसका हमने विरोध किया था। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मैदानी इलाकों के लिए कुछ और चाहिए। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए और कुछ योजना चाहिए। हमें फ्रीडम दी जाए कि हम योजनाएं अपने प्रदेश के हिसाब से बनाएं। हम केन्द्र सरकार के धन्यवादी हैं कि इस बात को माना गया और डॉ0 मनमोहन सिंह जी ने ही यह कमेटी बनाई थी। जो प्लानिंग कमीशन के सैक्रेटरी थे, वे उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने ही रिक्मेंडेशन की कि one cap does not fit all. इस करके अलग-अलग स्टेटस अपने ढंग से योजनाएं बनाएं। आपको पैसा मिल गया इसलिए स्कीमें

आप बनाओ। पैसा जो बढ़ा हुआ मिला, उसके लिए धन्यवाद करो। स्कीमों के लिए स्वतंत्रता मिल गई, यह भी हो गया तो फैडरल सिस्टम और स्ट्रॉंग हुआ।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, धूमल जी ने कहा कि स्टेटस ने यह मांग की थी। मैं जानना चाहती हूं कि किस स्टेट ने यह मांग की थी कि आधुनिकीकरण जो पुलिस का हो रहा है, जिसके लिए स्पेशल ग्रांट आती थी, वह बंद कर दिया जाए? जोकि नेशनल लेवल पर ही सम्भव है। किसी स्टेट के पास इतनी नॉलेज ही नहीं है कि वह डिवैल्प कर सके कि पुलिस को आधुनिकीकरण के लिए क्या-क्या ज़रूरत है। पूरे देश में 6 हजार मॉडल स्कूल्ज़ बन रहे थे, कौन-सा प्रदेश ऐसा है जो यह कहेगा कि इसको डिलिंक कर दिया जाए? धूमल साहब, जब आप बोले तो मैंने कुछ नहीं कहा। कौन-सा ऐसा प्रदेश है जो यह कहेगा कि 10 परसैंट शेयर बढ़ा दो और

23.03.2015/1605/SS-jt/2

20 परसैंट के करीब जो सैंट्रल स्कीम्ज़ आ रही हैं उतना फंड कम कर दो? आपने जो बढ़ाया है, मुख्य मंत्री आपको बतायेंगे और बताया भी है, मैं बजट से बोल रही हूं। फिर आपने सी0एम0 साहब की बजट स्पीच देखी नहीं कि कितना आपको इंक्रीज हुआ है और कितना आपको नुकसान हुआ है। आपको पांच साल में लगभग 20 से 25 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। आपको आया कितना है? आप बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला। पर आपने यह कहा कि धन्यवाद करें। सवाल यह है कि धन्यवाद किस बात का करें। पहले धन्यवाद राहुल गांधी का करेंगे। राहुल गांधी फार्मर्ज़ का लीडर है। आपकी तरह पूंजीपतियों का नहीं। आप पूंजीपतियों के नेता हैं। आप लोग पूंजीपतियों के नेता हैं। आपने सैंट्रल बजट में पूंजीपतियों के लिए 5 परसैंट टैक्स कम किया और सर्विस टैक्स 2 परसैंट बढ़ाया। आप पूंजीपतियों के नेता हैं। आप रहने दीजिए। राहुल गांधी जी फार्मर्ज़ के नेता हैं। इसलिए आप फार्मर्ज़ के लिए जो लैंड अधिग्रहण बिल है, जिस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहती, आज आप उसके प्रोविजन्ज़ को चेंज करके किसानों की जमीनें पूंजीपतियों के हाथ करना चाहते हैं। वह आपकी सोच है और रहेगी। वह है और रहेगी। ..(interruption).. Speaker, Sir, please tell them not to interrupt me. क्यों बुरा लग रहा है? बुरा इसलिए लग रहा है कि आपकी सच्चाई सामने आ रही है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि कारपोरेट टैक्स 30 परसैंट से 25 परसैंट किया और सर्विस टैक्स जोकि पूरे हिन्दुस्तान पर लगता है वह 2 परसैंट बढ़ाया। साथ में जेटली जी ने क्या कहा? How am I worried about

middle class? They should look after themselves. ये आपकी सोच है। मैं इस पर बोलना नहीं चाहती थी। आप मुझे बजट पर बोलने दीजिए। आपकी नीतियों पर मैं बोलना नहीं चाहती। आप पूंजीपतियों की कठपुतलियां हैं। अध्यक्ष महोदय, ये जो बजट पेश हुआ है इसके जो मुख्य बिन्दु हैं उसके लिए मैं निश्चित तौर पर मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगी।

जारी श्रीमती के0एस0

23.03.2015/1610/केएस/जेटी/1

श्रीमती आशा कुमारी जारी----
यह जो बजट पेश हुआ है, इसके लिए मैं निश्चित तौर पर मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगी।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो "कठपुतली "शब्द का इस्तेमाल किया है यह असंसदीय शब्द है अतः इसको कार्यवाही से निकाला जाए।

श्रीमती आशा कुमारी : अब क्या हुआ? I am not yielding to you. I am yielding to your leader.

Speaker: Please don't indulge in arguments. ऑर्गुमैंट न कीजिए। Let her speak. आपकी बारी आएगी तो आप बोल लेना। ---(व्यवधान) -- Please don't indulge in arguments when somebody is speaking. जब मैम्बर बोल रहे हैं तो आप बीच में इंट्रप्ट मत कीजिए। जब आपकी बारी आएगी तो बोल लेना ।---(व्यवधान)—

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, न पूंजीपति शब्द असंसदीय है और न ही कठपुतली शब्द असंसदीय है ।

Chief Minister: Everybody has heard Dhumal Sahib with pin drop silence. और आज इनके लोग हमारी महिला वक्ता को डिस्रप्ट कर रहे हैं।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, ये मान-सम्मान जानते ही नहीं है। ---(व्यवधान)---

23.03.2015/1610/केएस/जेटी/2

Speaker: Bhardwaj Ji, you should not interrupt inbetween the speech. हम बोल रहे हैं कि आपको समय मिलेगा तो आप बोल लेना। When you will get time, then you speak.

Smt. Asha Kumri: Speaker, Sir, neither is the word "*Poonjipatti"* unparliamentary, nor is the word *"Kathputli"* unparliamentary.

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, सारे विधायकों को कठपुतली कहा जा रहा है इसका क्या मतलब होता है?

Speaker: You reply when the time comes for you to speak. आपको समय मिलेगा, तब बोल लेना। Please don't interrupt when somebody is speaking.
Shri Suresh Bhardwaj: Sir, she has used the word "*Kathputli".*
श्रीमती आशा कुमारीः तो उसमें क्या अनपार्लियामेंट्री है, धूमल साहब ? कठपुतली में क्या अनपार्लियामेंट्री है? --(व्यवधान)-- अध्यक्ष महोदय, मैंने पार्टी की सोच के बारे में बोला, about their thinking. I am not talking about your M.L.As. I am talking about the thought process of your party.
श्री सुरेश भारद्वाजः आपने कहा कि आप कठपुतली है। अध्यक्ष महोदय, यह असंसदीय है इसलिए इसको डीलीट किया जाए। ----(व्यवधान)—

23.03.2015/1610/केएस/जेटी/3

श्रीमती आशा कुमारीः हम तो मानते हैं कि हम अपनी पार्टी की कठपुतली है। -----

(व्यवधान)-- Speaker, Sir, can I continue? ..(interruption)..

Speaker: Please sit down.

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, शुरूआत से ही अगर हम देखें जो मेन प्वाइंट्स बजट के अन्त में दिए गए हैं, एच.आर.टी.सी. की बसों में जो फ्री सुविधा दी जाती है, उसके लिए मुख्य मंत्री महोदय बधाई के पात्र है कि यह आपने केन्द्रीय विद्यालयों के बच्चों के लिए भी एक्सपैंड की है। इसके साथ-साथ ही 800 बसें JNNURM के तहत एच.आर.टी.सी. को आ रही है मगर यह भी दुख का विषय है कि जो चीजें सैंट्रल एड के लिए डीलिंक हुई है उसमें JNNURM भी एक है। It has been delinked. बसें हमारे समय में मिल गई थी, धन्यवाद है हमारी सरकार का वरन् अगर आज का इंतजार करते तो आज तो डीलिंक हो चुकी थी। हम यू.पी.ए. सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं जिनकी वजह से आज हमें ये बसें मिल रही है। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी की सोच को आगे बढ़ाते हुए

23.03.2015/1610/केएस/जेटी/4

होर्टिकल्चर और एग्रिकल्चर सैक्टर को आगे बढ़ावा देने के लिए स्कीमें इंट्रोड्यूस की गई हैं, ये सराहनीय हैं। बहुत सारी स्कीमें हैं, अगर इन सब का नाम लेने लगे तो काफी समय लग जाएगा मगर इसमें विशेष करके जो ऑफसीज़न वेजिटेबल्ज़ के लिए आपने प्रावधान किया है यह सराहनीय है। वैटरीनरी डिपार्टमैंट से सम्बन्धित चारा को बढ़ाने का जो आपने प्रोविज़न किया है, यह भी सराहनीय है क्योंकि जब तक हमारा किसान वापिस खेतों की ओर, डेयरी फार्मिंग की ओर नहीं जाएगा तब तक हालांकि यह ठीक है, जैसा कि अभी विपक्ष की तरफ से कहा गया कि हमारी परकैपिटा इन्कम एक लाख से ज्यादा हो गई है और आपने यह भी कहा कि प्रसेंटेंज के हिसाब से अगर देखें तो आपके समय में ज्यादा हुई, निश्चित तौर पर होनी थी क्योंकि उसी समय नरेगा आई। जब मनरेगा आई तो जो पर-केपिटा इन्कम है वह बढ़ी तो निश्चित तौर पर वहां पर यू.पी.ए. की सरकार थी, यहां आपकी सरकार थी तो वह भी यू.पी.ए. सरकार की उपलब्धि है न कि आप की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

23.3.2015/1615/jt/av/1

श्रीमती आशा कुमार जारी--------

स्किल डिवैल्पमैंट के बारे में आपने बहुत चर्चा की है। मुझे लगता है कि धूमल साहब, आपको जितना मैनिफैस्टो हमारा याद है उतना अपना भी याद नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार जिसका नेतृत्व माननीय वीरभद्र सिंह जी कर रहे है; ये अपने मैनिफैस्टो

को पूरा करने के लिए पूरी तरह से वचनवद्ध है। यहां जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि हिमाचल के लोगों ने जो इस बार हमें 5 साल का समय दिया है उसमें हम पूरा करेंगे और अगला मैनिफैस्टो बनाकर के अगले 15 साल भी हम ही पूरा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, स्किल डिवैल्पमैंट की बात हो रही थी। मैं स्किल डिवैल्पमैंट के लिए मुख्य मंत्री जी और आपके मंत्री मंडल के सदस्यों को बधाई देना चाहती हूं कि आपने हिमाचल प्रदेश में जो स्किल डिवैल्पमैंट की स्कीम चलाई आज राष्ट्र में उसी स्कीम को अडोप्ट किया गया है। (---व्यवधान---) बिल्कुल उल्टा नहीं है। आपके केंद्रीय बजट में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए जो नई अनाउंसमैंट हुई है, भारद्वाज साहब, मैं आपको बता दूं कि उसमें दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के नाम से हुई है जिसका नाम यू.पी.ए. सरकार के समय में स्किल डिवैल्पमैंट स्कीम था। आप यह मत कहिए कि यह उल्टा है, यह सीधा है। यहां से शुरु हुई और वहां गई। आपको मानना पड़ा कि हिमाचल सरकार की स्कीमों में पूरा दमखम है। धूमल साहब, आप अनइम्प्लॉयमैंट भत्ता की बात कर रहे थे। यह तो आप भी मानेंगे कि यह एक तरह का अनइम्प्लॉयमैंट भत्ता-कम-स्किल डिवैल्पमैंट अगर इकट्ठा हो जाये तो यह हमारे देश के नवयुवकों के लिए ज्यादा अच्छा होगा। अगर हमें उनको एक हजार रुपये भत्ता देना है और साथ-साथ में उनका कोई स्किल डिवैल्प हो जाए, जिससे उनको रोजगार भी मिल सके तो इसको मैं कोई बुरी बात नहीं समझती। मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन जरूर करुंगी। हमने यह बात सदन के अंदर और सदन के बाहर भी आपके मंत्री से बहुत बार उठाई है कि स्किल टीचिंग के नाम से बहुत सारी शॉप्स चल पड़ी है। उसमें कुछ फ्रॉड थी जिसमें कुछेक

23.3.2015/1615/jt/av/2

में ऐक्शन भी हुआ है और एफ.आई.आर. भी दर्ज हुई हैं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जो आपके इण्डस्ट्रियलिस्ट इण्डस्ट्री लेकर आ रहे हैं या जो इण्डस्ट्रीज लग रही हैं उनकी जो वेकेंसीज हैं उनके साथ स्किल ट्रेनिंग को जोड़ने का प्रयास करें। आप एक हजार रुपये सरकार की ओर से दें और जिस ट्रेड के लिए कम्पनी को उसकी जरुरत है वहीं उनको ट्रेनिंग के लिए ऐप्रैंटिसशिप के लिए भेज दिया जाए ताकि उनको आगे जाकर वहीं नौकरी मिल सके। मेरा आपसे यह एक सुझाव रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है एक पूरा सैशन विपक्ष वाले यहां आए ही नहीं थे। ये सुजानपुर में एक रैली की तैयारी कर रहे थे। (---व्यवधान---) लगभग, लगभग। आप तैयारी कर रहे थे। अच्छी बात है, अपने नेताओं के लिए तैयारी करनी भी चाहिए। उस रैली के बाद आप सत्ता में भी आ गए। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि जब वह रैली हुई थी तो इनके वे बड़े नेता तब मुख्य मंत्री थे और अब प्रधान मंत्री है। उन्होंने उस वक्त कहा था कि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है। बहुत अच्छा राज्य है। मगर जो हिल स्टेट होती है इनकी अपनी समस्याएं होती हैं। इनके लिए अलग सोच होनी चाहिए। बहुत अच्छी सोच की जो हमें स्पेशल स्टेट्स मिला हुआ था उसको खत्म कर दिया गया। (---व्यवधान---) खत्म कर दिया। (---व्यवधान---) हम कह रहे हैं कि खत्म कर

दिया। आप साबित कर दीजिए कि नहीं किया। (---व्यवधान---) खत्म ही कर दिया। हम कह रहे हैं कि खत्म कर दिया और आप साबित कीजिए कि नहीं किया। आप वापिस उसको रैस्टोर करवा दीजिए, हम उसमें आपका सहयोग मांगते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इनको बाद में भेज दूंगी जो स्कीमें डीलिंक्ड हुई हैं। ये बहुत सारी स्कीमें हैं। अगर मैं इनको यहां पढूंगी तो बहुत समय लगेगा। मगर आपकी अनुमति से एक-दो का जिक्र करना चाहूंगी जैसे जवाहर लाल शहरी नवीनीकरण योजना, सामान्य केंद्रीय सहायता, अन्य अतिरिक्त केंद्रीय सहायता, विशेष केंद्रीय सहायता और 20 नम्बर पर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता। यह मैं नहीं बोल रही हूं, यह इनका केंद्रीय बजट बोल रहा है। (---व्यवधान---) मैं आपको दे दूंगी।I will send it to you. (---व्यवधान---) no, no. स्पेशल केटेगरी और हिल भी; मैं यह सब सोच की बात कर

23.3.2015/1615/jt/av/3

रही हूं। स्पेशल केटेगरी तो मैंने आपसे कहा ही कहा कि हमारा यह कहना है कि स्पेशल केटेगरी का स्टेटस तो खत्म ही है क्योंकि उसका जीरो बजटिंग है और सैंट्रल बजट में उसका कोई जिक्र नहीं है।-----

श्री बी.जे.द्वारा जारी

23.3.2015/1620/negi/ag/1

श्रीमती आशा कुमारी... जारी...

उसका सेन्टर बजट में कोई जिक्र नहीं है। हमारा यह भी कहना है कि हिल स्टेट्स के प्रति जो एक सोच थी उसको भी आपने डिलिंक कर दिया । हिल स्टेट्स तो थोड़े से ही हैं। नोर्थ-ईस्ट स्टेट्स को डिलिंक नहीं किया क्योंकि उनके लिए अलग मंत्रालय है, यह आप भी जानते हैं, आप सांसद रहे हैं और मुख्य मंत्री रहे हैं। आपको मैं समझा नहीं सकती, सिर्फ आपको याद दिला रही हूं। आप जानते हैं कि मैं जो कह रही हूं ठीक कह रही हूं। अगर आप इस बात पर मुझे असत्य साबित करेंगे तो मेरे से ज्यादा खुश और कोई नही होगा। अगर हिमाचल प्रदेश का स्पैशल कैटेगरी स्टेटस बना रहे we will equally be happy.

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने कुछ चीज़ें बजट में रखी। ये 3 LED बल्ब की बात कर रहे थे कि 10 रूपये लेना नहीं चाहिए। वो सरकार का अपनी सोच है। मैं इनको बधाई देना चाहूंगी कि इन्होंने एल.ई.डी. बल्ब पर वैट 13.75 परसेन्ट से कम करके 5 परसेन्ट कर दिया। मेरा तो यह सुझाव रहेगा कि आप एल.ई.डी. बल्ब पर से वैट हटा ही दीजिए। क्योंकि यह एक पावर सेविंग डिसीजन है। अगर आप इसको हटा भी दें तो मैं नही समझती कि इसका कोई नुकसान होगा। आप जितना

पावर सेव करेंगे It is directly proportional to the relief you give. So, I request you to consider it और इसको एबॉलिश ही कर दीजिए only on LED.

आपने क्रैश बैरियर्ज़ के लिए 50 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया है, यह बहुत ही सराहनीय कदम है। हमारे इलाकों में खासकरके जो अपर हिल्ज़ हैं वहां पर बहुत ज्यादा एक्सीडेन्ट्स होते हैं, वहां पर इसका बहुत फायदा होगा। जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स एच.आर.टी.सी. ने आईडेन्टीफाई किए हैं और पी.डब्ल्यू.डी. ने आइडेन्टीफाई किए है, इन ब्लैक स्पॉट्स में ये लगेंगे तो निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा।

23.3.2015/1620/negi/ag/2

इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से मुख्य मंत्री महोदय को बहुत ज्यादा बधाई देना चाहती हूं क्योंकि एक exclusive college for visual and fine arts आप सैटअप करने जा रहे हैं, इस तरह से आप पूरे हिमाचल प्रदेश की जो कल्चर है, संस्कृति है इसको आप बचाएंगे, बढ़ाएंगे, पूरा हिमाचल प्रदेश आपका ऋणी रहेगा और धन्यवाद करता है।

Speaker: Kindly wind-up.

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष जी, आधा समय तो मेरा भारद्वाज़ भाई ने ही ले लिया है और इनका आधा समय मुझे ट्रांसफर हो गया।

अध्यक्ष महोदय, एक इन्होंने अपने बजट में रखा है कि Study on Hill Towns through PPP Mode. अध्यक्ष महोदय, यह समय की पुकार भी है क्योंकि हमारे जो शहरी इलाके हैं, टाउन्ज़ हैं इनकी जो मिस-मैनेजड प्लानिंग है इससे हमें बहुत नुकसान हुआ है। जो हो चुका है वो हो चुका है, जहां नहीं कुछ बनना चाहिए था, जो इनक्रोचमैन्टस हुई हैं वे रेगुलराज्ड हो गया है। मगर आगे आने वाले समय में कम से कम इन हिल टाउन्ज़ का अगर आप स्टडी करेंगे और उस स्टड़ी को उसके बाद लागू करेंगे तो हमारे शहरों में डेफिनेटली फायदा होगा।

आपने माइनोरिटीज़ के डिवलपमैन्ट के लिए 2 करोड़ रूपये का फंड रखा इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। आपने डेलीवेज़र्ज़ की दिहाडी 170/- रूपये से बढ़ा कर 180/- रूपये किया । धूमल साहब का कहना है कि इसको और बढ़ा देना चाहिए। मैं इसपर ज्यादा नहीं कहना चाहती लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगी कि यह सब आपको अपने समय में कर लेना चाहिए था। अगर आपको इतना था तो आप अपने समय में यह कर लेते। हम कर रहे हैं । आप दिहाड़ी 200/- रूपये करना चाह रहे हैं, यह आप कर लेते। हम तो कर देंगे। मुख्य मंत्री जी इसको बढ़ा रहे हैं । जो हमारा मैनीफैस्टो है उसको हम पूरा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

23.3.2015/1620/negi/ag/3

आपने पार्ट-टाईम वर्कर्ज़ को जो राहत दी है इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। पार्ट-टाईम कर्मचारी 8 साल पूरे करने पर डेलीवेज़र्ज़ बन जाएंगे । जो डेली-वेज़र्ज़ जिन्होंने 31 मार्च तक 7 साल पूरे कर लिए हैं वे रेगुलराइज्ड हो जाएंगे। अनुबन्ध कर्मचारी, बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल इम्प्लॉइज़ हैं जो प्रदेश में लगे हुए हैं जो कि सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से सिलेक्ट हो करके आए हैं, नार्मली वे रेगुलर लगते थे। मगर कुछ इस तरह की पॉलिसी बनी कि वे कॉन्ट्रैक्ट पर लगे। आपने कान्ट्रैक्चुअल पीरियड 5 साल का कर दिया इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। यह भी हमारे मैनीफैस्टो का हिस्सा था। धूमल जी को पता है वह हमारे मैनीफैस्टो को हमसे अच्छा जानते हैं।

इसी तरह से आपने सरकारी आवास एडिशनल बजट प्रोविजन किया । अध्यक्ष महोदय किसी भी सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि जो गवर्नमैन्ट सर्वेन्ट्स हैं उनकी रहने की सुविधा अच्छी हो। जो बजट है...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

23.03.2015/1625/यूके /एजी/1
श्रीमती आशा कुमारी ---जारी ----

जो बजट है उसके over and above आपने 30 करोड़ दिया और उसके अलावा जो बिल्डिंग को restore and renovate करने के लिए आपने 15 करोड़ रखे, यह भी यह सराहनीय कदम है ।

अध्यक्ष महादेय, एक आपने जो ऑफ सीज़न वेजिटेबल्ज के लिए 7 करोड़ रखे हैं, यह जो Establishment of Centres of Excellence for Vegetable Nursery Production यह हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास कर के उन इलाकों के लिए जहां पर ऑफ सीज़न वेजीटेबल्ज़ का काम बहुत ज्यादा है । जैसे कि हमारा सलूणी और तीसा का इलाका है उसमें फ्लोरिकल्चर और वेजीटेबल्ज़ वगैरहा का काफी काम है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी और सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि जब यह पैसा लगे तो जहां इसकी जरूरत है, जहां यह काम होता है वहां यह पैसा बिना भेदभाव के लगाया जाए ।

अध्यक्ष महोदय, पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए आपने 109 करोड़ रुपए की ग्रांट दी है, उसके अलावा 195 करोड़ रुपए 14वें वित्तायोग की सिफारिशों के मुताबिक उनको मिलेगा । हमारे पंचायतें सबसे छोटी इकाई जरूर हैं मगर सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं और इनको सुदृढ़ करना हमारा कर्तव्य भी और फर्ज भी है ।

अध्यक्ष महोदय, ये जो बजट यहां पेश हुआ हम इसको वैलकम करते हैं, विशेष कर के मैं मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगी

23.03.2015/1625/यूके /एजी/2

कि आपने विधायकों की निधि 50 लाख रूपए से 20 लाख रूपए और बढ़ा कर के 70 लाख रुपए कर दी है । यही एक बात है, जिसमें मैं धूमल साहब के साथ एग्रीमैंट में हूं कि इस 20 लाख रुपए को को टाई-अप मत कीजिए।

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

इसका मिस्सयूज़ ज्यादा होगा क्योंकि अगर हम टैंक्स बनाने के बात करेंगे तो यदि किसी ने मनरेगा में टैंक बनाया होगा, या किसी अन्य योजना में बनाया होगा तो वह इसी के लिए ले जायेगा । इसको दिखा कर के और वह हो जायेगा । यह व्यवहारिक नहीं है, इरिगेशन के साथ व्यवहारिक नहीं है ।

मुख्य मंत्रीः इस पर विचार किया जायेगा ।

श्रीमती आशा कुमारीः किसी और चीज़ के साथ (व्यवधान) मोदी जी ने दो रूपए दिए और तीन रूपए ले लिए। मोदी जी की बात मैं नहीं करूंगी, फिर आप नाराज हो जाओगे। मोदी जी ने जेब से निकाल कर दो रूपए दिए और हमारी जेब से निकाल कर 3 रूपए ले लिए। मोदी जी की चर्चा मैं नहीं करूंगी। क्योंकि अब बहुत अच्छे दिन आ गए हैं, इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि मैं उसकी चर्चा ही नहीं करना चाहती। अगर आप मुझे छेड़ोगे तो फिर मैं बोलूंगी और यदि मैं बोलूंगी तो फिर आप गुस्से हो जाओगे। (व्यवधान) आप बात नहीं कर रहे हैं, आप राजनैतिक छेड़छाड़ कर रहे हैं। पर्सनल छेड़छाड़ नहीं आप राजनैतिक छेड़छाड़ कर रहे हैं

23.03.2015/1625/यूके /एजी/3

और राजनैतिक छेड़डाड़ करेंगे तो राजनैतिक जवाब भी मिलेगा। आप धूमल साहब से सीखों कि भाषण कैसे देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो 18वां एतिहासिक बजट 18 तारीख को इस विधान सभा में पेश हुआ है, यह एक परैगमैटिक बजट है, यह कोई पॉपुलिस्ट बजट नहीं है मगर फिर भी टैक्स-फ्री बजट है। There is a difference between a populist budget and जिसमें डोल(Dole) दिए जाएं, ये हमारे हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग के लोगों की चाहे किसान है, बागवान है, चाहे वह कर्मचारी है, यूथ है, आपने 5,000 जॉब्ज़ of functional posts. उनको भरने का भी जिक्र किया है। यूथ है, स्किल डवेलपमैंट है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है, जो इसमें छोड़ा गया हो। मैं इसके लिए मुख्य मंत्री महोदय को और इनकी सरकार को बधाई देती हूं और पूर्ण समर्थन करती हूं।
उपाध्यक्षः श्री प्रेम कुमार धूमल जी।

23.03.2015/1625/यूके /एजी/4

श्री प्रेम कुमार धूमलः उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मुद्दों पर बात करूंगा। माननीय सदस्य ने स्पेशल केटेगरी स्टेट के स्टेटस के बारे में जिक्र किया। माननीय मुख्य मंत्री ने भी धन्यवाद प्रस्ताव पर इसका जिक्र किया था। वे जानते हैं कि स्पेशल केटेगरी स्टेटस जो है, यह Government of India की नोटिफिकेशन से मिलता है। अधिसूचना जारी होती है, जैसे बिहार वाले कह रहे हैं।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

23.03.2015/1630/sls-ag-1
प्रो० प्रेम कुमार धूमल ...जारी

आज तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कि इसको विदड्रा कर लिया हो। कुछ स्कीम्ज का आप ज़िक्र कर रहे थे। मैंने पहले ही कह दिया कि जब पैसा फ्री दे दिया तो उसमें आप स्कीम्ज को इंम्लीमैंट करो। लेकिन as such अगर स्टेटस की वो बात हुई होती तो KFW का 341 करोड़ रुपये का जर्मनी से जो लोन आना है, जिसमें 90% ग्रांट होगी, that is special category status कि लोन विदेश से आएगा। उन्होंने तो पूरा वापिस लेना है लेकिन इसमें 10% हिमाचल देगा और 90% भारत सरकार वापिस देगी। दूसरा, आपने (श्रीमती आशा कुमारी) कहा कि दिहाड़ी और बढ़ा दी। दुर्भाग्यवश आप पिछली बार हमारे साथ यहां नहीं थी। ...(व्यवधान)... हम तो इस बार भी कोशिश करते लेकिन आप आ गई हैं।

हमने दिहाड़ी 75 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये की थी; दुगुनी की थी। हम तो चाहते हैं कि अब आप इसे 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये करो। हम यह मांग कर रहे हैं।

23.03.2015/1630/sls-ag-2

उपाध्यक्ष : अब डॉ० राजीव बिन्दल जी चर्चा में भाग लेंगे।
डॉ० राजीव बिन्दल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2015-16 का जो बजट प्रस्तुत किया, उस पर विचार रखने के लिए आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्य मंत्री जी का इस बार यह तीसरा बजट है। मैं 2013 के बजट की तरफ नज़र दौड़ा रहा था। (मुख्य मंत्री जी से) माननीय मुख्य मंत्री जी, आप 15 मिनट मुझे सुन लें तो अच्छा रहेगा।
मुख्य मंत्री : मैं आपको सुनूंगा।
डॉ० राजीव बिन्दल : धन्यवाद।

वर्ष 2013 के बजट में बहुत ज़ोर-शोर के साथ आपने श्रीमती सोनिया गान्धी जी का, श्री राहुल जी का और माननीय प्रधान मंत्री जी का गुणगान किया था। गुणगान करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन गुणगान के आगे इस बात का कोई

ज़िक्र नहीं किया कि उन्होंने कौन-सी ऐसी विशेष सहायता हिमाचल प्रदेश की सरकार को दी जो लगातार कर्जे में डूब रही थी। उस सरकार को कौन-सी ऐसी चीज दी जिसको लेकर आपने उनका धन्यवाद किया? अच्छा किया कि उनको स्मरण किया। वर्ष 2014 में भी स्मरण किया पर जब 2015 की बारी आई तो माननीय मुख्य मंत्री जी देश के माननीय प्रधान मंत्री, जो इस समय दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पापुलर लीडर हैं, उनका नाम तक लेना भूल गए और उनकी चर्चा करना भी भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि पहली बार हिमाचल प्रदेश को रेलवे बजट में 350 करोड़ रुपये दिए, इसलिए उनका नाम भूल गए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय प्रधान मंत्री जी के साथ अन्याय नहीं है, हिमाचल प्रदेश के लिए सहयोग करने वाला जो कोई केंद्र में बैठा हुआ नेता है, उसके साथ और हिमाचल के साथ अन्याय है।

23.03.2015/1630/sls-ag-3

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2013 में स्वर्गीय डॉ० यशवन्त सिंह परमार जी को भी याद किया था। अब उनको भी भूल गए। 2014 में भी और 2015 में भी भूल गए। वर्ष 2015 में केवल अपने गुणगान से काम शुरू हुआ। माननीय उपाध्यक्ष जी, क्यों माननीय मोदी जी का नाम नहीं आना चाहिए? कर्जे में डूबती हुई सरकार, लगातार कर्जे-पे-कर्जा लेती हुई सरकार, जिसके ऊपर अंकुश लग गया कि अब और कर्जा नहीं ले सकती; हर महीने यह ख़बर आती थी कि अब कर्मचारियों को तरख्वाह नहीं मिलेगी, उस सरकार को 14वें वित्तायोग के अंदर 42000 करोड़ रुपये का तोहफा जिस प्रधान मंत्री ने दिया, उसका नाम लेना भूल गए। धूमल जी की सरकार को पांच साल के अंदर यू.पी.ए. सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 7800 करोड़ रुपया दिया था और आपकी सरकार को पांच साल के अंदर 42000 करोड़ रुपये दिया। उसके बाद भी आप उनका नाम लेना भूल गए, ये बड़ी चिंता की बात है। अब तो माननीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार की बल्ले-बल्ले है। आप जितने मरज़ी पुल बना सकते हैं, जितनी मरज़ी सड़कें बना सकते हैं, हजारों कर्मचारी रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इतना पैसा कांग्रेस की सरकार को मोदी की सरकार ने दे दिया है। मैं यहां कहना चाहूंगा, दर्ज़ करवाना चाहूंगा कि इसके बाद भी अगर कर्मचारियों की भर्ती नहीं होती और सड़कें नहीं बनती, पेयजल योजनाएं नहीं बनती हैं तो इससे ज्यादा

निकम्मी सरकार कोई नहीं होगी। पैसे दिल्ली ने भरपूर दिए हैं, केवल इस्तेमाल करने की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे।

जारी..गर्ग जी

23/03/2015/1635/RG/JT/1

डॉ. राजीव बिन्दल--------क्रमागत

और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे। यदि आपने मोदी जी का नाम नहीं लेना है, तो न लें, लेकिन देश और प्रदेश की जनता तो उनका नाम ले रही है। उनका नाम नहीं लेना चाहिए, कहीं क्रेडिट न ले जाएं। इण्डियन इंस्टीटियुट ऑफ मैनेजमैंट दे दिया, फटाफट कार्रवाई हो रही है, वहां से दल आ रहे हैं, वहां से भूमि का चयन हो रहा है और इसी साल आई.आई.एम. की क्लासेज लगने वाली हैं। माननीय बाली जी, मंत्री महोदय आ गए, इनका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब बाली तह का विभाग है, तो मोदी जी का धन्यवाद तो करना चाहिए। ऐम्स आ गया। ये मेरे चुनाव क्षेत्र नाहन में गए थे, तो इनका इस्तक़बाल तो करना ही था। मोदी जी तो ऐम्स पिछले साल दे रहे थे। डॉ. हर्ष वर्धन जी ने पत्र लिखा कि ऐम्स ले लो, मैं दे रहा हूं, तो एक मंत्री जी ने कहा कि यह कांगड़ा में बनेगा, दूसरे ने कहा कि शिमला में बनेगा, तीसरे ने कहा कि मण्डी में बनेगा और चौथे मंत्री कहते हैं कि अभी मैं जगह ढूंढ रहा हूं। तो इस तरह पिछला साल बर्बाद हो गया। इस साल ऐम्स दे रहे हैं, तो उनका धन्यवाद तो करना ही चाहिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अब बिलासपुर में हो गया।

डॉ. राजीव बिन्दल : तो बहुत अच्छा हो गया। अब मैडिकल कॉलेजिज के लिए पिछली सरकार 189 करोड़ रुपये प्रति कॉलिज के लिए घोषणा कर गई। कागज़ के टुकड़े पर घोषणा कर दी। सरकार चली गई और स्वास्थ्य मंत्री भी अपना चुनाव हार गए। परन्तु मिला कुछ नहीं। घोषणाएं होती रहीं, कह दिया, दे दिया। परन्तु अब आकर माननीय नड्डा जी को वह पैसे देने पड़ेंगे। इसके लिए उनका धन्यवाद तो करते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013 में कहा, मैं यह बताना चाहता हूं कि इन्होंने क्या-क्या कहा और क्या-क्या किया! वर्ष 2013 में कहा कि 50,000 बेरोजगार लोगों को हम उद्योगों के माध्यम से रोज़गार देंगे। तो वे 50,000 रोजगार तो कहां देने

थे, 149 औद्योगिक इकाइयां बन्द हो गईं जिससे 50,000 लोग और बेरोजगार हो गए। इससे रोजगार का तो सूपड़ा ही साफ हो गया। आपने कहा कि कौशल विकास भत्ता शुरू होगा और उसके माध्यम से हम रोज़गार का सृजन करेंगे, लेकिन आज तक एक भी रोज़गार का सृजन कौशल विकास भत्ते के माध्यम से नहीं हुआ। वर्ष 2013, 2014 और अब वर्ष 2015 आ गया, लेकिन एक भी व्यक्ति को उस कौशल

23/03/2015/1635/RG/JT/2

विकास भत्ते के प्रशिक्षण के माध्यम से रोज़गार नहीं मिला। मैं चुनौती के साथ यह बात कहना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने वर्ष 2012 में कहा कि हम भत्ता देंगे, वह भत्ता तो गायब हो गया और वर्ष 2015 के बजट में भी भत्ते का कोई जिक्र नहीं है। इस प्रकार 12,00,000 बेरोजगार नौजवान आपको जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। वर्ष 2013 में कहा गया कि हम आई.टी. पार्क बनाएंगे और इलैक्ट्रॉनिक्स क्या-क्या मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर्ज बनाएंगे और बहुत कुछ कहा, लेकिन आज तक वह आई.टी. पार्क पता नहीं कहां है और वे इलैक्ट्रॉनिक वाले जो आई.टी.आई. कर लेते हैं, कोई बी.सी.ए. या एम.सी.ए. कर लेते हैं, वे सारे सड़क पर हैं, किसी के लिए कोई रोजगार नहीं है। न कोई पार्क बना, न कोई आई.टी. बनी और इस बार फिर लिख दिया कि हम कुछ और बनाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 में कहा गया कि 80,000 लोगों को कौशल विकास भत्ते के माध्यम से रोज़गार देंगे। मैं उसके नंबर लिखकर लाया हूं, प्वाइंट नंबर कौन सा है? 80,000 लोगों को रोज़गार देंगे, पहले 50,000 लोगों को रोज़गार दे रहे थे, फिर 80,000 लोगों को दे रहे थे, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं मिला।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार बजट की बात करती है, वर्ष 2014 में आपने कहा कि हम भाखड़ा ब्यास मैनेजमैंट बोर्ड का 7.19% प्राप्त करके रहेंगे, कुछ भी हो जाए हम पैसा लेंगे। आपने क्या फौलो अप किया कि हमारा चार हजार करोड़ रुपया डूब गया। हिमाचल प्रदेश की जनता को माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में जवाब क्यों नहीं दिया कि हमारा चार हजार करोड़ रुपया कहां गया और वह चार हजार करोड़ रुपया क्यों नहीं मिला? इसका जवाब हिमाचल प्रदेश की जनता को देना पड़ेगा। बाली जी, आप सुन लीजिए, यह आंकड़ा बहुत जबरदस्त है। वर्ष 2013-

14 में कहा गया कि हम 1918 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे, वर्ष 2014-15 कहा कि हम 2000 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे और अब वर्ष 2015-16 के बजट में कह रहे हैं कि 1050 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

23/03/2015/1640/MS/JT/1

डॉ0 राजीव बिंदल जारी----------

वर्ष 2014-15 में कहा कि 2 हजार मेगावाट पैदा करेंगे और वर्ष 2015-16 में कहा कि 1050 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। मैं टोटल कर रहा था कि कितना बना तो मैंने देखा कि यह लगभग 5 हजार मेगावाट बना और अभी इसी बजट में बता रहे हैं कि हमने 956 मेगावाट बिजली पैदा कर दी है। 5 हजार में से 956 मेगावाट बिजली पैदा कर दी, उसका आंकड़ा दिया है और वह भी पता नहीं धूमल जी के समय वाली फिगर मिलाकर बता दी हो। आप क्या लक्ष्य प्राप्त करने जा रहे हैं और क्या बता रहे हैं? आप हिमाचल की जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं? इस बार फिर आपने 1000 मेगावाट का लक्ष्य रख दिया। 5000 मेगावाट का हिमाचल की जनता को जवाब चाहिए क्योंकि आपने अपने बजट में कहा है।

उपाध्यक्ष जी, वर्ष 2013 में 'अटल स्वास्थ्य सेवा योजना' आई थी। आज बड़ी चर्चा होती है कि उसके तहत पांच लाख मरीजों को ढोया। मैं धन्यवाद करता हूं श्री धूमल जी का जिन्होंने यह अटल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की और अटल जी के जन्मदिन के ऊपर इसको शुरू किया था। यह योजना बहुत अच्छी चल रही है। माननीय मंत्री जी को हम इसके लिए बधाई देते हैं कि आपने इसको और आगे बढ़ाया, अच्छा चलाया परन्तु कहीं-न-कहीं अटल जी का और पिछली सरकार का धन्यवाद कर देना चाहिए। इन्होंने कहा कि हम 90 परसेंट कैटेगरी स्टेट है। क्या हुआ अगर 'अटल स्वास्थ्य सेवा 108 एम्बूलैंस राष्ट्रीय सेवा' उसका नाम रख दिया। आपको ग्रांट 20 परसेंट मिल रही है और 80 प्रतिशत प्रदेश सरकार लगा रही है। तो कहां गया 90 परसेंट कैटेगरी स्टेट? हमारे समय में कहा कि 60 परसेंट देंगे लेकिन 20 परसेंट मिल रहा है। यू0पी0ए0 की सरकार ने 20 परसेंट पर लाकर खड़ा कर दिया है और आप 90 परसेंट की बात कर रहे हैं। इस सदन को जवाब चाहिए।

इसी तरह से स्वास्थ्य बीमा योजना है। कहां गया स्पैशल कैटेगरी स्टेट? 75:25 का क्यों मिल रहा है? यू0पी0ए0 की सरकार ने इसे शुरू किया। 90 और 10 का हिस्सा कहां गया? हम मांगते रहे लेकिन नहीं मिला। आज भी 75 और 25 पर

स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है। उपाध्यक्ष जी, 2014 में कहा कि सचल चिकित्सालय चलाएंगे, सचल अल्ट्रासाउंड चलाएंगे और सचल जीवन रक्षक दवाइयां चलाएंगे। आई0जी0एम0सी0 में, टांडा में और बाकी जगह MBBS की सीटें 300 करेंगे। एम0डी0 की सीटें 300 करेंगे, पी0जी0 की सीटें बढ़ाएंगे और सुपर स्पैशलाइजेशन करेंगे। लेकिन वही ढाक के तीन पात। इस बार बजट में से सीटें बढ़ाने का जिक्र गोल हो गया। अरे, उन सीटों को तो बढ़ा दो जिनका जिक्र पिछली बार किया था।

उपाध्यक्ष जी, महत्वपूर्ण विषय शिक्षा, कृषि और बागवानी है। कृषि के साथ क्या धोखा किया? आपने 2013 में कहा कि हम बंदरों से किसानों को बचाएंगे। धूमल जी की सरकार के समय नसबन्दी केन्द्र शुरू हुए थे। लगभग 60 हजार बंदरों की नसबन्दी हो गई थी। नसबन्दी केन्द्र 75 बनाने का निर्णय किया। वर्ष 2013 में कहा कि हम छः बनाएंगे परन्तु 2015 आते तक सारे नसबन्दी के टारगेट खत्म हो गए। नये सेंटर बनाने के टारगेट खत्म हो गए। अब बन्दर अच्छे लगने लग गए और किसान की चिन्ता खत्म हो गई।

वर्ष 2013 में कहा कि हम जैविक खेती को बढ़ावा देंगे। लेकिन उपाध्यक्ष जी, एक भी सेल सेंटर हिमाचल की सरकार ने जैविक खेती का किसानों को अभी तक उपलब्ध नहीं करवाया है। कोई बेचारा भूला-बिसरा यदि जैविक खेती लगा भी लेगा तो उस व्यक्ति को अपना उत्पाद बेचने को जगह नहीं है यानी मार्किट उपलब्ध नहीं करवाई गई। जो वर्ष 2013-14-15 में घोषणा कर रहे हैं उसका क्या विश्वास है? आपने वर्ष 2013 में क्रम संख्या 34 पर आवारा पशुओं का बड़ा जिक्र किया और कहा कि हम खेतों के चारों तरफ पता नहीं क्या-क्या लगाएंगे, वह मैं पढ़ रहा था। लेकिन वह समझ में नहीं आया। वर्ष 2014 में भी गोल हो गया और 2015 में भी गोल हो गया और अभी तक आवारा पशुओं से खेतों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता चला गया। पशु आवारा बढ़ते चले गए, किसान की फसलें

बर्बाद होती चली गई और बंदरों का आतंक बढ़ता चला गया। आपने वर्ष 2013 में क्रम संख्या 36 पर कहा, फलों पर आधारित उद्योग लगाएंगे, पैकेजिंग युनिट लगाएंगे फलों के संयंत्र लगाएंगे, जूस निकालने के संयंत्र लगाएंगे, कन्सन्ट्रेट बनाने के संयंत्र लगाएंगे,

जारी श्री जे0के0 द्वारा--------

23.3.2015/1645/जेके/एजी/1
डॉ0 राजीव बिन्दलः-----जारी--------

कंसंट्रेट बनाने के संयंत्र लगाएंगे, हम वाईन बनाएंगे, हम एप्पल साईडर बनाएंगे, पता नहीं क्या-क्या बनाएंगे? 2013 से 2015 आ गया वह किसान बेचरा वैसा का वैसा ही है। बागवानी की बड़ी चर्चा की गई। बागवानी की चर्चा इसलिए करते हैं कि कहीं बागवान इनसे रूठ न जाएं। मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत हर बार कुछ न कुछ बढ़ाते थे। इस बार न सेब में कुछ मिला, न नीम्बू में कुछ मिला, न संतरे में मिला, न गलगल में मिला और न ही किसी अन्य फल में कुछ दिया गया। किसानों के लिए कितना हाहाकार किया। वर्ष 2013 में कहा कि हम प्रदेश का लैंटाना उखाड़ देंगे। लैंटाना से प्रदेश को मुक्त कर देंगे। आपने वर्ष 2014 में भी बोला और वर्ष 2015 में भी बोल दिया लेकिन लैंटाना बढ़ता जा रहा है और कृषि भूमि घटती जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष जी, हम पूछना चाहते हैं कि लैंटाना उखाड़ने का खर्चा किसकी ज़ेब में गया? मैं आरोप लगा रहा हूं कि लैंटाना उखाड़ने का पैसा कहां गया, उसकी जांच होनी चाहिए। वह पैसा कहां गया और किसानों के साथ किसने अन्याय किया? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल पुराने बजट का हवाला दे रहा हूं। यहां पर अधिकारी नोट कर रहे हैं। वर्ष 2014 में 38 नम्बर पर कहा कि हम कॉफी का उत्पादन करेंगे। मैं यहां पर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की बात कर रहा हूं। कॉफी बढ़ायेंगे और प्रदेश में बहुत सारी कॉफी लगाएंगे। केरल के मुकाबले में हिमाचल को पहुंचा देंगे। कॉफी का एक भी पेड़ हिमाचल प्रदेश के अन्दर नहीं लगा। आपको इस बार के बजट में कहना चाहिए था कि हमने इतना करोड़ रूपया खर्च किया। कॉफी के पौधे नहीं लगे हम फेल हो गये और अब हम चाय लगाएंगे। यहां पर कुछ तो बताते। आपने किसानों के लिए वर्ष 2014 में क्या कहा कि हम कोल्ड चेन बनाएंगे। सारे हिमाचल में कोल्ड चेन बनाएंगे। जो सब्जी पैदा करेगा उसकी कोल्ड चेन कोल्ड स्टोरेज के अन्दर नैट वर्क बनाएंगे। वह कोल्ड चेन पता नहीं कहां गई? अभी तक न

चेन नज़र आ रही है और न ही कोल्ड नज़र आ रहा है, हाँ जुकाम का कोल्ड ज़रूर है। आप लोगों ने किसानों के साथ धोखा किया है। आप लोगों ने कृषि के नाम पर इस

23.3.2015/1645/जेके/एजी/2

बार के बजट में क्या किया कि जो धूमल सरकार के समय की योजनाएं थी उनका नाम बदल दिया, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, किसान, बागवान समृद्धि योजना। 90 प्रतिशत पॉली हाऊस पर सबसिडी मिलती थी। हजारो पॉली हाऊसिज लग रहे थे। आपने उसका नाम बदल करके किसी और नेता के नाम रख दिया। सबसिडी 90 प्रतिशत से घटा करके 85 प्रतिशत कर दी। इस तरह से सबसिडी घट गई। अब न पॉली हाऊस लगे और न कुछ और लगे। आपने यहां पर कहा सूक्ष्म सिंचाई योजना, यह भी पंडित दीन दयाल उपाध्याय योजना और किसान, बागवान समृद्धि योजना का पार्ट था। उसका भी आपने नाम बदल करके कोई दूसरा नाम रख दिया। आपने एक भी नई योजना किसान के लिए नहीं चलाई। मिट्टी टैस्ट योजना के बारे में आप कह रहे हैं कि एक लाख किसानों को मृद्धा टैस्ट योजना का कार्ड देंगे। ढाई लाख किसानों को तो धूमल जी ने पहले दे दिया था। मिट्टी टैस्ट का काम मोदी जी ने पूरे देश में चलाया उसका पैसा आप इस्तेमाल करेंगे। अब पता नहीं जैसे पहले की योजनाएं ठण्डे बस्ते में हैं, इसका पैसा कहां जाएंगा उसका पता नहीं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक गम्भीर मामला मैं यहां पर लाना चाहता हूं। आपने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलना चाहिए। आपने कहा कि सोसायटी बना करके लोग उसको चलाएं। एक गांव कुंडला है। मैं चाहूंगा कि अधिकारी इसको नोट करें। उस गांव के अन्दर एक ट्यूबवैल है। उस ट्यूबवैल से पानी लोग अपने खर्चे के ऊपर बिजली लेते हैं और उनको कमर्शियल रेट की बिजली लगाई जाती है, उनको एग्रीकल्चर रेट नहीं लगाया जाता । मैंने इसके बारे में अनेक बार प्लानिंग की बैठक में कह दिया है। या आप लोग यहां पर कह दें कि हम कृषि के क्षेत्र लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते उनका बिजली का मीटर भी उखाड़ कर ले गये और कहने लगे कि फसलें सूखती है तो सूखने दें। उनको कमर्शियल रेट लग रहा है। माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके बारे में कोई पॉलिसी यहां पर लाई जाए। यदि कोई प्राईवेट ट्यूबवैल कॉम्युनिटी के लिये लगा है, प्राइवेट यानि सोसायटी बना करके ट्यूबवैल को रन कर रहा है और वह सबके काम आ रहा है तो उसके अन्दर

23.3.2015/1645/जेके/एजी/3

सबसिडी का प्रावधान किया जाए । मैंने केवल अभी तक कृषि की बात की है। यानि यह कृषि के नाम पर 90 प्रतिशत किसानों और बागवानों के साथ धोखा करने का बजट।

श्री एस.एस. द्वारा जारी--------

23.03.2015/1650/SS-JT/1
डॉ0 राजीव बिंदल क्रमागतः

पंचायती राज प्रतिनिधियों को क्या मिलना था, इनको लगा कि अब नया चुनाव आयेगा, नये प्रधान आयेंगे, उनके लिए सोचेंगे। पुराने के लिए क्या सोचना है। परन्तु पुरानों को रगड़ा देने का काम ज़ोरों पर है। माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रश्न संख्याः 1678 भाई जयराम जी का लगा। 50 प्रधानों को सस्पैंड कर दिया और सिरमौर में ठगड़े का रगड़ा तगड़ा है क्योंकि वहां 11 को सस्पैंड कर दिया। बाकी सब लाइन में लगाकर रखे हैं। 11 प्रधान सस्पैंड और टर्मिनेट कर दिए। मंत्री जी थोड़ी-सी मेहर करो। अनिल जी, आप तो अच्छे आदमी हैं। जो हारे हुए नेता हैं उनके कहने पर हमारे प्रधानों को सस्पैंड करके रगड़ा देने में लगे हैं और हारे हुए नेताओं को सिरमौर में नेता बनाकर चमकाया जा रहा है। लगे हुए हैं और वे गेड़ा दे रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगला महत्वपूर्ण विषय शिक्षा है। शिक्षा के विषय के अंदर क्या हालत है?

Deputy Speaker: Please wind up.

डॉ0 राजीव बिंदलः आपका प्रश्न ज़बरदस्त है। उत्तर भी आज ही आया है। प्रश्न संख्याः 1670 - ऐसी कितनी पाठशालाएं हैं जिनमें 5 बच्चे हैं। तो बोले कि 411 पाठशालाएं हैं जिनमें 5 बच्चे हैं। ऐसी कितनी पाठशालाएं हैं जिनमें 6 और 9 बच्चे हैं। 725 पाठशालाएं ऐसी हैं जिनमें 6 और 9 बच्चें हैं। जिनमें एक अध्यापक है ऐसी 943 पाठशालाएं हैं। आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं। हिमाचल का बच्चा कहां पर जा कर किस प्रकार से आगे बढ़ेगा? सिरमौर का प्रश्न इसी में लगा हुआ है। मेरा प्रश्न है। प्रश्न संख्याः 1700 और उसके उत्तर में हायर एजुकेशन में आपने बोला कि

6979 में से 1926 पद रिक्त हैं। 30 परसैंट स्टाफ खाली है। न डॉक्टर हैं और न मास्टर हैं। पीअन भी नहीं है। आप बोलते हैं कि स्कूल खोल रहे हैं। जितनी बार जाते हैं उतनी बार धड़ाधड़ स्कूल खोलने की घोषणा होती है ताकि वोट ले लें। वोट ले लो परन्तु बच्चों की चिन्ता ज़रूर करो। मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा भी केवल वोट की राजनीति से शिक्षा नहीं चलेगी।

रोजगार के लिए पर्यटन सबसे बड़ा साधन है और पर्यटन के विकास के लिए आपने क्या किया? आपने 2014 में कहा कि हम हवाई पट्टियों का विस्तार करेंगे। प्वाइंट नं0-99 पर आपने कहा कि हवाई पट्टियों का विस्तार करेंगे। कुल्लू की हवाई

23.03.2015/1650/SS-JT/2

पट्टी में बड़े हवाई जहाज़ उतरेंगे। गग्गल में उतरेंगे। कण्डाघाट में बहुत बड़ा हवाई अड्डा बनायेंगे। बेचारे सोलन वाले बड़े खुश हो गए। माननीय मंत्री जी भी बड़े खुश होंगे, मेरे साथी हैं। परन्तु वह कण्डाघाट अभी तक जीरो है। कोई हवाई पट्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपने 2014 में कहा प्वाइंट नं0-102 पर कि टूरिज्म के विस्तार के लिए सारी सड़कों के किनारे बढ़िया-बढ़िया शौचालय बनायेंगे। जनता की सुविधा के स्थान बनायेंगे। अभी शिमला से लेकर कांगड़ा तक चले जाओ, कालका से लेकर किन्नौर तक और कहीं गलती से माननीय मंत्री जी सिरमौर में चले जाएं, माननीय मंत्री जी आप सिरमौर के मंत्री भी हैं, तो एक भी शौचालय ढूंढकर टूरिज्म के लिए मिल जायेगा तो बड़ी कठिनाई होगी। आप क्या बोलते हो और क्या करते हैं, यह सब सामने है। टूरिज्म में रोजगार सृजन कोई व्याख्या 2015 के अंदर नहीं आई कि पिछले तीन साल के अंदर आपने टूरिज्म के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार दिया। अगले साल कितने लोगों को टूरिज्म के माध्यम से रोजगार देंगे। केवल मंदिरों को 20 हजार देंगे। इससे क्या टूरिज्म बढ़ेगा? क्या टूरिज्म विस्तार की हमारी यही नीति है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन मिनट लूंगा। यानी उस मंदिर को 20 हजार मिल गया तो क्या टूरिज्म विकास हो जायेगा?

सड़कें हमारी भाग्य रेखाएं हैं हर बार बोल देते हैं लेकिन हालत क्या है? सोलन-मीनस रोड, पूरे सिरमौर को क्रॉस करके जाती है। सिरमौर की छाती पर से जाने वाली सड़क चलने के काबिल नहीं है। सैंज से गिरीपुल की रोड, उस सड़क की

बहुत चर्चा होती है। सेब वहां से निकालेंगे। रोहडू के लोग भी खुश हो जाते हैं परन्तु सेब के ट्रक जब वहां से जाते हैं तो उनके एक्सल 12 किलोमीटर पर टूट जाते हैं। उस रास्ते में बहुत मकैनिक होंगे, मजे हो गए। नाहन-कोलावाला बोर्ड, हाटकोटी-ठियोग की बड़ी चर्चा है। सकेती-खजुरना, पांवटा-शिलाई, हालत सड़कों की माड़ी है।

जारी श्रीमती के0एस0

23.03.2015/1655/केएस/जेटी/1

डॉ0 राजीव बिन्दल जारी----

सकेती-खजुरना, पांवटा-शिलाई, सड़कों की हालत माड़ी है। 2013 में आपने 80 नम्बर पर बोला कि हम वहां टनल्ज़ बनाएंगें। चामुण्डा-होली, कार-सेहर, भुभुजोत, तीसा-किलाड़,जलोड़ी-जोत। 2015 तक शून्य, एक भी पैसा नहीं, कहां गई वह टनल्ज़। अब नई कहानी, आज मैं पढ़ रहा था कि अब नया रोपवे बनाएंगें। पुराना तो क्योंकि रणधीर जी के क्षेत्र में नैनादेवी में बनना था, अब उसको कैंसल कर दिया । अब नया बनाएंगें। जब तक नया बनाने की सोचेंगें तब तक यह सरकार चली जाएगी। उपाध्यक्षः माननीय सदस्य अब समाप्त करें। आपने बहुत समय ले लिया। 25 मिनट से ज्यादा समय हो गया।

डॉ0 राजीव बिन्दलः उपाध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं समाप्त कर रहा हूं। जनजातीय क्षेत्र की चर्चा करना चाहूंगा। ट्राईबल ऐरिया में रहने वाले ट्राईबल्ज़ को तो ग्रांट मिलती है लेकिन जो ट्राईबल एरिया से बाहर रहने वाले हैं, क्षमा करना उपाध्यक्ष जी, जितने लोग ट्राईबल एरिया में रहते हैं उससे तीन गुना लोग नॉन-ट्राईबल में ट्राईबल रहते हैं और उनके लिए धन का प्रावधान नहीं है। मैं समझता हूं कि इसको नोट करना चाहिए। नौणी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को पैंशन नहीं मिल रही है । दो करोड़ रुपये के विदेशी फंड का घपला हो गया, उसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। सेवानिवृत्त लोगों को आपने रोज़गार दे दिया आपने 6 करोड़ बर्बाद कर दिया। सेवानिवृत्त लोगों को रोज़गार दे-दे करके दो करोड़ में हजारों नए लोगों को रोज़गार मिल जाता।

23.03.2015/1655/केएस/जेटी/2

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि नाबार्ड का पैसा प्रदेश में इक्वल डिस्ट्रिब्यूट होना चाहिए। कुछ विधान सभा क्षेत्रों में

200 करोड़ लग गया और हमारा नाहन विधान सभा क्षेत्र 20 करोड़ से भी नीचे है। हम चाहेंगें कि उन विधान सभा क्षेत्रों में ज्यादा पैसा अलॉट हो । नाहन विधान सभा क्षेत्र में 13 स्कूलों की दरकार है। लगातार हम मांग कर रहे हैं, अभी तक एक भी पुल की सेंक्शन हमको नहीं मिली है। परसों भी हमने धरना-प्रदर्शन किया।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, अब समाप्त करें आपको बोलते हुए पूरा आधा घंटा हो गया है। आप खत्म नहीं कर रहे हैं मैं अब अगले वक्ता को बुला रहा हूं।

डॉ0 राजीव बिन्दलः माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बजट केवल और केवल प्रदेश की जनता को धोखा देने वाला बजट है। 2013, 2014 और 2015, जो वर्ष 2013 में कहा, वही 2014 में कहा, 2015 में कहा । यह केवल और केवल मायाजाल है। केवल और केवल जनता को धोखा देने का प्रयास है परन्तु जनता धोखे में नहीं आने वाली है। उसने 2014 में बता दिया कि आपका क्या हश्र होगा। 68 में से 58-59 विधान सभा क्षेत्र में कांग्रेस साफ हो गई, आने वाला समय भी ऐसा ही होगा इसलिए अगर कुछ सुधार कर सकते हो तो कर लो । जनता की चिंता कर लो। धन्यवाद।

23.03.2015/1655/केएस/जेटी/3

उपाध्यक्षः अब श्री संजय रतन जी चर्चा में भाग लेंगें।

श्री संजय रतनः उपाध्यक्ष महोदय, 18 मार्च, 2015 को हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो इस माननीय सदन में 2015-16 के बजट अनुमान प्रस्तुत किए हैं, मैं उनके बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस विधान सभा में 18वां बजट प्रस्तुत किया और शायद सबसे लम्बा बजट अनुमान प्रस्तुत किया। ये हिन्दुस्तान के चंद लोगों में से हैं जिन्हें सबसे अधिक बजट प्रस्तुत करने का मौका किसी विधानसभा में मिला है। जैसे माननीय सदस्या श्रीमती आशा कुमारी जी ने कहा कि इन बजट अनुमानों से उनकी जो परिपक्वता है,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

23.3.2015/1700/ag/av/1
संजय रतन जारी--------

उनकी वह परिपक्वता है कि किस तरीके से पहले और भविष्य में; अपने सीमित साधनों में वे हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी एक झलक इसमें दिखाई देती है। बजट अनुमान और महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण वर्तमान सरकार का आईना होता है। इसके द्वारा पूरे प्रदेश में यह बताया जाता है कि सरकार ने पिछले साल क्या किया है और भविष्य में क्या करने जा रही है। माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने वर्ष 2012 से हिमाचल प्रदेश की बागडोर सम्भाली है। उस समय हिमाचल प्रदेश का जो विकास रुका हुआ था उसको आगे बढ़ाने की उन्होंने पूरी कोशिश की है; इसके लिए हम उनको बधाई देना चाहते हैं।(---व्यवधान---) नरेन्द्र ठाकुर जी, इसलिए बधाई देना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण की शुरुआत सर्वकल्याण समग्र विकास के साथ की थी। हिमाचल प्रदेश का विकास एक समान और बिना किसी भेदभाव के हो। उसमें न ऊपर का हिमाचल, न नीचे का हिमाचल और न मध्य का हिमाचल। पूरे हिमाचल प्रदेश का विकास एक समान करने की वचनवद्धता उन्होनें इस बजट अनुमान के साथ हिमाचल की जनता को बताने की कोशिश की है; उसके लिए भी हम मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। अभी माननीय विपक्ष के नेता यहां बोले। दूसरे माननीय सदस्यों की प्रक्रिया भी यहां आई हैं। जब माननीय सदस्या श्रीमती आशा कुमारी जी बोल रही थी तो आप की तरफ से बार-बार यह कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को बहुत कुछ दिया है। कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जो केंद्र सरकार से स्पोनसर हैं, उसमें कट लगा हो। आप लोग कह रहे थे कि 14वें वित्तायोग में जो हिमाचल प्रदेश को मिला है उसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार और मुख्य मंत्री धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। हमें वह वक्त भी याद है जब केंद्र में यु.पी.ए. की सरकार थी। उस समय परवाणू से नीचे इनकी भाषा कुछ और हुआ करती थी और जब हिमाचल में प्रवेश किया करते थे तो इनकी भाषा कुछ और हुआ करती थी। हमें धन्यवाद करने में कोई गुरेज नहीं है। हम धन्यवाद खुले

23.3.2015/1700/ag/av/2

दिल से कर सकते हैं और सरेआम कर सकते हैं। आज हिन्दुस्तान का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के पास है जो पार्टी में आपके हिमाचल प्रदेश के इनचार्ज रहे हैं। आपके बहुत से लोगों के उनके साथ व्यक्तिगत सम्बंध भी हैं जैसे आप यहां क्लेम करते हैं। अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश के इतने ही हितेषी है तो आप सब लोग इकट्ठे होकर जाओ और हिमाचल के लिए उनसे एक आर्थिक पेकेज मांगो। आर्थिक पेकेज लेकर हिमाचल के लिए आओ, हम खुले दिल से उनका धन्यवाद करेंगे। (---व्यवधान---) हमने नहीं किया परंतु आप करके दिखाओ। आपके पास समय है। जब केंद्र में यु.पी.ए. की सरकार थी तथा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो आपकी भाषा कुछ और हुआ करती थी। आज केंद्र में आप लोगों की सरकार है। आप लोग दिल्ली जाओ, हिमाचल के लिए आर्थिक पेकेज लेकर आओ हम खुले दिल से आपका धन्यवाद करेंगे। आपको बोलने की

आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप धन्यवाद करो। हम खुद करेंगे मगर एक आर्थिक पेकेज लाओ और हिमाचल प्रदेश को आर्थिक संकट से उबारने की कोशिश करो। आज कलम आपके हाथ में है। उस कलम का सदुपयोग हिमाचल प्रदेश के लिए होना चाहिए, हम तब मानेंगे---

श्री बी.जे.द्वारा जारी

23.3.2015/1705/negi/ag/1
संजय रतन जारी--------

बजाय इसके कि यहां जब पक्ष के लोग बोलते हैं तो महज़ आप लोग विरोध करना जानते हैं। आप लोग यहां पर गलत आंकड़े पेश करके, प्रैस गैलरी में देख कर ताकि कल प्रैस में छप जाए, गलत प्रचार करके आप वाहवाही लूटना चाहते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता भली-भांति जानती है । अभी माननीय सदस्य डॉ0 राजीव बिन्दल जी बजट के ऊपर भाषण दे रहे थे, वह वर्ष 2015-16 के बजट के ऊपर बात नहीं कर रहे थे, वह तो वर्ष 2013-14 और 2014-15 की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि वर्ष 2015-16 के ऊपर वह कल बोलेंगे। मेरा आप लोगों से यह निवेदन है कि आप लोगों के पास जैसा आप यहां बार-बार क्लेम कर रहे हैं, एक अच्छा नेतृत्व है, आपकी पार्टी की केन्द्र में सरकार है अगर हमारे से कुछ नहीं हो पाया तो आप करके दिखाओं । हिमाचल की जनता और हम सब आपका स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 2015-16 के बजट में हर क्षेत्र में कोई न कोई राहत प्रदान करने की कोशिश की है । सामाजिक क्षेत्र में पैंशन 550/- रूपये से बढ़ा कर 600/- रूपये की गई है। 80 साल से ऊपर के बुजुर्गो और 70 परसेन्ट से ज्यादा जो अपंग हैं उनकी पैंशन 1000 रूपये से बढ़ा कर 1100 रूपये कर दिया गया है। इसके लिए हम मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन एक निवेदन मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से भी करना चाहता हूं, कमी की बात नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं और जो चीज़ हम कर सकते हैं उसके लिए हम माननीय मुख्य मंत्री महोदय से हम अपील भी करेंगे, चाहे इस बजट में करें या अगले साल के बजट में करें। लेकिन अगले चुनावों से पहले-पहले हम आपको सब करके दिखाएंगे। जैसे मैंने कहा कि हमारा जो मैनीफैस्टो है वह 5 साल का मैनीफैस्टो है। वह किसी एक साल का मैनीफैस्टो नहीं है । जिसको हमारे विपक्ष के नेता जी ने यहां पढ़ा वह 5 साल का मैनीफैस्टो है। बुजुर्गो के लिए पैंशन की आयु सीमा जो 80 साल रखा है, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि लेडिज़ के लिए इसको

23.3.2015/1705/negi/ag/2

कम किया जाए। महिलाओं के लिए 2-3 साल कम किया जाए क्योंकि महिलाओं की औसत आयु कम होती है। बहुत सी बुजुर्ग माताएं हमें मिलती हैं और पैंशन की मांग करती हैं लेकिन आयु की वजह से उनको पैंशन नहीं मिल पाती ।

दूसरा, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जैसे आप सब विधायकों की भी मांग थी, विधायक निधि 50 लाख से 70 लाख की है और उसमें जो राइडर लगा है कि 20 लाख रूपये केवल मात्र लघु सिंचाई योजनाओं के लिए खर्च करेंगे, तालाबों के लिए खर्च करेंगे, उस राइडर को हटा दिया जाए। जिस तरीके से हम 50 लाख रूपये डिस्ट्रिब्युट करते हैं उसी तरीके से 20 लाख को भी हम डिस्ट्रिब्युट करें। कई ऐसे चुनाव क्षेत्र हैं जहां कूहलों का प्रावधान नही है, पानी नही है। अगर हम लघु सिंचाई योजना को बनाएं तो 20 लाख में कोई लघु सिंचाई योजना नही बनेगी। किसी दरिया से पानी उठाने में और किसी खड्ड से खेतों तक पानी पहुंचाने में करोड़ों रूपये लगते हैं। इस तरह से यह पैसा अनस्पेंट रह जाएगा क्योंकि हम इस 20 लाख रूपये को खर्च नहीं पाएंगे। या फिर जो मनरेगा के तहत तालाब बनें हैं उसी पर हम बार-बार पैसा देते रहेंगे और उन्हीं तालाबों की रेनोवेशन होती रहेगी और इस पैसे का मिसयुज होगा। इसलिए इस राइडर को हटा दिया जाए। यह मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं ।

इसके साथ-साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल एक नई प्रथा शुरू करके, ऐच्छिक निधि विधायकों के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 2 लाख रूपये जारी की थी और उसका भरपूर फायदा चुनाव क्षेत्रों में विधायकों द्वारा उठाया गया। मेरा यह निवेदन है माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कि .....

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

23.03.2015/1710/यूके /एजी/1

श्री संजय रतन---जारी ----

तो मेरा माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन है कि दो लाख रुपए आज के समय में बहुत कम है, इसको कम से कम 4 लाख रूपए किया जाए । यह राशि डबल कर दी जाए ।

इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने गौ वंश संवर्द्धन बोर्ड बनाने की बात की है और इसके लिए 10 करोड़ रूपये का प्रावधान भी किया है, यह बहुत ही काबिले तारीफ है क्योंकि आज के समय में प्रदेश में इसकी बहुत आवश्यकता है । शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हिमाचल प्रदेश में आयी है । पिछले साल कई स्कूल्ज़ अपग्रेड किए गए । 14 नए कॉलेजिज़ खोले गए और वह कॉलेजिज़ ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में खोले गए । उसका भरपूर फायदा हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मिला है । मेरे चुनाव क्षेत्र में खुंडिया में भी डिग्री कॉलेज खोला गया और जो बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे उनके लिए बहुत ही फायदे की बात हुई है । वे आज घर-द्वार पर घर का खाना खाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और खास कर के लड़कियां, जिनको मां-बाप प्लस टू के बाद कॉलेज भेजने से इसलिए गुरज करते थे, दूरी के कारण, जंगल होने के कारण, खड्ड और नाले होने के कारण, उनको कॉलेज नहीं भजते थे, वे आज उस कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं ।

इस साल के बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो शिक्षा ऋण 7.50 लाख रूपए तक लेते हैं, उसके ऊपर जो पंजीकरण शुल्क लगता था उसको माफ करने की बात की है, यह बहुत ही सराहनीय कदम है । इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बहुत मुश्किल आती थी, उन्हें अब

23.03.2015/1710/यूके /एजी/2

फायदा मिलेगा । "रूसा" के तहत हमारी एच0पी0 यूनिवर्सिटी को पूर्णतया जो वाई-फाई करने की बात कही गयी है, वह भी बहुत ही सराहनीय कदम है क्योंकि आज कम्प्यूटराईजेशन का जमाना है, हर काम कम्प्यूटर पर होता है, इंटरनेट से होता है । तो बच्चों को, छात्रों को जो असुविधा होती थी, उसको दूर करने का प्रयास किया गया है । सबसे बड़ी बात जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने ।TIs का विस्तार करने की की है, तकनीकी शिक्षा का विस्तार करने की कही है, और 100 नये स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा को लागू करने की बात की है, यह भी बहुत ही सराहनीय है, इससे हमारे बच्चे टैक्नीकल तौर पर निपुण होंगे और रोजगार प्राप्त करने में वे खुद सक्षम होंगे ।

कौशल विकास भत्ते के लिए जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने निगम बनाने की बात की है, उससे पूरे हिमाचल प्रदेश और हमारे नौजवानों को बहुत फायदा होगा । कौशल विकास करने के बाद वे निपुण होंगे और अपना रोजगार प्राप्त करने

में वे हिमाचल प्रदेश के और देश के किसी भी कोने में जा कर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। यह भी एक बहुत अच्छा कदम है।

हिमाचल प्रदेश के आर्ट और कल्चर को बचाने के लिए और उसको पुनः स्थापित करने के लिए जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आर्ट एवं कल्चर कॉलेज की बात की है, बहुत ही सराहनीय बात है। पिछले दिनों

23.03.2015/1710/यूके /एजी/3

माननीय मुख्य मंत्री महादेय, हरिपुर-गुलेर में गए हुए थे, वहां पर भी लोगों ने मांग की और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने वहां पर भी यह घोषणा की थी और उस जो घोषणा की थी उसको अमली जामा इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पहनाया है।

सिविल सर्विसिज़ में आज कमी आ रही है। प्रारम्भिक परीक्षा अगर कोई हिमाचल के नौजवान पास करते हैं तो उनको 30 हजार रुपए देने की बात जो की है, इससे और ज्यादा प्रोत्साहन सिविल सर्विसिज़ मे जाने के लिए लोगों को मिलेगा और हिमाचल प्रदेश में ऑफिसर्स की कमी को पूरा करने का एक प्रयास माननीय मुख्य मंत्री द्वारा किया गया है। इसके लिए भी हम उनको बधाई देना चाहते हैं। कम्पैशनेट जॉब जो एक अहम मुद्दा है, आज हिमाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे कर्मचारी भाई हैं।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

23.03.2015/1715/sls-AG-1
श्री संजय रतन ...जारी

हिमाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे कर्मचारी भाई थे जिनकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई। उनके परिवार में रोज़गार प्राप्त करने में बहुत-सी दिक्कतें आती थीं। खासकर इनकम क्राइटेरिया में ही मैक्सिमम केसिज खत्म हो जाते थे। उस लिमिट को माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये करने की बात की है। यह बहुत अच्छा कदम है। लेकिन इसमें मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवदेन करना चाहता हूं। वर्ष 2006 में पे स्केल्ज रिवाईज हुए थे। सबकी पैंशन्ज और फैमिली पैंशन्ज रिवाईज हुईं हैं। अगर इस बढ़ी हुई इनकम को उसी के आधार पर कट ऑफ डेट लगाकर पीछे से 2006 से लागू किया जाए तो बहुत से परिवारों को, जिनको आज

रोज़गार की जरूरत है, उनको रोज़गार मिल सकता है, अदरवाईज डेट ऑफ एप्लीकेशन अगर लेंगे तो उसमें मैक्सिकम केसिज रिजैक्ट हो जाते हैं। जबसे हिमाचल प्रदेश में इम्पलाईज के पे स्केल्ज रिवाईज हुए, अगर इस इनकम को हम उसके साथ जोड़ दें तो हिमाचल प्रदेश के काफी परिवारों को इसका फायदा होगा।

बजट में और भी कई ऐसी बातें हैं जिनका हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बार प्रावधान किया है। यह बहुत ही सराहनीय हैं। मैं सिर्फ़ अपने विपक्ष के भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका क्रिटिसिज्म केवल क्रिटिसिज्म की हैशियत से नहीं होना चाहिए। क्रिटिसिज्म फैक्ट्स के आधार पर होना चाहिए और बेहतरी के लिए होना चाहिए। यहां मैं इस माननीय सदन में पहली बार विधायक बनकर आया हूं। मगर जब से हम इस माननीय सदन में आए हैं, हमें ऐसा लगा कि विपक्ष की भूमिका सिर्फ़ हर चीज को क्रिटिसाईज करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अच्छी बात है, उसकी तारीफ़ होनी चाहिए और जहां आपको लगता है कि गलत है, उसको अगर आप इस सदन के माध्यम से सरकार के ध्यान में लाएंगे तो सरकार उसमें सुधार भी कर सकती है।...(व्यवधान)...आप लाते नहीं है, सिर्फ़ क्रिटिसिज्म करते हैं। आप तो यहां तक कह देते हैं कि यह दीवार व्हाईट नहीं है, हरी है। आप सब यही बोलेंगे कि हरी है। यह नहीं कहेंगे कि व्हाईट है। कई बार

23.03.2015/1715/sls-AG-2

आपको व्हाईट को व्हाईट, हरे को हरा, लाल को लाल और काले को काला बोलने की क्षमता भी रखनी चाहिए। यह मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं।

हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन सालों में बहुत विकास हुआ है। हम नहीं कहते कि आपने विकास नहीं किया है। आपकी सरकार रही, आपने भी विकास किया होगा। मगर हमने, जब से माननीय मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार संभाली है, तब से विकास को और आगे ले जाने की कोशिश की है और हिमाचल प्रदेश में और ज्यादा विकास हो रहा है। आज किस क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में; सब क्षेत्रों में विकास हो रहा है और आने वाले दो-तीन सालों में भी आपको लगेगा कि हिमाचल प्रदेश में विकास हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, मैंने पहले भी इस सदन में कहा था और आज भी कह रहा हूं , ऐसा मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश में हमें नहीं मिल सकता जो दिन-रात मेहनत करते हो। पिछले

दिनों मुझे माननीय मुख्य मंत्री महोदय के साथ कांगड़ा के दौरे में जाने का मौका मिला। रात के दो-दो बजे तक लोगों से मिल रहे थे और काम कर रहे थे। ऐसा मुख्य मंत्री, मैं नहीं समझता कि हिमाचल प्रदेश को पहले कभी मिला हो। ऐसी कोशिश आज हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी की है। जैसे हम डॉ० वाई. एस. परमार का नाम लेते हैं कि हिमाचल को उन्होंने बनाया है, आज हिमाचल को संवारने में माननीय मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी की अहम भूमिका है जो हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों से यह निवदेन करना चाहता हूं ..

जारी ..गर्ग जी

23/03/2015/1720/RG/AG/1
श्री संजय रतन-------क्रमागत

मैं आप लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा आप हमें कह रहे हैं, तो मैंने कहा कि हम धन्यवाद करेंगे, आप कुछ-न-कुछ आर्थिक पैकेज केन्द्र सरकार से लेकर आएं। इस तरह जो आज हिमाचल प्रदेश में विकास हो रहा है इसको आगे बढ़ाने में आप लोग भी सहयोग करें, अच्छे वातावरण में रहकर साथ चलें, कंधे-से-कंधा मिलाएं और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा, दिन दुगुणी, रात चौगुणी तरक्की करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद, जय हिन्द।

समाप्त

-/2

23/03/2015/1720/RG/AG/2

उपाध्यक्ष : अब श्री गोविन्द राम शर्मा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री गोविन्द राम शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट दिनांक 18 मार्च, 2015 को इस माननीय सदन में पेश किया है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझसे पूर्व भी काफी वक्ताओं ने अपनी-अपनी बात रखी, लेकिन मैं समझता हूं कि इस बजट में जो विषय आने चाहिए थे, वे नहीं आए। जिन वर्गों की चिन्ता करनी चाहिए थी, उनकी चिन्ता नहीं की गई।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं मजदूरों की बात करूंगा कि जो इस प्रदेश में सबसे निम्न स्तर का व्यक्ति है, जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जिसकी चिन्ता पूर्व में धूमल सरकार ने की, जिनकी दिहाड़ी को 75/-रुपये से 150/-रुपये हमने पिछले पांच वर्ष में किया था, आज इस बजट में उन मजदूरों के लिए केवल 10/-रुपये की बढ़ौत्तरी की गई है। उधर से महंगाई, बच्चों की शिक्षा की फीस में बढ़ौत्तरी की गई। यह उन गरीबों के साथ एक ज्यादती और अन्याय है। दूसरा जो निम्न स्तर का और सबसे गरीब व्यक्ति इस प्रदेश में है, जिनके साथ मैं समझता हूं कि ईश्वर ने भी ज्यादती की हो, इसमें अपंग, विधवा बहनें और वृद्ध हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा पेन्शन का प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस सरकार ने कभी इस बारे में चिन्ता नहीं की। इस सामाजिक सुरक्षा पेन्शन की चिन्ता जिसने की, वह आदरणीय शांता कुमार जी ने वर्ष 1977-78 में की। उस समय इसको 50/-रुपये से शुरू किया था और जब वर्ष 1990 में शांता कुमार जी दुबारा आए, तो उन्होंने उस जमाने में इसको 50/- से सौ रुपये किया था। वर्ष 1980 से लेकर 1990 तक और वर्ष 1993 से लेकर वर्ष 1998 तक कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस के मुख्य मंत्री रहे, एक पैसे की भी इसमें बढ़ौत्तरी नहीं की गई। लेकिन वर्ष 1998 में आदरणी प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी मुख्य मंत्री बने। इन्होंने इसको सौ रुपये से दो सौ रुपये किया। वर्ष 2003 से वर्ष 2007 तक फिर कांग्रेस के मुख्य मंत्री रहे, लेकिन इन्होंने इसमें एक पैसे की भी बढ़ौत्तरी नहीं की। मैं इसीलिए यह बात कह रहा हूं कि ये लोग प्रदेश के सबसे निम्न और गरीब हैं और इनके बारे में कांग्रेस की सरकारों ने कोई चिन्ता ही नहीं की, इनके बारे में कुछ कहा नहीं। इसके पश्चात वर्ष 2007 में आदरणीय प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी फिर मुख्य मंत्री बने, इन्होंने इसको 200/-रूपये से बढ़ाकर 450/- रुपये किया। मैं समझता हूं कि इस बार वर्तमान मुख्य मंत्री महोदय ने भी इसमें थोड़ी बढ़ौतरी की है----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

23/03/2015/1725/MS/JT/1
श्री गोविन्द राम शर्मा जारी----------

मैं समझता हूं इस बार वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी थोड़ी सी बढ़ोत्तरी की लेकिन ढाई साल में अगर 50 रूपये बढ़ा दिए तो इसे कोई बढ़ोत्तरी नहीं समझता। क्योंकि महंगाई को ध्यान में रखते हुए उस निम्न स्तर के व्यक्ति को, उस गरीब व्यक्ति को 450 रूपये के बजाए 900 या 1000 रूपये करना चाहिए था। लेकिन वह चिन्ता नहीं की गई। इतना ही नहीं आज इस प्रदेश के विकास के लिए जो अधिकारी/कर्मचारी रात-दिन एक कर रहे हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय से जो लाभ दिए जा रहे थे, आदरणीय धूमल जी ने

पंजाब स्केल जब आए उसके बाद जो 4-9-14 का लाभ दिया था, उसको भी वर्तमान सरकार ने विड्रो कर लिया। उसमें मेरा सरकार से निवेदन है कि कर्मचारी हमारे और आपके भाई हैं। ये हमारे परिवार के हैं इसलिए इनकी चिन्ता करना हम सबका कर्त्तव्य बनता है। कर्मचारियों को राजनीतिक आधार पर विकटेमाइज करना, कर्मचारियों को राजनीतिक आधार पर ट्रांसफर करना कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत से कर्मचारियों को राजनीतिक आधार पर वर्तमान सरकार ने इन दो-ढाई सालों में ट्रांसफर किया भी है। इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने यहां रखना चाहता हूं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमैंट में एक श्री विनोद ठाकुर हैं। वह कर्मचारियों के नेता हैं और परिसंघ के अध्यक्ष हैं। उनको बार-बार ट्रांसफर किया जा रहा है। उपाध्यक्ष जी, वह आपके क्षेत्र किन्नौर में पहले भी नौकरी कर चुके हैं। उनको कभी काजा ट्रांसफर कर देते हैं और कभी किन्नौर कर देते हैं। मैं कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं कि कोर्ट से अब उनको स्टे ऑर्डर मिल गए हैं। हम तो सरकार से निवेदन कर सकते हैं कि बदले की भावना से कोई काम न किए जाएं बल्कि सरकार को उनकी चिन्ता करनी चाहिए। कुछ लोग कहते थे कि वर्तमान सरकार कर्मचारी हितैषी है। परन्तु वर्तमान सरकार ने कर्मचारियों का क्या हित किया है? जो कर्मचारियों को ट्रैवल के लिए एल0टी0सी0 मिलता था, वह भी बन्द कर दिया।

अभी डॉ0 बिन्दल जी कर्मचारियों को जो एक्सटैंशन दी, उसके बारे में बता रहे थे। उनमें बहुत से ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनकी एक-डेढ़ वर्ष पहले प्रमोशन होनी थी लेकिन आज तक प्रमोशन नहीं हो पाई। अब उनमें कोई दिसम्बर में रिटायर होने

23/03/2015/1725/MS/JT/2

हैं कोई जनवरी में रिटायर होने हैं। कुछ लोगों को ही इसका लाभ मिला यानी जिनको एक्सटैंशन मिली उनको तो सरकार ने लाभ दे दिया। चलो, अच्छी बात की। लेकिन जिनकी प्रमोशन ड्यु थी, क्या सरकार उनको जिस डेट से वे प्रमोट होने थे उनको बैक डेट से प्रमोट करेंगे? उस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए।

जहां तक कर्मचारियों के स्केल की बात है, बहुत से अधिकारी, पत्रकार मित्र और विधायकगण भी यहां बैठे हुए हैं। ये पंजाब स्केल कब-कब रिवाइज हुए? पहला पे-स्केल वर्ष 1976 में रिवाइज हुआ, फिर 1986 में हुआ, फिर 1996 में हुआ और फिर वर्ष 2006 में हुआ। ये पे-स्केल और इनके एरियर किसने दिए? जो पे-स्केल 1976 में रिवाइज हुआ था, उस समय आदरणीय शांता कुमार जी मुख्य मंत्री थे तो स्केल उन्होंने दिए। जो 1986 में रिवाइज हुए, उसको भी शांता कुमार जी ने 1990 में दिया। जो 1996 में रिवाइज हुए, उनको आदरणीय धूमल जी ने दिया और जो वर्ष 2006 में रिवाइज हुए, उन्हें भी आदरणीय धूमल जी ने ही दिया। तो कर्मचारियों की हितैषी सरकार कौन है यह कर्मचारियों को पता है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

23.3.2015/1730/जेके/जेटी/1
श्री गोविन्द राम शर्माः-------जारी-----

व्याख्यान करने के बजाय कर्मचारियों को हर चीज का पता है। जो दैनिक भोगी कर्मचारी है क्या उसको आप लोगों ने कभी रैगुलर किया? माननीय शांता कुमार जी ने उस समय यह ऑर्डर किये थे कि जो दैनिक भोगी कर्मचारी हैं उनको रैगुलर वर्कचार्ज किया जाए। कांग्रेस ने उन लोगों के लिए कौन सा बेनिफिट दिया? जो बेनिफिट भाजपा ने लोगों को दिये उनको भी छिनने का प्रयास किया गया। दूसरे, हमारे जिला से पक्षपात किया गया। प्रदेश में सभी जिलों में आई.पी.एच. सर्कल है। बिलासपुर , किन्नौर में और अन्य जिलों में भी आई.पी.एच. सर्कल है। हर जगह हैं और काज़ा में भी आई.पी.एच. सर्कल है लेकिन सोलन जिला में आज तक आई.पी.एच. सर्कल नहीं है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि सोलन जिला में आई.पी.एच. सर्कल खोला जाए।

दूसरे, यहां पर विधायक निधि की बात की गई। इसके लिए मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। जो चीज़ अच्छी है उसका धन्यवाद भी करना चाहिए। बजट में 50 लाख से 70 लाख कर दिया लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं हुआ। फायदा इसलिए नहीं हुआ कि आपने बजट में कहा कि लघु सिंचाई योजना के लिए यह पैसा दिया जाता है। मेरा अर्की क्षेत्र ऐसा है जहां पर सूखा ही सूखा है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर लघु सिंचाई योजना हो ही नहीं सकती है। अब उस पैसे को हम कहां पर लगाएं? जैसे आपने पहले 50 लाख रूपया दिया है और उस पैसे को हर जगह खर्च किया जाता है, उसी तरीके से उस बढ़े हुए पैसे को भी खर्च करने के ऑर्डर दिए जाए। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से इस बारे में निवेदन है कि इस ओर जरूर ध्यान दिया जाए। इस राशि को बढ़ाया जाए और कम से कम इसे एक करोड़ रूपये तक किया जाए। यहां श्री संजय रतन जी ने एक बात बहुत अच्छी की कि ऐच्छिक निधि 2 लाख से बढ़ा कर 4 लाख की जाए। मैं भी इसका समर्थन करता हूं कि यह ऐच्छिक निधि बढ़नी चाहिए। दूसरी बात श्री संजय रतन जी

23.3.2015/1730/जेके/जेटी/2
ने और की कि परवाणू से नीचे कुछ और बोलते हैं और उससे ऊपर कुछ और बोलते हैं। श्री संजय रतन जी आप हमारे छोटे भाई हैं। यह तो कांग्रेस का इतिहास है।

परवाणू में आप क्या करते हैं? यह तो पुराना इतिहास है इसका आपको पता होगा कि कब-कब क्या हुआ, कैसे हुआ, चाहे ठाकुर रामलाल जी हों या श्री आन्नद शर्मा जी हों? इन सभी बातों का आपको पता है। यह इतिहास आपका है, हमारा नहीं है। इसलिए हमारे लिए सब बराबर है। हम सभी का मान-सम्मान भी करते हैं। करूणामूलक आधार पर डेढ़ लाख की लिमिट है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जबसे पंजाब स्केल आए उसमें सैलरी बढ़ी है। जो क्लास-IV और क्लास-III है उनकी विधवा के लिए शायद 60 साल तक तो पैंशन ज्यादा मिलती है उसके बाद कम हो जाती है। उनको कम से कम 20 हजार रूपये तक पैंशन मिलती है। अगर 20 हजार रूपये पैंशन महीने की मिलती होगी तो साल की कितनी हो गई। इसलिए कम से कम ढाई लाख तक उसकी लिमिट की जाए। उससे गरीबों के लिए, उन विधवाओं के लिए, उनके बच्चों के लिए नौकरी का प्रावधान हो सकता है। उस परिवार के लिए रोज़ी-रोटी का समाधान हो जाएगा। इसमें मेरा निवेदन है कि सरकार इस ओर जरूर ध्यान दें। कुछ बातें मैं अपने क्षेत्र की यहां पर रखना चाहता हूं। प्लानिंग की मीटिंग में मैंने कहा था कि अर्की में दो बड़े उद्योग हैं इसलिए वहां पर एक ट्रांसपोर्ट नगर बनना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसको माना था। लेकिन दुख इस बात का है कि बार-बार कहने पर जो ततीमा उसका बनना चाहिए था वह अभी तक नहीं बन पाया है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

23.03.2015/1735/SS-JT/1

श्री गोविन्द राम शर्मा क्रमागतः

सीमेंट उद्योग हमारे दाड़लाघाट में अम्बुजा का है। जे0पी0 का मांगल में है। वहां बहुत सारे ट्रक हैं। ट्रक ऑपरेटर हैं। उनके लिए उसका लाभ मिलेगा। केन्द्र सरकार उसके लिए पैसा देगी। यहां से प्रस्ताव जायेंगे तो केन्द्र से एप्रूवल आयेगी। वह माननीय मुख्य मंत्री जी ने माना था। उसके बारे में भी चिन्ता की जाए।

अर्की में पानी की बहुत दिक्कत है। मैं आदरणीय धूमल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। रवि जी, उस टाइम सिंचाई मंत्री थे। मैंने इनसे निवेदन किया और एक 30 करोड़ की बड़ी स्कीम वहां सैंक्शन भी हुई। उसका शिलान्यास भी हो गया और काम भी चल पड़ा। लेकिन वह काम सुस्त है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह काम जल्दी-से-जल्दी पूरा हो ताकि अर्की में जो पानी की दिक्कत है वह दूर हो। और भी

पेयजल योजनाएं हैं जोकि नाबार्ड से एप्रूवड हैं, सैंक्शंड हैं लेकिन उनके काम अभी तक नहीं चले। उनको भी तुरन्त शुरू किया जाए। बाली जी, अभी बाहर चले गए। बसों की बहुत दिक्कत है। भौगोलिक दृष्टि से हमारा अर्की क्षेत्र किन्नौर की तरह है। कम-से-कम 170 किलोमीटर एक कोने से दूसरे कोने तक है। पहाड़ी क्षेत्र है। सड़कों के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि धूमल जी की सरकार में बहुत-सी सड़कें बना दीं। बहुतों के उद्घाटन कर दिए। कई जगह रोड पास करवा दिए। कुछ जो शेष बचा था, वह हमने बाद में पास करवा दिया। बसों की बहुत दिक्कत है। हमने बार-बार मंत्री जी और विभाग से निवेदन किया लेकिन अर्की में बसों का प्रावधान नहीं हुआ। उसका उलटा हुआ। जो धूमल जी ने वहां सब-डिपो दिया था, वह भी कहीं ट्रांसफर कर दिया। स्टाफ और मशीनरी भी कहीं ट्रांसफर कर दी। उलटा काम हो गया। जो लोगों को सुविधा देनी थी, वह नहीं मिली। एक बात और है। मैं तो पेपर के माध्यम से पढ़ पाया। उपाध्यक्ष महोदय, अर्की हमारी तहसील है, वहां पर तहसीलदार और नायब-तहसीलदार की पोस्ट थी। वहां आपके ही क्षेत्र से एक हमारे नायब-तहसीलदार हैं। उस नायब-तहसील की पोस्ट को स्टाफ सहित ही खत्म कर दिया। मेरे को किसी ने बताया कि 12 या 13 पटवार सर्कल हैं इसलिए वह खत्म कर दी। लेकिन ऐसे ही 10, 11, 12 पटवार सर्कल पूरे प्रदेश में हैं जहां पर सब-तहसील भी साथ चली है। नायब-तहसीलदार और स्टाफ भी वहां बैठता है। मैं उनके नाम भी दे दूंगा कि वे कहां-कहां हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि लोगों की ज़रूरतों, भौगोलिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए और अर्की के लोगों की चिन्ता करते हुए वहां

23.03.2015/1735/SS-JT/2

नायब-तहसीलदार की पोस्ट खत्म न की जाए। वहां पर स्टाफ दोबारा लगाया जाए। ऐसा पक्षपात न किया जाए। छोटी-छोटी बात है। पूर्व सरकार के समय अर्की में बॉयज़ स्कूल में साइंस ब्लॉक के लिए धूमल जी से पैसा लिया। पूर्व शिक्षा मंत्री, आदरणीय धीमान जी ने शिलान्यास कर दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि वर्तमान सरकार ने वह पैसा ही कहीं अन्य क्षेत्र के लिए ट्रांसफर कर दिया। पूर्व मंत्री ने शिलान्यास किया। पैसा अन्य क्षेत्र के लिए ट्रांसफर कर दिया। ऐसा पक्षपात क्यों? एक छोटी-सी और बात है। यह तो आपकी मर्जी है कि क्या करना है। लेकिन मैं समझता हूं कि मैं जहां-जहां भी पूर्व मुख्य मंत्री जी के साथ गया, वहां कांग्रेस के जो पूर्व विधायक थे, उनके क्षेत्र में जाकर जब ये उद्घाटन करते थे या शिलान्यास

करते थे तो अपने नाम के साथ कांग्रेस के जो विधायक थे उनका पट्टिका में नाम लिखते थे। लेकिन वर्तमान में हमने वहां भवन बनाया और यहां से एक मंत्री जी गए। मेरे को भी बुलाया तो मैं भी चला गया। जब मैंने वह पट्टिका देखी तो उसमें मंत्री जी ने अपना नाम लिखा और विधायक का नाम नहीं लिखा। मेरे को कोई शौंक नहीं है। लेकिन पैसा भी लगाया, काम भी करवाया, कम-से-कम नाम लिखते तो क्या बुराई थी? ऐसे शायद मुख्य मंत्री मना नहीं करते होंगे। जो स्कूल हमने बनाया, धूमल जी ने 90-95 लाख के करीब पैसा दिया, उसका उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया। हमने स्वागत किया। लेकिन उस स्कूल में उस उद्घाटन प्लेट में विधायक का नाम लिखना तो दूर जो शिलान्यास किया था वह प्लेट भी अभी तक वहां नहीं लगी।

जारी श्रीमती के0एस0

23.03.2015/1740/केएस/जेटी/1

श्री गोविन्द राम शर्मा जारी---

मेरा नाम लिखना तो दूर लेकिन जो शिलान्यास किया था, वह प्लेट भी अभी तक वहां पर नहीं लगी। इसी प्रकार चाहे आई.टी.आई. की बात हो चाहे कुछ और हो, हमारी सरकार के समय में जो काम हुए उनके उद्घाटन तो करे लेकिन जो शिलान्यास हमने किए उनकी प्लेट भी तो लगाओ। बदले की भावना से काम किया जा रहा है और जो शिलान्यास और उद्घाटन हमारी सरकार के समय में हुए थे, ठाकुर गुलाब सिंह जी ने हमारे क्षेत्र में बहुत से उद्घाटन किए थे। वह प्लेंटें तोड़ दी लेकिन सरकार ने आज तक उसके ऊपर कोई ऐक्शन नहीं लिया। प्लेंटें तुड़वाना बुरी बात है । आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी जब मुख्य मंत्री थे, अर्की गए पूर्व मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने वहां पर एक शिलान्यास किया था, उस समय धूमल जी ने मुझे कहा कि गोविन्द जी, साथ में इनकी प्लेट भी लगनी चाहिए क्योंकि शिलान्यास इन्होंने किया था। स्वर्गीय धर्मपाल ठाकुर जी ने फोरैस्ट के रैस्ट हाऊस का शिलान्यास किया था। धूमल जी ने कहा कि उनकी प्लेट भी साथ लगनी चाहिए, हमने लगाई। हमने कहीं पक्षपात नहीं किया, हमने कोई प्लेट नहीं तोड़ी, सरकार हमारी भी थी लेकिन हमने कोई गुंडागर्दी नहीं की।

उपाध्यक्ष जी, उद्योगों के बारे में भी कहना चाहूंगा। उद्योग मंत्री जी का पीछे जवाब आया था कि विभाग में उद्योगपतियों ने रिपोर्ट दे दी है कि 70 प्रतिशत हिमाचली रखे लेकिन जो हिमाचली उद्योगों में रखे हैं उनकी छंटनी की जा रही है। लोग हड़ताल कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उसकी भी चिन्ता सरकार को करनी चाहिए कि कम से कम वहां पर जो

23.03.2015/1740/केएस/जेटी/2

गरीब परिवार के हिमाचली लगे हैं, उनको वहां रैगुलर किया जाए, छोड़ा नहीं जाए बल्कि और हिमाचलियों को भी लगाया जाए। इस पर भी सरकार कोई ऐक्शन ले।

उपाध्यक्ष महोदय, गांव में बहुत से गरीब लोग हैं। उनके लिए आदरणीय शांता कुमार जी ने 1977-78 में पब्लिक टैप लगाए थे। वर्तमान सरकार ने उनको भी डोमैस्टिक कर दिया, उसके भी बिल दिए जा रहे हैं। उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए कि गरीब आदमियों को जो सुविधा दी है, उनको और ज्यादा सुविधा नहीं दे सकते तो उसको स्नैच भी नहीं किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अर्की में एक हॉस्पिटल है। उसमें हमारी सरकार के समय में 11-11 डॉक्टर होते थे लेकिन आज वहां पर केवल एक बी.एम.ओ. और एक डॉक्टर है। रात को अगर दूर से कोई मरीज आए या कोई दुर्घटना हो जाए तो वहां पर उनको देखने वाला कोई नहीं है। फील्ड में जो पी.एच.सी. है वहां के डॉक्टरों को बुला लेते हैं जिससे वहां के लोग ह्रास होते हैं। मैंने आदरणीय मंत्री जी से भी निवेदन किया था। इतना ही नहीं आपकी स्थिति तो यह है कि जो भवन हमारी सरकार ने आदरणीय धूमल जी के आशीर्वाद से बनाए, चाहे वह हैल्थ के हो या अन्य हो, आपके पास उनका उद्घाटन करने का भी समय नहीं है।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

अध्यक्ष महोदय, पी.एच.सी. लोहारघाट को बनकर दो-ढाई साल हो गए है। पी.एच.सी. डुमैहर दो-सवा दो साल से तैयार है। सब सैंटर

23.03.2015/1740/केएस/जेटी/3

बधोखरी दो साल से तैयार है लेकिन आप उनके उद्घाटन तक नहीं कर सकते तो जनता का क्या होगा यह तो ईश्वर ही जाने लेकिन जनता की चिन्ता करने की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है कि इस पर भी ध्यान दिया जाए। मैंने प्लानिंग की मीटिंग में भी कहा था कि नालागढ़ से कुनिहार के लिए जो रोड़ आता है, उसकी

स्थिति बहुत ही दयनीय है। वहां पर पता ही नहीं लगता कि सड़क है, गड्ढे हैं या क्या है। उसके बारे में आज तक किसी ने चिन्ता नहीं की। दो-तीन साल से वहां पर एक पैच भी नहीं लग पाया। मैंने निवेदन किया था कि उसकी दशा को सुधारा जाए लेकिन कुछ नहीं किया गया। मेरा निवेदन है कि उस सड़क की ओर भी ध्यान दिया जाए। वैसे तो सारी की सारी सड़कों की स्थिति खराब है लेकिन उस सड़क पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं धूमल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैंने पूर्व में इनसे निवेदन किया था कि अर्की में पार्किंग की समस्या है, कुनिहार में पार्किंग की समस्या है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

23.3.2015/1745/ag/av/1

श्री गोविन्द राम शर्मा जारी--------

कुनिहार में धूमल जी ने कुछ पैसा दिया था और वहां पार्किंग बन रही है। धूमल जी ने अर्की में पार्किंग के लिए पैसा दिया वह काम भी बार-बार बोलकर और आन्दोलन करके आपने लेट शुरु किया। एक पार्किंग नगर पंचायत की तरफ से 1.17 करोड़ रुपये की बननी थी। उसके लिए माननीय धूमल जी ने उस समय 20-30 लाख रुपये जारी किए थे। केवल वही पैसा आया था और उसके बाद कोई पैसा नहीं आया। अब वह काम भी बंद है और पहले दिया गया पैसा भी बरबाद कर दिया गया क्योंकि वर्तमान सरकार ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा सरकार से निवेदन है कि उसके लिए पैसा देकर वहां पार्किंग की व्यवस्था की जाए।

आदरणीय बाली जी यहां बैठे हैं। पहले आप यहां पर नहीं थे। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। वहां अर्की में बस स्टेण्ड के लिए बहुत जगह है। आप वहां टूर कर लें। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो हम प्राइवेट से भी करवा सकते हैं। आप वहां आकर एक बार चैक कर लें। वहां पर एक बहुत बड़ा बस स्टेण्ड बन सकता है। बस स्टेण्ड बनने से वहां बिजनैस के लिए दुकानें खुलेगी जिससे वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार का साधन मिल सकता है। मुझे विश्वास है कि आप अर्की में बसों की कमी के बारे में जरूर चिन्ता करेंगे क्योंकि वहां बसों की बहुत कमी है। वहां सब-डिपो है, आप उसको डिपो कर दो। अगर वहां बस डिपो होगा तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

अब मैं स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की बात करुंगा। ठाकुर साहब, हमारे यहां अर्की होस्पिटल की बहुत बुरी स्थिति है। आप अभी आए, मैंने इस बारे में पहले भी बोला है। मैंने पिछली बार असैम्बली क्वैशचन किया था। आपने वहां सोलन से दो डॉक्टर डिप्यूट किए थे मगर जैसे ही असैम्बली खत्म हुई वे दोनों डॉक्टर सोलन वापिस चले गए। (---व्यवधान---) वह तो बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने दे दिया। मेरा क्षेत्र है, बहुत-बहुत धन्यवाद। अर्की में वर्तमान में एक बी.एम.ओ. और एक

डॉक्टर है। हमारी सरकार के समय में वहां 11-11 डॉक्टर हुआ करते थे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप वहां पर डॉक्टरों की व्यवस्था करें। वहां सब-सैंटर्ज और पी.एच.सीज. दो-दो सालों से तैयार है। आप वहां पर आकर उद्घाटन करो हम आपका स्वागत करेंगे। ठाकुर साहब, आदरणीय धूमल जी ने एक सी.एच.सी. दाड़लाघाट में दी थी और उसका शिलान्यास भी माननीय धूमल जी ने किया था। अब उसके लिए ढाई साल होने जा रहे हैं, आप कम-से-कम उसका काम तो शुरु करवा दो। (---व्यवधान---) ई.एस.आई. बना दिया। आपने बता दिया, मुझे तो ध्यान ही नहीं था। उसको सी.एच.सी. से ई.एस.आई. बना दिया होगा (---व्यवधान---) भवन वहां नहीं बना, आप उस तरफ भी ध्यान देंगे तो मैं आपका धन्यवादी रहूंगा।

मैं आई.पी.एच. मंत्री जी से भी निवेदन करुंगा। मैं आपसे मिला भी था कि कोटली में एक पेयजल योजना है। उसके बारे में पहले भी आन्दोलन हुआ। जब हमारी सरकार थी तब भी आन्दोलन हुआ था। हमारी सरकार ने उसके टैंडर लगवा कर काम शुरु करवा दिया था। वह टैंडर ढाई साल पहले लगे थे मगर अभी तक उसका कोई काम नहीं हुआ। उसका केवल 30 लाख रुपये का काम है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उस बारे में विभाग को निर्देश दें ताकि वह काम गर्मियों से पहले पूरा हो जाये। वहां पानी की बहुत दिक्कत है इसलिए आप उसके बारे में जरूर चिन्ता करें। एक सिंचाई योजना की बात करुंगा। हमने जितनी भी सिंचाई योजना डाली विभाग ने आज तक उन पर कोई काम नहीं किया। मैक्सिमम तो यही लिख दिया कि 'नोट फीज़िबल'। जहां फीज़िबल है उनकी डी.पी.आर. आज तक नहीं बन पाई। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप उसके लिए भी निर्देश दें कि जहां-जहां पानी या फीज़िबिलिटी है वहां तो वह बने। मुझे विश्वास है कि आप उसको करेंगे।

मैं एक बात और करना चाहता हूं क्योंकि यह पूरे प्रदेश की समस्या है। मैं सभी निर्वाचन क्षेत्रों की बात कर रहा हूं। आपके आई.पी.एच. में फीटर, की-मैन की बहुत कमी है---------

श्री बी.जे.द्वारा जारी

23.3.2015/1750/negi/AG/1
श्री गोविन्द राम शर्मा... जारी...

आपके आई.पी.एच. डिपार्टमैन्ट में फीटर/ की-मैन की बहुत कमी है और सर्वेयर की कमी है। इसपर भी ध्यान दिया जाए। आई.पी.एच. विभाग में ही नहीं बल्कि पी.डब्ल्यू.डी. और इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी यही स्थिति है। शिक्षा विभाग में भी बहुत बुरी स्थिति है। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर तुरन्त ध्यान दिया जाए। मैंने एक और निवेदन करना है, माननीय मुख्य मंत्री जी अपने बजट भाषण में कह रहे थे कि हम जहां 2 बच्चे हैं वहां भी स्कूल खोलेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे खुशी इस बात की भी है कि आदरणीय मोदी जी ने भी घोषणा

की है कि 5 किलोमीटर की डिस्टैंस में स्कूल देंगे। यह बात केन्द्र से भी कहा है। मेरे कुछ स्कूल हैं जो बहुत दूर-दराज़ क्षेत्र में हैं। मैं दो बच्चे वाला तो नहीं बोलूंगा लेकिन जहां बच्चे हैं घडियाल स्कूल जहां बच्चों को 25 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है वहां प्लस टू स्कूल बनना चाहिए। जगूल स्कूल हाई स्कूल बनना चाहिए। कुंअर स्कूल हाईस्कूल बनना चाहिए। शारवा मिडिल स्कूल से हाईस्कूल बनना चाहिए। कोहू हाईस्कूल बनना चाहिए क्योंकि बहुत डिस्टैंस है। बिहुकरी हाईस्कूल बनना चाहिए क्योंकि बहुत डिसटैंस है। जगदाघाट प्लस टू स्कूल बनना चाहिए जहां बहुत डिसटैंस है। जयनगर प्लस टू स्कूल बनना चाहिए क्योंकि बहुत डिसटैंस है। ऐसे ही बैरना में 25 किलोमीटर से दूर से आना पड़ता है, इंटीरियर है वहां पर हाईस्कूल बनना चाहिए बहुत जरूरत है । धूमल जी ने बाघा में एक हाईस्कूल दिया था उसको आपने हाईस्कूल से मिडिल स्कूल कर दिया। मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां पर बहुत दिक्कत है, इंटीरियर पंचायत है उस स्कूल को जो पूर्व सरकार के समय में दी थी उसको फिर से हाईस्कूल कर दिया जाए। ऐसे अनेकों स्कूल वहां पर बनने वाले हैं। वहां पर बहुत सी सी.एच.सी. और पी.एच.सी. की आवश्यकता है, आप उस तरफ ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन बजट दिशाहीन है इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता।

समाप्त

23.3.2015/1750/negi/AG/2

अध्यक्षः अब श्री मन्सा राम जी, माननीय मुख्य संसदीय सचिव, इस चर्चा में भाग लेंगे।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री मन्सा राम)ः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहारें लाएगा यह बजट मुख्य मंत्री जी के परिश्रम में।

अध्यक्ष महोदय, मुझे गौरव है कि 1967 से इस विधान सभा के अन्दर बजट चर्चाओं पर, बजट अनुमानों पर मैंने चर्चा की है और मैं जानता हूं । लेकिन हमें गौरव इस बात का है कि इस बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया एक तो वह तीन घंटे खड़े रहे वह क्या शक्ति है कि इस उम्र में वह 3 घंटे खड़े रहे। मैं तो 3 घंटे खड़ा नहीं हो सकता हालांकि मैं उनसे उम्र में छोटा हूं। लेकिन 3 घंटे खड़े होना,

यह कोई देवीय शक्ति है। यह देवीय शक्ति ही है क्योंकि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के देवी-देवताओं के मन्दिरों का निर्माण किया इसीलिए उनपर इतनी शक्ति है और इस उम्र में वह इतनी देर तक रात को काम करते हैं, इसका हमें गौरव है। ...(व्यवधान).. रात को तो धूमल जी भी नहीं सोते हैं परन्तु आजकल सोते हैं, पहले सोते नही थे। मुझे गौरव है इस बात का। मैं पुरानी बात जानता हूं 1962 में जब धूमल जी उस वक्त कहीं पढ़ रहे थे या साहब बने हुए होंगे, 1962 के अन्दर हिमाचल प्रदेश की जनता ने एक निर्णय लिया राजकुमार श्री वीरभद्र सिंह जी राज परिवार से संबंधित हैं और उनको लोकसभा में लाया और हिमाचल प्रदेश के लिए इन्होंने तब से काम किया है जब वह एम.पी. थे । हमें गौरव है कि वहां पर इनको इंदिरा गांधी जी की सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला । उसके बाद राजीव गांधी जी की सरकार में भी मंत्री बनने का मौका मिला और आखिर में मन मोहन सिंह जी के मंत्रिमण्डल में मंत्री बनने का मौका मिला। आपने नहीं, हिमाचल की जनता ने इनको 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री के लिए भारी बहुमत से जिताया। ...(व्यवधान).. आप अपना काम करते हैं और आप जो कर रहे हैं वह आपका अपना काम है। क्योंकि जब

23.3.2015/1750/negi/AG/3

आप इधर आएंगे तो आप भी हमारी तरह बोलेंगे, ऐसा चलता है। लेकिन यह ठीक है कि इतना बड़ा राजनीतिक जीवन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुख्य मंत्री जी को चाहे...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

23.03.2015/1755/यूके /1
मुख्य संसदीय सचिव, श्री मंसा राम ---जारी ----

भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुख्य मंत्री ने चाहे वह श्री शांता कुमार जी हैं, बुरा कोई नहीं है लेकिन लोगों ने उनको वोट नहीं दिए और वे इतनी बार मुख्य मंत्री नहीं रहे । हमें इस बात का गौरव है कि उनको हिमाचल प्रदेश के लोगों ने, और अब भी मैं आपको कहता हूं, जिस टाईप की उनको शक्ति आयी है, उनके ऊपर देवी-देवताओं का आशीर्वाद है, तो आप तड़पते रह जाएंगे और वे 7वीं बार फिर से मुख्य मंत्री बनेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि यह जो बजट है, यह इतना अच्छा बना है और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने गागर में सागर को भरा है । कोई

वर्ग इसमें अछूता नहीं रहा । कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसके बारे में चर्चा नहीं है । कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसको कुछ दिया नहीं हो । यानि हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों को जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं उनको तथा हिमाचल प्रदेश की सभी जनता को मालोमाल करने वाला बजट है । अध्यक्ष महोदय, हम समझते हैं उनकी आयु बढ़े और उनका भविष्य उज्जवल हो । वैसे मैने तो पहले ही बोल दिया है आपको (विपक्ष) कि आप तड़पते रह जाएंगे और ये फिर से 7वीं बार मुख्य मंत्री बनेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यही कहना है कि मेरे क्षेत्र में कुछ समस्याएं हैं जिन पर मैं बोलना चाहूंगा और माननीय मुख्य मंत्री जी कोशिश करेंगे कि इनका समाधान हो । मुझे तत्तापानी तीर्थ के बारे मे बात करनी है । तत्ता पानी तीर्थ परशु राम जी की तपस्या से वहां पानी के स्त्रोत फूटे और जो हमारे करसोग के गरीब लोग, और सारे हिमाचल प्रदेश के गरीब लोग

23.03.2015/1755/यूके /2

वहां पर अस्थि विसर्जन करने जाते थे क्योंकि लोग गरीब थे, उनके पास पैसा नहीं होता था जिस कारण से वे लोग हरिद्वार नहीं जा सकते थे और जो हरिद्वार नहीं जा सकते थे, वे वहां पर अस्थियां बहाते थे । अब तो लोग हरिद्वार चले जाते हैं । लेकिन उस वक्त बड़ी मुश्किल थी । अध्यक्ष महोदय, उस तीर्थ-स्थान को खत्म कर दिया गया है, उसका सागर बन गया है । उसमें लोक निर्माण विभाग का बहुत सुन्दर रैस्ट हाऊस था, वह खत्म हो गया । वहां पर टूरिज़म का काम्पलैक्स था, बॉथरूम थे, वह भी सारे डूबे, खत्म हुए। वहां पर एक हाई स्कूल था, उसमें 15 बीघा जमीन थी, उनकी जमीने बह गयी, कोल डैम के लोगों ने उनको कोई पैसा नहीं दिया । सरकार को कोई पैसा नहीं मिला । किसी को यदि मिला है तो उसके लिए धन्यवाद । लेकिन हिमाचल सरकार का जो नुकसान हुआ है, मैं आदरणीय मुख्य मंत्री से कहूंगा क्योंकि ये धार्मिक व्यक्ति हैं, ये तत्ता पानी की तरफ ध्यान दें और कोशिश करें कि वहां पर पर्यटन विभाग का जो होटल था, बॉथरूम थे, उनको ऊपर लाया जाए और वहां के गर्म पानी के स्त्रोतों को जो वहां पर प्राईवेट होटल बने हैं, उनमें उस पानी को लाया जाए । वहां पर गरम पानी के स्त्रोत हैं उसको ज्योलॉजिकल डिपार्टमेंट के सहयोग से कर उस पानी ऊपर लाया जाए और जो पुराना होटल डा0 वाई0एस0 परमार के वक्त में बना था उसको दोबारा जीवित किया जाए, यह मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा । मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि वहां पर झील के बनने से, वह झील

बिल्कुल गांव के साथ आ गयी है, उसकी भी सुरक्षा की जाए । झील के चारों तरफ कोई ऐसा इन्तजाम किया जाए

23.03.2015/1755/यूके /3

जिससे कोई छोटे बच्चे या पशु उसमें न गिरें । जो प्रोजेक्ट बनते हैं उसमें उनको बड़ा पैसा मिलता है और जो कोल डैम प्रोजेक्ट बनेगा उनको भी बड़ा पैसा मिलेगा, उससे वहां के लोगों की सेवा भी की जाए । मैं यही निवेदन करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से तत्तापानी के साथ-साथ करसोग क्षेत्र की सड़कों के बारे में भी प्रार्थना करना चाहता हूं क्योंकि मेरे यहां डढौर से तत्तापानी तक एक सड़क जो एन0एच0 है, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने मदद की है, उसके ऊपर काम शुरू हुआ है । मैं समझता हूं कि उस काम की गति को और तेज किया जाए । मुझे बड़ा गौरव है कि शिमला से तत्तापानी तक एन0एच0 बन रहा है । उसके साथ उसको जोड़ दिया गया है । करसोग क्षेत्र को भी एन0एच0 के साथ जोड़ा जाए । मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि यदि उधर से नहीं जुड़ सकता तो कोटलू की तरफ से भी जोड़ा जा सकता है क्योंकि आनी और रामपुर को एन0एच0 से जोड़ा जा रहा है । तो करसोग को भी किसी भी तरफ से कहीं से चाहे मंडी से, चाहे शिमला से चाहे रामपुर से इस क्षेत्र को एन0एच0 के साथ जोड़ा जाए ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से अपने क्षेत्र के कुछ पुलों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं कि एक खड्ड सरौर उसमें बीगण नाला से एक पुल भलाण के लिए स्वीकृत है, उसमें सारी आबादी गुज्जरों और ओ0बी0सी0 की हैं, वहां पर गुज्जर लोग रहते हैं । उस पुल में बच्चे भी डूब जाते हैं ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

23.03.2015/1800/sls-ag-1
श्री मनसा राम (माननीय मुख्य संसदीय सचिव)...जारी
बच्चे भी डूबते हैं और पशु भी डूबते हैं। मुझे सरकार से प्रार्थना करनी है कि इस पुल की तरफ भी ध्यान दिया जाए।

मेरी सात-आठ सड़कें हैं - तत्तापानी परलोग वाया बिंदला सड़क, महौटा बगशाड़ वाया तलैहण सड़क, बगशाड़-शावंगी-कुण्ड-बेस्टा सड़क, माहूनाग सरतौला सड़क, करसोग-परलोग सड़क, सराहन से हरिपुर आनी कॉलेज सड़क, करसोग से काण्डा सड़क और माहूनाग से बगशाड़ सड़क। इनका निर्माण एफ.सी.ए. के कारण फंसा है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इन्हें क्लीयर किया जाए। इनमें पैसा है। कोई नाबार्ड की सड़कें हैं तो कोई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें हैं। एफ.सी.ए. के कारण इनमें आगे काम बंद हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, सारे करसोग क्षेत्र में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां कम बिजली है और लाईट डिम रहती है। इसलिए 33 के.वी.ए. के पॉवर स्टेशन लगाकर उस डिम लाईट को इंप्रूव किया जाए। वहां पर जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको रात को पढ़ने में मुश्किल आती है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस लाईट में सुधार किया जाए। करसोग क्षेत्र में यह बड़ी समस्या है।

अध्यक्ष महोदय, एक इमला-बिमला खड्ड है। मैंने उसकी चैनेलाईजेशन के लिए भी सरकार से प्रार्थना की है। मुझे आशा है कि वह कार्य हो जाएगा। ...(व्यवधान)...क्या अपनी समस्याओं का भी ज़िक्र न करें। सी.पी.एस. नहीं बोल सकते हैं लेकिन एम.एल.ए. के नाते तो बोल सकते हैं। ...(व्यवधान)...जैसे बैल होते हैं, जिनके मुंह बंद होते हैं, वह बोल तो सकते नहीं। हम न तो सवालों के जवाब दे सकते हैं, न ही प्रश्न कर सकते हैं। आप हमें यहां तो बोलने दो, विधायक का काम तो करने दो। लोगों ने विधायक बनाया है, इसलिए मैंने अपनी बात रखनी है। उससे आपको क्या तकलीफ़ है? मैं सरकार की ख़िलाफ़त नहीं कर रहा हूं और न आपकी

23.03.2015/1800/sls-ag-2

कर रहा हूं। आपका भी मुझे सबका पता है। मैं एक-एक आदमी को जानता हूं।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : आप अपनी चर्चा पर केंद्रित होकर बोलते रहिए।

श्री मनसा राम (माननीय मुख्य संसदीय सचिव) : अध्यक्ष महोदय, मैं इमला-बिमला खड्ड की चैनेलाईजेशन के लिए भी सरकार से प्रार्थना करूंगा। चैरा से माहूनाग उठाऊ पेयजल योजना के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं

कि उन्होंने इसके लिए 13.50 करोड़ रुपये दिए हैं और वह शुरू हो रही है। उसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। इन दो सालों में उन्होंने मुझे 9 हाई स्कूल, पांच 10+2 स्कूल, 2 मिडल स्कूल और 2 प्राईमरी स्कूल दिए जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। उन्होंने करसोग की तरफ बहुत ध्यान दिया है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक विकास का प्रश्न है, मुझे इस बात का गौरव है और मेरे पास मुख्य मंत्री जी को बधाई देने के लिए शब्द नहीं हैं जिनसे उनको बधाई दूं कि उन्होंने करसोग क्षेत्र के लिए, जो कि शिमला से 110 किलोमीटर और मण्डी से 122 किलोमीटर पर स्थित है, डिपो दिया। उस डिपो से वहां लोग बहुत खुश हुए हैं। वह इसका उद्घाटन करेंगे जिसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और आप सभी को इस बात की भी बधाई देता हूं कि इस बजट के बाद हिमाचल प्रदेश में विकास की गति तेज़ होगी; लोग आगे बढ़ेंगे। यह बजट इतना लंबा है जिसकी मैं चर्चा नहीं कर सकता। काफी लोगों ने चर्चा की भी है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि ऐसा बजट मैंने 1967 के बाद पहली बार देखा है। मैं इतना आपको बता सकता हूं। मैंने कई मुख्य मंत्रियों के साथ काम किया हुआ है। मैं धूमल जी को भी जानता हूं क्योंकि मैं उनके मंत्रिमण्डल में भी रहा हूं। मैं सिर्फ़ शांता कुमार जी के मंत्रिमण्डल में नहीं रहा अन्यथा हिमाचल प्रदेश के जितने मुख्य मंत्री हुए हैं, मैं उनके मंत्रिमण्डल में रहा हूं। इसलिए मैं सभी

23.03.2015/1800/sls-ag-3

पार्टियों का काम जानता हूं। कोई मुझे ऐसे ही नहीं कह सकता क्योंकि मैं सब-कुछ जानता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत आभारी हूं। उनका बहुत-बहुत धन्यवादी हूं क्योंकि मेरे क्षेत्र की ओर उनका ध्यान गया है।

जयहिंद, जय हिमाचल।

अगले वक्ता ..श्री गर्ग जी के पास

अध्यक्ष : अब श्री बलदेव सिंह तोमर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बलदेव सिंह तोमर : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 18 मार्च, 2015 को माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो बजट भाषण प्रस्तुत किया गया उसमें प्रदेश के हित में कुछ भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश की जनता को मात्र गुमराह किया गया है। यह बजट किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और कर्मचारी विरोधी बजट है।

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें सड़कों की बात कही गई है। सड़कें वास्तव में ही हमारी भाग्य रेखाएं होती हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक मात्र सड़क जोकि माननीय धूमल जी की सरकार जब प्रदेश में थी उस समय नेशनल हाईवे घोषित हुई थी। उसकी आज भी बहुत खराब हालत है। काफी मेहनत के बाद, लगातार दिल्ली जाकर मैं तीन बार माननीय केन्द्रीय मंत्री जी से मिला, उसके पश्चात उसके लिए बजट आया, टैण्डर्ज भी हो गए, लेकिन पिछले डेढ़ साल से सड़क की हालत बहुत खराब है। जिस ठेकेदार को काम मिला है अभी तक उस ठेकेदार ने मात्र 10 प्रतिशत ही काम किया है। उस सड़क पर चलना बहुत मुश्किल है। मैंने कई बार प्रश्न के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष यहां यह मांग रखी है, लेकिन सड़क की हालत अभी भी ज्यों-की-त्यों बनी है। इसके अतिरिक्त मेरे विधान सभा क्षेत्र की दर्जनों सड़कें पिछले दस साल से बन रही हैं। लेकिन अभी तक भी वे सड़कें पास नहीं हुई हैं। कई बार कहने के बाद भी विभाग कोई सुनवाई नहीं करता है।

अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में जो इस समय यहां माननीय मंत्री जी बैठे हैं, उन सबसे एक निवेदन है कि अपने दौरे उन क्षेत्रों में बनाएं जैसा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि पिछले दो वर्षों में कोई भी मंत्री मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में आए हों। कम-से-कम वहां आकर वहां की हालत भी देखें कि ऐसे-ऐसे क्षेत्र भी अभी इस प्रदेश में हैं जिनकी हालत बहुत खराब है।

अध्यक्ष महोदय, यहां कहा गया कि हम प्रदेश को इण्डस्ट्रीयल हब बनाना चाहते हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र के साथ लगता हुआ पांवटा साहिब विधान सभा चुनाव क्षेत्र

है। वहां बहुत सारे उद्योग लगे। लेकिन पिछले एक वर्ष के अंदर 60 उद्योगों ने अपने बिजली के कनैक्शन कटवा दिए। क्या कारण है कि उद्योग यहां से जा रहे हैं? वे अपने बिजली के कनैक्शन कट करवाकर दूसरे प्रदेशों में वे चले गए। क्योंकि हमारे प्रदेश में जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए थीं वे उन्हें नहीं मिल रही हैं। यहां पर माननीय विधायक श्री संजय रतन जी ने कहा कि क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता

23/03/2015/1805/RG/AG/2

पार्टी की सरकार है इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी दिल्ली जाकर उनसे बात करनी चाहिए और आर्थिक पैकेज लाना चाहिए। लेकिन मैं भाई संजय जी को बताना चाहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, हमारे प्रदेश के मंत्री लोग गुलदस्ते लेकर लगातार दिल्ली जा रहे हैं, फोटो खिचवा रहे हैं। तो क्या वहां पर ये खाली फॉर्मेलिटी के लिए जा रहे हैं या वहां जाकर कोई बात भी करते हैं?

अध्यक्ष महोदय, माननीय धूमल जी ने पिछले सत्र में यहां पर कहा था कि यदि हमारी आवश्यकता होगी तो हम दिल्ली चलने के लिए तैयार हैं। आप लोग यदि विपक्ष से सहयोग मागेंगे, तो माननीय धूमल जी के नेतृत्व में हमारा विपक्षी दल भी प्रदेश हित के लिए जरूर जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, यहां इस बजट में बिजली की बात कही गई कि एल.ई.डी. के तीन-तीन बल्ब सभी को 10/- रुपये की किश्तों में दिए जाएंगे। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिजली के बल्ब देकर क्या करेंगे जब बिजली ही नहीं होगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिजली की यह हालत है कि अगर एक बार ट्रांसफॉरमर खराब हो जाए, तो 15-15 दिन तक वह ट्रांसफॉर्मर ठीक होकर नहीं आता। अगर कोई पोल गिर जाए, तो उसको बदलवाने के लिए 3-3 महीने लग जाते हैं। तारें घरों के ऊपर हैं, लोगों ने लकड़ी के खंबे लगाकर अपने घरों के ऊपर तार लगाई हुई हैं जिसका हमेशा खतरा बना रहता है। हम कई बार अधिकारियों को कहते हैं और कई बार लिखकर नोट दिए गए हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसका कारण है कि जिस प्रकार प्रदेश के मंत्री लोग उस क्षेत्र में नहीं जाते, उसी तरह अधिकारी लोग भी हमारे क्षेत्र में नहीं जाते। यह बड़े दुःख का विषय है।

अध्यक्ष महोदय, मनरेगा की बात यहां पर आई। जिस तरह हमारा क्षेत्र है----
--जारी

एम.एस. द्वारा जारी

23/03/2015/1810/MS/JT/1

श्री बलदेव सिंह तोमर जारी----------

दूसरे यहां पर मनरेगा की बात आई। जैसा माननीय धूमल जी ने भी कहा, मनरेगा में जिस तरह के हमारे क्षेत्र हैं, उनमें मटीरियल में कैरिज बहुत पड़ता है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जिस तरह के हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां पर किराया बहुत लगता है, वहां पर आप मटीरियल के लिए उसकी कुछ रेशो/परसेंटेज बढ़ा दीजिए ताकि वहां पर मनरेगा के तहत जो कार्य हो रहे हैं, वे आसानी से हो सकें।

बेरोजगारों के लिए लगातार दो साल से स्किल डवलपमैंट के नाम पर रोजगार की बात की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में लगभग साढ़े ग्यारह लाख बेरोजगार हैं। हमारा क्षेत्र पौंटा औद्योगिक क्षेत्र है। वहां पर बहुत सारे नौजवानों को रोजगार मिल रहा है लेकिन जिस हिसाब से रोजगार मिलना चाहिए, वैसे नहीं मिल रहा है। पिछले दिनों हमारे यहां रोजगार मेला नाहन में रखा गया। पूरे आपके नेता लोग जिनको जनता ने नकार दिया, वे वहां पर अपनी फोटोज खिंचवा रहे थे। वे वहां पर गए और उन्होंने पूरे जिले के नौजवानों को वहां इकट्ठा किया। बेरोजगार नौजवान वहां यह सोचकर चले गए कि शायद हमें नौकरी मिल जाए लेकिन वहां नौकरियां हमारे जिले के नौजवानों को क्या मिली, मात्र मजदूर की 5000/-रूपये की नौकरी उनको मिली। जिन लड़कों ने बी.टैक, एम. टैक, बी. फार्मा और एम. फार्मा किया हुआ था, उनको रोजगार नहीं मिला या जो लड़के और अच्छे पढ़े हुए थे उनको कोई रोजगार नहीं मिला। क्योंकि ऊपर के पदों पर बाहरी प्रदेश के लोग लगते हैं। उद्योग मंत्री जी सदन में बैठे नहीं है। मेरा उनसे निवेदन है कि वह वहां जाएं या किसी को भेजें और जाकर देखें कि 70 प्रतिशत किन लोगों को वहां रोजगार मिला है। सिरमौर के नौजवानों को ठेकेदारी प्रथा के तहत ठेकेदारों के पास रखा गया है और उनका शोषण किया जा रहा है।

अध्यक्ष जी, अवैध खनन के बारे में आज सुबह मेरा यहां प्रश्न भी लगा था। हमारे विधान सभा क्षेत्र में रोजगार का साधन मात्र खनन है लेकिन बहुत सारी

माइन्स बन्द हैं। जैसा यहां कहा गया कि माइन्स 13 महीने चल रही हैं। तो 13 महीने तो लीगल रूप से चल रही हैं लेकिन जो अवैध खनन हो रहा है जिससे हमारी

23/03/2015/1810/MS/JT/2

सड़कों को नुकसान हो रहा है उन सड़कों की हालत, जैसे मैंने यहां कहा कि कांटी-मसवा सड़क, नेशनल हाइवे 72 वी सड़क, सकोली सड़क और पुड़वा सड़क। उस सड़क पर इतना अवैध खनन हो रहा है कि दिन में 50 और 100 ट्रक यानी दिन-रात वहां यह काम चला हुआ है। वहां जे0सी0बी0 मशीने लगी हुई हैं। मैं उस समय इस प्रश्न के उत्तर पर जो जवाब मिला, संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने माननीय मंत्री जी को कहा कि आप उस पर पूछे कि छः महीने से एफ0आई0आर0 क्यों नहीं हुई? कौन अधिकारी उसके लिए जिम्मेवार है? आपको पता है कि वहां कोई रास्ता भागने का नहीं है मात्र एक सड़क है। आप वहां नाका नहीं लगा सकते, पुलिस नहीं भेज सकते तो जो आपके वहां माइनिंग इन्स्पैक्टर बैठे हैं वे क्या करते हैं? उनको किसका संरक्षण प्राप्त है? इस बात की जरूर चिन्ता करें।

दूसरा माननीय धूमल जी ने भी कहा कि नशे के ऊपर आज बहुत चिन्ता करने की आवश्यकता है। मेरे यहां सतौन पत्थर की एक बहुत बड़ी मण्डी है। वहां पर पत्थर का स्टॉक होता है और बहुत दूर-दूर से वहां पर काम करने के लिए कारोबारी लोग आते हैं और काफी सारे मजदूर भी बाहर से हैं। वहां नशे का बहुत कारोबार है और हमारे वहां के नौजवान लड़के नशे के कारोबार में लगे हैं। वे नशा ले रहे हैं। पिछले दिनों लगातार वहां दो-तीन नौजवान लड़कों की मौतें हुई हैं। जब मैं वहां पर शोक व्यक्त करने गया तो उनकी माताओं ने मुझसे सिर्फ एक बात कही कि आप भले ही क्षेत्र का विकास रहने दीजिए लेकिन हमारे बच्चों की जिन्दगी बचाइये और इस नशे को खत्म कीजिए। इसलिए इस पर कोई न कोई नीति बननी चाहिए। जहां पर हमारी चाय या पान की दुकानें हैं, वहां पर यह सब कारोबार होता है। इस तरह के कारोबार इन छोटी-छोटी दुकानों के अन्दर होते हैं। तो कोई न कोई सरकार इस तरह की नीति बनाएं ताकि वहां जाकर इस चीज को रोका जाए।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट बुक में बहुत सी बातें आई हैं। मंत्री जी सदन से बाहर चले गए हैं। गिरीपार क्षेत्र जो हमारा आता है वह बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है और स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा समस्या उस क्षेत्र में है। वहां बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती हैं। आप

सब लोग अखबारों में पढ़ते रहते होंगे। वहां पर बहुत सारी छोटी गाड़ियां और बसें वगैरह दुर्घटनाग्रस्त होती रहती हैं और बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं। लेकिन

23/03/2015/1810/MS/JT/3

वहां पर अस्पताल नाममात्र का है। जब माननीय धूमल जी की सरकार प्रदेश में थी तो शिलाई में एक सी0एच0सी0 खोली गई थी। वहां पर पूरा स्टाफ था। छः-सात डॉक्टर्ज थे । सरकार बदलते ही सभी डॉक्टर्ज के तबादले कर दिए गए और आज वहां मात्र दो डॉक्टर हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा--------

23.3.2015/1815/जेके/जेटी/1
श्री बलदेव सिंह तोमरः---------जारी----

आज वहां मात्र दो डॉक्टर हैं। एक छुट्टी पर जाता है और एक वहां पर रहता है। लगभग 300-400 की ओ0पी0डी0 वहां पर है। जितने भी प्राइमरी हैल्थ सब सेन्टर्ज हैं, जैसे रोनालट है,पखोटा है, क्यारीगुणा है और सतौन है वहां पर एक-एक डॉक्टर है। उन डॉक्टरों का रेजिडैंस पौंटा साहिब में है। आधे दिन डियुटी पर जाते हैं और आधे दिन रहते ही नहीं है। ऐसी परिस्थितियों हमारे क्षेत्र में है। इस विषय में भी माननीय मंत्री जी गौर करें।

शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी बातें कही गई कि वहां पर स्टॉफ जा रहा है। डॉ0 बिन्दल जी ने यहां पर कहा कि कितने पद यहां पर खाली हैं। मात्र 7000 रिक्त पदों में से 2000 पद भरे गये और बाकी सब खाली हैं। बहुत अच्छी बात है कि एस.एम.सी. से भर्तियां की जा रही है। लेकिन वह भर्तियां किस प्रकार की हो रही है, उस विषय कि हमें चिन्ता करनी चाहिए? जो लड़का/लड़की 80 या 90 प्रतिशत नम्बर लेकर पास हुए हैं और बेरोजगार है उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। नौकरी किसको दी जा रही जिसके 50 या 60 परसेंट नम्बर है? ये उन नौज़वानों के साथ धोखा है, उन नौज़वानों के साथ छलावा किया जा रहा है। कस्तुरबा गांधी होस्टल लड़कियों का शिलाई में है, उसमें एक वॉर्डन लगनी थी। पूरे प्रदेश से इन्टरव्यू देने के लिए लड़कियां आई। उसका इन्टरव्यु एस.डी.एम. ने लेना था। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने शिलाई में एस.डी.एम. का ऑफिस खोला और मैंने उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद किया। वहां पर एस.डी.एम. मात्र एक महीने बैठा और बाद में

वे वहां से चले गए। आज तक वहां पर एस.डी.एम. नहीं है और तहसीलदार वहां पर काम कर रहा है। तहसीलदार उस इन्टरव्यू में बैठे। उन्होंने इन्टरव्यू लिया और अच्छा इन्टरव्यू लिया। उन्होंने पारदर्शिता रखने का प्रयास किया कि जिसके नम्बर ज्यादा होंगे उसको रख लिया जाएगा। एक लड़की के 4 नम्बर ज्यादा थे। 10 नम्बर का वायवा था। रिजल्ट बन कर तैयार हो गया। जब रिजल्ट बन रहा था तो अधिकारियों ने अपने

23.3.2015/1815/जेके/जेटी/2

फोन बन्द किए हुए थे। वे अधिकारीगण चाहते थे कि जो सही डीज़र्व करता है उसको रोजगार मिले। रिजल्ट बनने के बाद किसी को वहां पर फोन लेकर भेजा गया। पता नहीं किसका फोन आया? तहसीलदार को डराया गया कि आपके ऑर्डर अभी चम्बा के लिए कर दिये जाएंगे। इस रिजल्ट को बदलिए। तहसीलदार ने डर के मारे वह रिजल्ट चेंज कर दिया। जिस लड़की को 4 नम्बर आ गए थे उसको मात्र वायवा में 3 नम्बर दिये गये और जो लड़की 5-6 नम्बर पीछे थी उसको 8 नम्बर दिये गये और उसको सलैक्ट कर दिया गया। इस तरह का सिस्टम हमारे प्रदेश में बन गया है। यह उन नौज़वानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। उनके माँ-बाप मेहनत-मज़दूरी करके उनको पढ़ा रहे हैं। वे बेचारे मेहनत करके अच्छे नम्बर ले रहे हैं लेकिन इस तरह के कारणों से वे पीछे रह रहे हैं। इस विषय पर भी हमें गौर करना चाहिए। हमारे क्षेत्र में एक विषय यह भी चला है। एक कॉलेज हमारे शिलाई में है। मैंने प्लानिंग की बैठक में मांग रखी कि एक कॉलेज हमारे क्षेत्र में और होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। दूर-दराज़ से बच्चे आते हैं। पखोटा में सर्वे हुआ और उसके लिए पखोटा डिजर्व भी करता था। सर्वे होने के बाद वहां से रिपोर्ट आ गई कि जमीन दे दी गई है लेकिन पता नहीं कि सरकार की क्या मंशा थी दोबारा से एक चिट्ठी निकाली गई कि ठीक उससे 10 किलोमीटर के बाद वहां पर सर्वे किया जाए। वहां पर भी सर्वे की टीम चली गई। वहां पर क्षेत्रवाद फैल गया। दोनों तरफ नारेबाजियां होने लगी। एक क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि यहां पर कॉलेज होना चाहिए और दूसरी तरफ के लोग कह रहे हैं कि यहां पर कॉलेज होना चाहिए। आखिर हम किस तरह की राजनीति इस प्रदेश में करना चाहते हैं? केवल हम क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह की राजनीति से दूर हट कर सरकार यह

निश्चित करे कि कॉलेज कहां पर खोला जाए? हम चाहते हैं कि कॉलेज उस क्षेत्र में खोले जो क्षेत्र डीजर्व करता है और क्षेत्रवाद की राजनीति से हमें बचना चाहिए।

23.3.2015/1815/जेके/जेटी/3

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अभी यहां से चले गए। माननीय धूमल जी ने वर्ष 2000 में शामलात भूमि जो सरकार ने अपने कब्जे में ले रखी थी, माननीय धूमल जी के आर्शीवाद से हमें वह भूमि वर्ष 2000 में वापिस मिली। हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन आज तक कुछ क्षेत्रों में तो भूमि वापिस हो गई है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर माइनिंग का एरिया है उसमें आज तक तकसीम नहीं हो रही है ताकि वह वापिस मालिकों को न मिल सके। इतने सालों से तकसीम क्यों नहीं हो रही है?

श्री एस.एस. द्वारा---

23.03.2015/1820/SS-AG/1
श्री बलदेव सिंह तोमर क्रमागतः

बहुत सारी पंचायतों की अभी भी तकसीम करने को रही है। वह तकसीम हो जाए ताकि मालिकों को जमीन वापिस मिल जाए क्योंकि उसमें माइनिंग वालों को यह फायदा होता है कि उनको एन0ओ0सी0 की ज़रूरत नहीं पड़ती, मात्र एक एन0ओ0सी0 ग्राम सभा से ली, प्रधान को सैट करके ले ली और उसके बाद उनका काम चल जाता है। इसमें भी तुरन्त कार्रवाई की जाए ताकि तकसीम हो जाए और वहां पर जो इस तरह की धांधली चली हुई है वह भी खत्म हो जाए।

विधायक निधि के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 20 लाख रुपये बढ़ाए, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद है। सभी ने कहा है कि जो इस पर कंडीशन लगाई है उसको हटाया जाए तभी विकास के कार्य आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा उसको एक करोड़ रुपये करने की आवश्यकता है क्योंकि विकास के लिए 70 लाख रुपये हमारे जैसे दुर्गम क्षेत्रों में बहुत कम हैं। इसलिए उसको बढ़ाया जाए। उसके साथ-साथ उसकी गाइडलाइन्ज़ में भी परिवर्तन किया जाए। जैसे पहाड़ में सरगांव में रास्ते जाते हैं रास्ते गिर जाते हैं तो वहां दीवार लगती है लेकिन दीवार लगाने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है। उसमें डंगे के लिए विशेष प्रावधान किया जाए। साथ में जो कोई हमारा पहले का भवन बना है, वह गिर चुका है

या टूट रहा है, कोई सड़क बंद हो गई है, उसकी रिपेयर या मैंटीनेंस के लिए कोई प्रावधान नहीं है। उसमें वह प्रावधान भी किया जाए ताकि रिपेयर या मैंटीनेंस के लिए पैसा दे सकें।

एच्छिक निधि जो पिछले साल दो लाख रुपये की थी, भाई गोविन्द जी और रतन जी ने कहा कि उसको 4 लाख रुपये किया जाए। फिलहाल 4 लाख और अगले साल 5 लाख रुपये हो जाए, उससे भी फायदा होगा।

पिछले दिनों मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गांव शमां पड़ता है उसको अनसेफ घोषित किया गया। उसमें नीचे पानी का रिसाव होने से वह गांव बैठ रहा था। उसमें बहुत सारी दरारें आ गईं। उस समय उनको दूसरी जगह शिफ्ट भी किया गया। सरकार ने यहां पर जवाब दिया। विधान सभा के अंदर मैंने प्रश्न पूछा तो माइनिंग मंत्री जी ने कहा कि उनके लिए पांवटा साहब में जमीन दी जा रही है। मैं परसों उस गांव में गया था और अभी फिर बरसात आने वाली है तो फिर और मुश्किल हो

23.03.2015/1820/SS-AG/2

जायेगी। दो साल बीत गए हैं लेकिन अभी तक उनको जमीन नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई? उनको एक बार पांवटा साहब में जमीन दिखाई भी गई लेकिन उनको अभी तक जमीन नहीं मिली है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उनको तुरन्त जमीन दी जाए। इसलिए और भी बहुत सारी समस्याएं क्षेत्र में हैं। पूरे प्रदेश में हैं। इस बजट के अंदर कोई ऐसी विशेष बात नहीं है कि मैं इस बजट का समर्थन करूं तो मैं इस बजट का समर्थन नहीं करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः आदरणीय धूमल जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, आज अत्यन्त महत्वपूर्ण दिवस है। शहीद-ए-आजम भगत सिंह जी का शहादती दिवस है। अच्छा होगा कि सारा सदन आपके नेतृत्व में एक प्रस्ताव उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करते हुए पास करे क्योंकि उन शहीदों के

कारण ही हमें आज़ादी मिली है। वह रिकॉर्ड में भी आ जायेगा और आपकी वाहवाही हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हिमाचल विधान सभा देश के महान् शहीद शहीद-ए-आजम भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि भेंट करती है और उनके सहयोगी राजगुरू और सुखदेव जी को भी श्रद्धांजलि भेंट करती है और उनके सम्मान में उन्हें नमन करती है।

अध्यक्षः शहरी विकास मंत्री जी, आप क्या बोलना चाहेंगे?

शहरी विकास मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आज शहीद भगत सिंह जी का जो शहादत दिवस है और उनके साथ उनके साथी राजगुरू और सुखदेव जी, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहूति दी..

जारी श्रीमती के0एस0

23.03.2015/1825/केएस/जेटी/1
शहरी विकास मंत्री जारी---

प्राणों की आहूति दी, उसके ऊपर जो आज यहां पर पक्ष और विपक्ष की तरफ से प्रस्ताव आया है, मैं उसमें यह कहना चाहूंगा कि आज अगर हमारा देश आजाद है तो इस प्रकार की जो कुर्बानियां उस समय के नौजवानों ने दी है, उसके कारण हम आज आजाद है और हमारे देश में प्रजातंत्र स्थापित है। मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं।

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया और भाई सुधीर जी ने पक्ष की ओर से उसका समर्थन किया। मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि क्रान्तिकारी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन किया, अपनी जान को हथैली पर ले करके पूरे भारत में बंगाल से ले कर पंजाब तक क्रान्ति की एक लौ जलाई और इंगलैंड में बैठकर जिसको शुरू किया वह चाहे काले पानी से ले करके फांसी के तख्तों तक हो, उनके लिए आज यह माननीय सदन नमन करता है और मैं भी उसमें अपने आप को शामिल करता हूं।

अध्यक्षः तो जो यह प्रस्ताव पेश हुआ, दोनों तरफ से यह स्वीकृत भी हुआ कि शहीदेआज़म भगतसिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव को यह सदन नमन करें और श्रद्धांजलि दें । यह दोनों तरफ से स्वीकृत है तो यह प्रस्ताव पास हुआ।

हमारे जो ऐसे क्रान्तिकारी, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपनी ज़िन्दगी में कुछ नहीं देखा, जवानी में ही वे देश के लिए लड़े, उनके लिए सारा देश और हम सभी नमन भी करते हैं और उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। इसके साथ ही यह प्रस्ताव पास हुआ।

अब इस माननीय सदन की बैठक मंगलवार 24 मार्च, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

दिनांकः 23 मार्च, 2015 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
शिमला-171004 **सचिव।**